● किसकी शह पर ? ● बढ़ रहा है भारत ● मजाक नहीं नस्लीय अपमान

मदर इंडिया

हिन्दी मासिक, मूल्य 50 रुपये

प्रकाशन के 26वें वर्ष में

10 नवम्बर - 9 दिसंबर 2026



शुभ: लाभ:

वैभव लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, धन लक्ष्मी की जय हो!



दुनिया के **हीरो**

अवैध निर्माण
अतिक्रमण
प्रदूषण
डी.सी के लिए
चुनौती



वर्दी की शान !



REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWS PAPER
FOR INDIA UNDER NO. DELHIN-1999/2008

SHREYA

FURNISHING

Unit of Nirmals

Happy
Diwali

The only trusted establishment in Delhi for Furnishing & Sofa Fabrics

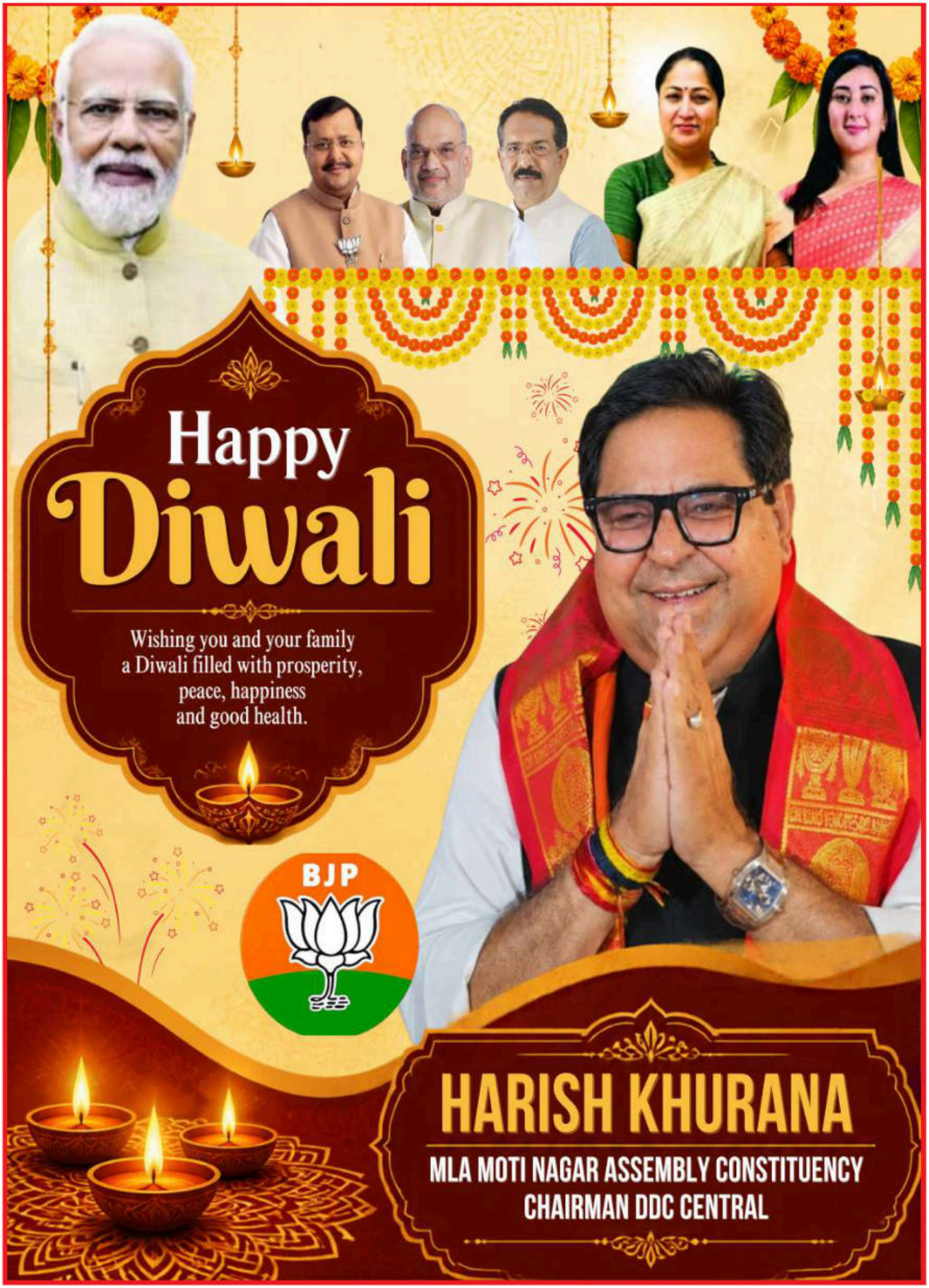
We have clothes available here at reasonable rates.

Curtains • Sofa Fabrics • Cushions • Carpets



1/88, W.H.S. Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi - 15

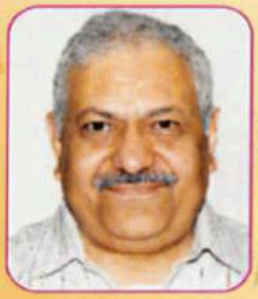
Tel: 41722097, 9871 016 727


Happy
Diwali
Wishing you and your family
a Diwali filled with prosperity,
peace, happiness
and good health.
BJP
HARISH KHURANA
MLA MOTI NAGAR ASSEMBLY CONSTITUENCY
CHAIRMAN DDC CENTRAL

Wish You A Very

Happy Diwali

With Best Compliments From



Arun Berry
Proprietor
M 9312251951



Abhishek Berry
Proprietor
M 8826989998

BERRY ART PRESS

A Well Known Name in the Service of Printing Industry Since 1948

Solution In Packaging

A-9, Mayapuri Indl. Area, Phase-1, New Delhi-11064

Ph.: 011-41016041 • Telefax: 41016041

Email: berry_press@yahoo.com

Happy Bhaiya Dooj • Happy Guru Purab • Happy Chhath

इस माह

मदर इंडिया

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष :26 अंक : 12 10 नवंबर 2026

संरक्षक

श्रीमती वीणा देवी

सम्पादक

ललित 'सुमन'

समाचार सम्पादक

पुष्पा झा

मुख्य संवाददाता

आशीर्वाद भारतीय

दिल्ली प्रतिनिधि

बालाजी

बिहार ब्यूरो

प्रवीण 'बब्लू'

झारखंड ब्यूरो

किरण चौधरी

उत्तर प्रदेश ब्यूरो

रोहित

राजस्थान ब्यूरो

कुमार संजय

उड़ीसा ब्यूरो

अभिषेक

उत्तराखंड ब्यूरो

विनोद खंडूरी

ग्राफिक्स टीम

बादल

आराधना उपाध्याय

प्रसार व विज्ञापन

जीवछ झा

कानूनी सलाहकार

एल. एस. सैनी (अधिवक्ता)

अमित कुमार

सर्वाधिक सुरक्षित 'मदर इंडिया' में प्रकाशित सभी सामग्रियों से सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। सभी मामलों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

5–10 दुनिया के हीरो.....



स्मित मच्छार की तारीफ जहां पूरी दुनिया कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश विरोधी ताकतों की आँख में वह कांटा बने हुए हैं। कोरोनाकाल के बाद भारतीयों के खिलाफ जिस तरह का जहर बोने का काम किया गया, कप्तान स्मित की बहादुरी ने उसकी काट का काम किया। स्मित की बहादुरी से प्रभावित यूएई के शासक शेख "अल नाहयान"ने न केवल उनका सम्मान व सराहना की बल्कि मुलाकात के दौरान् गले से भी लगा लिया।

14–20 अपराध पर सख्ती बरकरार



दिल्ली पुलिस पर देश की राजधानी की सुरक्षा के साथ-साथ करोड़ों नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है।ऐसी परिस्थितियों में पुलिस नेतृत्व के लिए प्रशासनिक अनुभव, दूरदर्शिता, अनुशासन, त्वरित निर्णय क्षमता और जनता के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस के वर्तमान आयुक्त अनुराग कुमार ने 17 जुलाई को अपना कार्यभार संभाला।

22-23 किसकी शह पर ?



चावड़ी बाजार इलाके में 2 व्यक्तियों की मौत के बाद ए.ई. , जे.ई. निलंबित किए गए। सीएम गृह मंत्री के साथ खुद आईं। मेयर से लेकर पार्षद ने अवैध निर्माण की भर्त्सना की। लेकिन इस घटना से जागना तो दूर, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र कीर्ति नगर डब्लू.एच.एस में धड़ल्ले से अवैध निर्माण न केवल बन रहे हैं, बल्कि उन्हें संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जनता का सीधा सवाल है कि लगातार हादसों के बावजूद गहरे बेसमेंट के साथ कैसे 6 मंजिला अवैध निर्माण कैसे ?

34 निजता भी जरूरी , पारदर्शिता भी

डीएनपीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने कहा कि यदि समाचार के विषय बने व्यक्ति को ही डाटा के इस्तेमाल पर "ऐसा" नियंत्रण मिल जाए जिससे वह रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सके तो पत्रकारिता का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 17 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है।



48-49 चाय पर चर्चा.....



व्यापार जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले आर.एस. चौहान को लोग सम्मानपूर्वक 'चौहान साहब' के नाम से पुकारते हैं। उनका व्यक्तित्व उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं अधिक व्यापक है। मृदुभाषी स्वभाव, सहयोग की भावना, उदार हृदय और सादगीपूर्ण जीवनशैली उनकी पहचान बन चुकी है।

खत आपके 2

सम्पादकीय 3

कही - सुनी 4

आशियाने पर चली जेसीबी.....12

विधायक खुराना ने किया निरीक्षण..31

बढ़ रहा है भारत 40

मजाक नहीं नस्लीय अपमान 36

कीर्ति नगर टिंबर मार्केट 51

रॉयल कोस पोलो कप (खेल) 52

व्यंग्य 55

राशिफल 56

प्रधान कार्यालय

जे–61 ए, रमेश नगर

नई दिल्ली – 110015

web : www.motherindiamagazine.com

web: www.dainikindiadarpan.com

Web : didnews.in, rashtrapratham.com

मो. : 9910886465, 9210050718

editorindiadarpan@gmail.com

E-mail : dainik.indiadarpan@yahoo.in

फिर जहरीली हुई हवा

नवंबर की शुरुआत होते ही दिल्ली की हवा फिर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। 2 नवंबर को आईटीओ पर एक्यूआई 349 दर्ज हुआ और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू करना पड़ा। सरकार ने से विंटर एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें दफ्तरों में आधी उपस्थिति जैसे कदम शामिल हैं। ये कदम जरूरी हैं, लेकिन हर साल दोहराई जाने वाली यह कहानी आखिर कब सुलझेगी। सरकार को सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाना, पराली का स्थायी विकल्प देना और धूल पर सख्त नियंत्रण करना ही होगा।

नरेश चंद्र शर्मा
पीतमपुरा, दिल्ली

आंध्र पर दोहरी मार

चक्रवात 'अर्नब' के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने 3 नवंबर की सुबह प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास दस्तक दे दी। तेज हवाओं और भारी बारिश से 30 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान, कपास और मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा है।

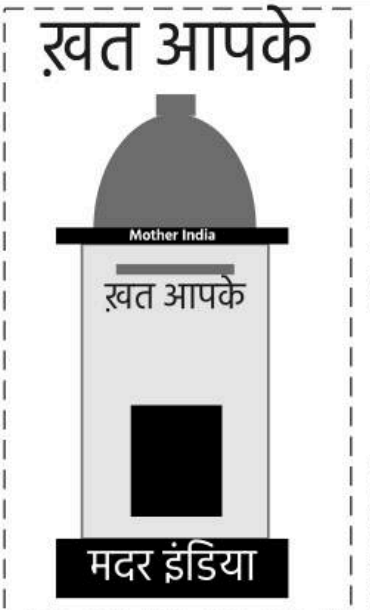
समय रहते लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाना और एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती सराहनीय है। अब सरकार की प्राथमिकता किसानों को जल्द मुआवजा और बीमा दावों का तेज निपटारा होनी चाहिए। लगातार आ रहे चक्रवात यह भी बताते हैं कि तटीय इलाकों में मजबूत तटबंध और बेहतर जल निकासी अब विलासिता नहीं, जरूरत है।

वेंकटेश्वर राव
हैदराबाद

बैंक पर भरोसा न टूटे

ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से ग्राहकों के बचत खातों और एफडी से पैसे गायब होने के आरोपों ने आम आदमी को चिंता में डाल दिया। ग्राहकों के अनुमान के मुताबिक यह रकम करीब 35 करोड़ रुपये है। यह नई बात नहीं है, पूर्व में ठगों और जालसाजों द्वारा ग्राहकों को चूना लगा कर पैसे निकाले गए। एक बैंक में तो वरिष्ठ ने ही करोड़ों का गबन एक बार-बाला के लिए कर लिया। ऐसे तत्वों पर जल्द कार्रवाई की जाए, साथ ही ग्राहकों को भी चाहिए कि वे एसएमएस अलर्ट चालू रखें और समय-समय पर अपनी पासबुक व एफडी की जांच करते रहें।

अनीता चौधरी
नोएडा



दीपावली का पर्व और सामाजिक सद्भाव

दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। इन दिनों में श्रद्धालु प्रथम पूज्य गणेश, मां लक्ष्मी और अन्य देवों के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व हमें अंधकार पर रौशनी की जीत का संदेश देता है।आइए, इस दीपावली को श्रद्धा, सद्भाव और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाएं।

रोशनी सिंह
गोरखपुर

बचपन लौटाइए

कुछ ही समय में बाल दिवस है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। बच्चे उनके प्रिय थे और वे जानते थे की बच्चे देश का भविष्य हैं। आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि बच्चों का बचपन मोबाइल और टीवी की स्क्रीन में सिमटता जा रहा है। मैदान खाली पड़े हैं और बच्चे घंटों ऑनलाइन गेम व रील्स में डूबे रहते हैं, जिसका असर उनकी आंखों, नींद, पढ़ाई और व्यवहार पर पड़ रहा है। माता-पिता को खुद उदाहरण बनना होगा और घर में स्क्रीन का समय तय करना होगा। बाल दिवस का सबसे अच्छा उपहार बच्चों को उनका खुला बचपन लौटाना है।

सुधा मिश्रा
लखनऊ

मिट्टी के दीयों वाली दीपावली

इस बार दीपावली 8 नवंबर को है और त्योहार से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है। ऐसे में पटाखों से दूरी बनाना सबकी सेहत के हित में है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों के लिए। मेरा सुझाव है कि इस बार हम मिट्टी के दीये और स्थानीय कारीगरों का बना सामान खरीदें। इससे कुम्हारों और छोटे कारीगरों के घर भी रोशन होंगे। रोशनी का पर्व तभी सार्थक है, जब उसमें किसी का दम न घुटे।

मीनाक्षी अग्रवाल
जयपुर

लौह पुरुष की विरासत

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। आजादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में शामिल कराना उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम था। गुजरात के एकता नगर में खड़ी 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके इसी योगदान की याद दिलाती है। लेकिन सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि केवल प्रतिमाओं और कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की एकता को मजबूत करने से होगी।

किशोर भाई पटेल
अहमदाबाद

न्यूजीलैंड में भारत की परीक्षा

न्यूजीलैंड दौरे पर टी-20 सीरीज 3-2 से जीतकर भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की। पांच टी-20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों वाला यह दौरा न्यूजीलैंड में किसी भी मेहमान पुरुष टीम के साथ अब तक की सबसे बड़ी द्विपक्षीय सीरीज है। लेकिन असली परीक्षा टेस्ट मैचों में होगी। 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था। 2019-20 के बाद भारत पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट खेलेगा। उम्मीद है कि टीम इस बार उस हार का हिसाब बराबर करेगी।

अमनदीप सिंह
लुधियाना

पाठकों से

मदर इंडिया का यह अंक आपको कैसा लगा लिखें। अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें।

संपादक
मदर इंडिया
जे-61ए, रमेश नगर,
नई दिल्ली-15

Web: www.motherindiamagazine.com



शांति से क्यों बैठें ?



ललित 'सुमन'

भ्रष्टाचार भारत के लिए ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को कौन रोकेगा। आज यही चिंता के साथ , चिंतन का भी मुद्दा है। एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं , जिसमें यह सामने आया है कि विगत 15 से 20 वर्ष पूर्व जिसके पास मुश्किल से कुछ लाखों में रुपये थे आज उसके पास 100 से 500 करोड़ की चल-अचल प्रॉपर्टी है। इन 15 से 20 वर्षों में उसके पास यह अकूत संपत्ति ईमानदारी व मेहनत से आ गई, ऐसी बात नहीं है। साफ है यह संपत्ति निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से काला धन भ्रष्टाचारी ने अर्जित किया है।भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी ने यह अकूत संपत्ति बगैर राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण के अर्जित कर लिया, यह भी गले के नीचे नहीं उतरता। निश्चित रूप से इस अकूत संपत्ति को अर्जित करने के लिए कानून व संविधान का बार-बार उल्लंघन किया होगा। कानून व संविधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो राजनेता हो व्यापारी हो, उद्योगपति हो या अन्य किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो , उस मगरमच्छ के खिलाफ कानून और संविधान हाथ डालने की हिम्मत तब तक नहीं जुटा पाते, जब तक वह मीडिया की सुर्खियों में नहीं या जाता। मदर इंडिया इस राष्ट्र के निर्माता से यह जानना चाहता है कि क्या सच में भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी को बेनकाब करने वाले देशभक्तों की रक्षा करने की हिम्मत हमारी व्यवस्था के पास है? जब कोई ईमानदार व देशभक्त हिन्दुस्तानी चाहे वह किसी पद पर हो , वह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, कानून की रक्षा करने का प्रयास करता है, कानून की रक्षा करने का हौसला रखता है । तो कैसे, और क्यों उसे रास्ते से हटा दिया जाता है ? क्या देश को यह बताने का काम हमारे राष्ट्र निर्माता करेंगे कि अब तक कितने देशभक्तों को ईमानदारी की बलि-वेदी पर चढ़ाया जा चुका है ? और देशभक्तों के कितने कातिलों को अब तक गद्दार घोषित कर उन्हें दंडित किया गया है ? देश का सैनिक, पहाड़ों और जंगलों में अपने परिवार से दूर, देश की सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने में देर नहीं करता । लेकिन, उसके शहीद होने के बाद उसके बूढ़े अभिभावक, विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे उसी देश में अपने को असुरक्षित पाते हैं । जिस देश की सीमा की रक्षा के लिए उसके बेटे , पति , बाप ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। एक ईमानदार आईए एस , आईपीएस , न्यायाधीश , पत्रकार, व्यापारी , उद्योगपति, के पास मुश्किल से दो व्यक्त की रोटी , बाबा आदम जमाने की कार, पुश्तैनी मकान के साथ-साथ तिनका-तिनका जोड़ लाखों रुपये की पूंजी मुश्किल से भविष्य के लिए जुट पाती है (जो आज के फास्ट पेमेंट युग में सुरक्षित भी नहीं हैं।)। वहीं भ्रष्टाचारी चंद ही वर्षों में कई आलीशान गाड़ी, नए नए मोडेल की गाड़ियाँ , हजारों करोड़ों की संपत्ति बना समाज में सम्मानित होते हैं । क्योंकि वे खुलकर अपने आकाओं पर धन लुटाते हैं , उन्हें अच्छे-अच्छे 'गिफ्ट' देकर पद भी प्राप्त कर लेते हैं। वहीं कर्तव्यनिष्ठ को कहीं किनारे बैठा दिया जाता है , कि, वेतन लो और 'शांति' से बैठो। अगर पद पर भ्रष्टाचारी विराजमान हो और उससे कानून और न्याय के पालन की उम्मीद की जाए ! यह आप सोच भी कैसे सकते हैं ! भारत की राजधानी दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे लोग हैं जो कल तक टेम्पो चलाते थे , आज करोड़ों-करोड़ के मालिक हैं । कुछ का परिवार तो अपराध में संलग्न था। लेकिन , आज वह परिवार कई करोड़ का मालिक बना घूम रहा है । ऐसे अनेकों उदाहरण हैं , जो भ्रष्टाचार का सहारा लेकर आगे बढ़े और समाज व राष्ट्र को सफेदपोश बनकर गुमराह करने का काम कर रहा है । आज भी ईमानदार, कानून के रखवाले, न्यायप्रिय राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी , व्यापारी , उद्योगपति व पत्रकार हैं , उनकी संख्या भ्रष्टाचारियों से अधिक है। लेकिन, वे सभी, असंगठित हैं, जबकी भ्रष्टाचारी, भू-माफिया , देश द्रोही संगठित हैं और दीमक की तरह राष्ट्र को चाट रहे हैं । इन माफ़ियाओं से अगर राष्ट्र को बचाना है, तो ईमानदारों को संगठित होकर इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और सरकार को ईमानदारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ दीपावली, धनतेरस, नरक चतुदर्शी, भाई दूज, छठ पूजा और गुरू नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनायें।

आपका

ललित सुमन

सत्यमेव जयते

मनुष्य अगर सिर्फ इंसान बन जाए तो वह समाज, राष्ट्र में स्वत: आदरणीय हो जाएगा। इंसान बनने की मशीन बाज़ार में नहीं मिलती, आत्ममंथन से ही मनुष्य इंसान बन सकता है। जो सत्य लिखने से डरते हैं वह मृत के समान है।

-ललित 'सुमन'

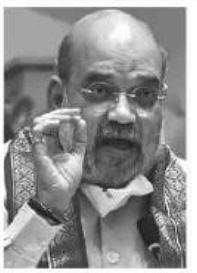


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में नाशिक में आयोजित हुई गोदावरी आरती का विहंगम दृश्य



किसी भी स्थल पर हर समय कब्जा नहीं किया जा सकता। ऐसा हुआ तो किसान, पत्रकार और बाकी लोग कहां जाएंगे? विरोध का अधिकार सभी को है, इसलिए तय स्थल के लिए तय समय और तय अवधि दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट



देश की जनता एसआईआर की खिलाफत की आड़ में घुसपैठियों को बचाने की राहुल गांधी की रणनीति को पूरी तरह समझ चुकी है। राज्यों में मिल रही लगातार हार से राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए।

केंद्रीय गृहमंत्री
अमित शाह



भारत ने 2025 में ही अपनी आधी स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर पेरिस समझौते का लक्ष्य पांच साल पहले पूरा कर लिया। अब हमारा लक्ष्य अगले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट नई गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ने का है।

भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी



चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं, यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी



भारत किसी को उकसाता नहीं, लेकिन उकसाए जाने पर दृढ़ता से जवाब देता है। हमारी रक्षा तैयारियां बढ़ी हैं। आज जब भारत बोलता है, तो दुनिया ध्यान से सुनती है।

रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह



लोग तरह-तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमारा पहला काम मतदाता सूची को सही कराना है। अगर हम मतदाता सूची ठीक नहीं करा पाए, तो यह लड़ाई नहीं जीत सकते। 26 नवंबर, संविधान दिवस पर हम पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष
अखिलेश यादव

भारतीय क्यों नहीं हो सकते दुनिया के हीरो ?





फ्लाई दुबई की उड़ान में हुई गंभीर कॉकपिट घटना ने जहां विमानन सुरक्षा, पायलटों की जांच और आतंकवादी मंसूबों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं इस घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक फर्जी बीबीसी रिपोर्ट ने उससे भी बड़ी चुनौती सामने रखी है-' सच और झूठ के बीच अंतर करने की चुनौती'/स्मित मच्छार की तारीफ जहां एक ओर पूरी दुनिया कर रही है , वहीं दूसरी ओर देशविरोधी , विदेशों ताकतों की आँख का कांटा वह बने हुए हैं/ आखिरकार कोरोना काल के बाद से भारत और भारतीयों के खिलाफ़ जहर जो बोया गया , इस एक वाकये ने उसकी काट करने का बेहतरीन काम किया है/

● मदर इंडिया डेस्क

विमानन क्षेत्र में सुरक्षा केवल आधुनिक तकनीक, कड़े नियमों और प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संकट के क्षणों में सूझबूझ, साहस और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर और फ्लाईदुबई के चालक दल के सदस्यों को सम्मानित किया जाना इसी मानवीय साहस और कर्तव्यनिष्ठा की पहचान है। 30 सितंबर को कॉकपिट में हुई एक गंभीर घटना के दौरान घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर ने जिस तरह कॉकपिट का दरवाजा खोला, उससे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और संभावित त्रासदी को टालने में मदद मिली। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा प्रथम श्रेणी जायद द्वितीय पदक प्रदान किया जाना इस साहसिक प्रयास की आधिकारिक मान्यता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि **विमान में सवार सैकड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पायलट और चालक दल के सदस्य केवल अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, बल्कि हर उड़ान में अनेक लोगों के जीवन की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में उनका काम यात्रियों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाना होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में यही जिम्मेदारी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकती है।** ऐसे समय में लिया गया एक निर्णय, दिखाई गई तत्परता और उठाया गया जोखिम अनेक परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। इस सम्मान का महत्व केवल एक भारतीय पायलट की व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय विमानन समुदाय के लिए भी एक संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के प्रति समर्पण और संकट के समय दिखाई गई जिम्मेदारी को राष्ट्रीय सीमाओं से परे पहचान मिलनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात का यह कदम उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थिति में अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सम्मान 27 अक्टूबर 2026 को प्रदान किया गया और दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने चालक दल के सदस्यों को पदक प्रदान किए। हालांकि, इस घटना को केवल व्यक्तिगत बहादुरी की कहानी मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं होगा। विमानन सुरक्षा की दृष्टि से यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि कॉकपिट के भीतर ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। कॉकपिट विमान का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है, जहां पायलटों के बीच समन्वय, अनुशासन और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि कॉकपिट के भीतर ही किसी अप्रत्याशित घटना से विमान और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, तो उसका प्रभाव विमान में सवार लोगों तक सीमित नहीं रहता। इससे पूरी विमानन व्यवस्था की सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता सामने आती है। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि सह-पायलट ने भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर हमला किया, जिसके बाद विमान कुछ ही क्षणों में हजारों फीट नीचे चला गया और यात्रियों तथा चालक दल के हस्तक्षेप से उसे नियंत्रित किया गया। विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। बाद में संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि सह-पायलट ने योजनाबद्ध तरीके से कॉकपिट में आपातकालीन कुल्हाड़ी से कप्तान पर हमला किया और विमान के नियंत्रण पर कब्जा करने का प्रयास किया; उन्होंने इसे एक आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने का प्रयास बताया। भारतीय कप्तान स्मित मच्छार की भूमिका को लेकर उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टें जो तस्वीर पेश करती हैं, उसे सोशल मीडिया पर फैलाए गए डीपफेक ने उलटने का प्रयास किया। विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार मच्छार पर हमला हुआ था और गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे दूसरे चालक दल के सदस्यों और यात्रियों को तक पहुंचने तथा स्थिति को



कप्तान स्मित को गले लगाते हुए यूएई के शासक ने कहा, "ठीक हो जाएँ, आपको लड़ना मैं सिखाऊँगा।""

कब क्या हुआ ?

- **30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मच्छार परउनके सह-पायलट हमाम अल-हमामी ने कथित तौर पर आपातकालीन कुल्हाड़ी से हमला किया।**
- **UAE अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कैप्टन को घायल कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की।**
- **गंभीर रूप से घायल होने और कई बार बेहोश होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास जारी रखा, ताकि बाहर मौजूद चालक दल और यात्री उनकी मदद कर सकें।**
- **कॉकपिट का दरवाजा खुलने के बाद चालक दल, यात्रियों और अन्य पायलटों ने मिलकर हमलावर को काबू किया। अन्य पायलटों ने विमान का नियंत्रण संभाला।**
- **विमान को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घायल कैप्टन को अस्पताल में भर्ती कराया गया।**

नियंत्रित करने का अवसर मिला। भारतीय और इजरायली नेतृत्व ने उनके साहस की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। रॉयटर्स और अन्य विश्वसनीय माध्यमों ने उन्हें उस संकट के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाला पायलट बताया है।इसके विपरीत, **सोशल मीडिया पर वायरल कथित बीबीसी वीडियो ने एक काल्पनिक भारतीय नागरिक "राघव मेनन" को पूरी घटना का आरोपी बताने की कोशिश की और बिना किसी प्रमाण के उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ तथा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जोड़ दिया। यहीं से यह पूरा प्रकरण केवल विमान सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सूचना सुरक्षा का मामला भी बन जाता है। किसी हिंसक घटना के बाद लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया तत्काल जानकारी हासिल करने की होती है। भय, जिज्ञासा और अनिश्चितता का यह मिश्रण सोशल मीडिया के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है।** जैसे ही कोई वीडियो सामने आता है, लोग उसके स्रोत, समय और संदर्भ की जांच किए बिना उसे आगे बढ़ाने लगते हैं। किसी प्रतिष्ठित समाचार संस्थान के लोगो, परिचित समाचार प्रस्तोता की तस्वीर और पेशेवर शैली का उपयोग उस सामग्री को अतिरिक्त विश्वसनीयता देता है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में इन संकेतों का भरोसा भी कमजोर हो चुका है। किसी प्रसिद्ध एंकर का चेहरा और आवाज अब इस बात का प्रमाण नहीं रह गए हैं कि उसने वास्तव में वही बात कही है जो वीडियो में सुनाई दे रही है। फ्लाईदुबई प्रकरण में सामने आया कथित बीबीसी वीडियो इस खतरे का लगभग पाठ्यपुस्तक जैसा उदाहरण है। **फ्रांस 24 की जांच के अनुसार वीडियो में बीबीसी की प्रस्तोता सैली बंडॉक के पुराने वास्तविक फुटेज का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर कृत्रिम आवाज तथा नए कैप्शन जोड़कर पूरी तरह अलग कहानी बनाई गई। जांच में इस्तेमाल किए गए मेवर डीपफेक डिटेक्टर ने इस सामग्री के कृत्रिम रूप से बनाए जाने की 99 प्रतिशत संभावना बताई।** वीडियो में इस्तेमाल दृश्य संकेत, समाचार ग्राफिक्स, मुंह की असामान्य गतिविधियां और कृत्रिम आवाज भी सामग्री की वास्तविकता पर सवाल खड़े करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल बीबीसी फुटेज घटना से एक दिन पहले किसी बिल्कुल अलग विषय पर प्रसारित हुआ था। यानी एक वास्तविक समाचार संस्थान के वास्तविक वीडियो को उठाकर उसमें झूठी सामग्री जोड़ दी गई और उसे नई खबर के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। यह तकनीक इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह पूरी तरह काल्पनिक सामग्री और वास्तविक सामग्री के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। **पुरानी तस्वीर वास्तविक हो सकती है, समाचार प्रस्तोता वास्तविक हो सकता है, विमान का वीडियो भी वास्तविक हो सकता है, यात्रियों की आवाजें भी वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन इन सभी वास्तविक टुकड़ों को गलत संदर्भ में जोड़ देने से जो कहानी बनती है, वह पूरी तरह झूठी हो सकती है। इस मामले में भी एक विमान के वीडियो को इस तरह प्रस्तुत किया गया जैसे वह उसी समय और उसी स्थान पर रिकॉर्ड हुआ हो जब उड़ान संकट में थी। फ्रांस 24 की जांच में पाया गया कि संबंधित दृश्य दुबई के आकाश का था और पृष्ठभूमि में हयात रीजेंसी की पहचान योग्य संरचना दिखाई देती है, जबकि विमान घटना के दौरान सऊदी अरब के ऊपर था और बाद में तबुक में उतरा।** इस प्रकार वीडियो का वास्तविक होना और घटना से उसका संबंधित होना दो अलग-अलग प्रश्न साबित हुए। इसके साथ ही यात्रियों की घबराहट और चीखों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी पुनः इस्तेमाल किया गया। खुले स्रोतों के आधार पर की गई जांच में यह पाया गया कि आवाजें किसी पुराने वीडियो से ली गई थीं, जिसमें विमान में अशांति का दृश्य था। उसे नए वीडियो के साथ जोड़कर ऐसा वातावरण तैयार किया गया मानो वह वास्तविक फ्लाईदुबई घटना की रिकॉर्डिंग हो। यह दुष्प्रचार की उस नई पद्धति को दिखाता है जिसमें झूठ पैदा करने के लिए जरूरी नहीं कि

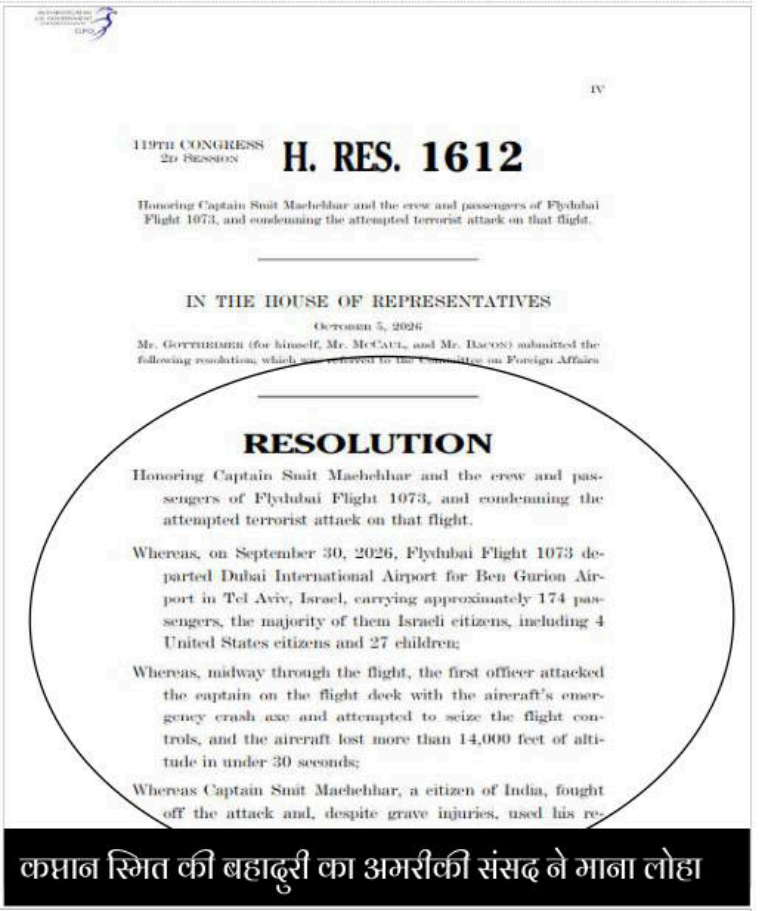
- **आरोपी की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हमामी के रूप में हुई। संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने मामले की जांच के आदेश दिए और इसे आतंकवादी हमले के प्रयास के रूप में जांचा जाने लगा।**
- **आरोपी विमान को इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल से टकराना चाहता था। जांच में उसके पूर्व के इजरायल दौरों और कथित कट्टरपंथी विचारों की जानकारी भी सामने आई।**
- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में कैप्टन स्मित से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनके साहस की सराहना की। भारतीय दूतावास ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और सहायता उपलब्ध कराई।**
- **अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 5 अक्टूबर को कैप्टन स्मित, फ्लाईदुबई के चालक दल और यात्रियों के साहस को सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनके साहस की सराहना की।**
- **संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कैप्टन स्मित मच्छार और फ्लाईदुबई के चालक दल को उनके साहस और यात्रियों की जान बचाने के प्रयासों के लिए " फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय " से सम्मानित किया।**

पुरस्कार समारोह के दौरान अमीरात के राष्ट्रपति/शासक शेख मुहम्मद "अल नाहयान" और कैप्टन मच्छार के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट का ध्यान खींचा। एक वीडियो में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को अल नाहयान के शामिल होने से पहले क्रू मेंबर्स से बातचीत करते हुए दिखाया गया। "आप कब ठीक होंगे?" शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने स्मित के हाथ के स्लिंग को देखते हुए पूछा। वीडियो में कैप्टन स्मित कहते हुए देखे गए, "शायद दो महीने।" शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने कहा, "तो मेरे पास एक आइडिया है। जब आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं आपके साथ एक सेशन करना चाहता हूं ताकि आपको लड़ना सिखाया जा सके।" "यह मेरे लिए सम्मान की बात है, महाराज," स्मित ने अमीरात के राष्ट्रपति को गले लगाते हुए कहा।

सब कुछ नया बनाया जाए। पुराने वास्तविक स्रोतों को तोड़-मरोड़कर, अलग-अलग संदर्भों को जोड़कर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उनके बीच झूठी कड़ी बनाकर कहीं अधिक प्रभावी भ्रम पैदा किया जा सकता है। इस पूरे मामले का एक और गंभीर पक्ष भारत को जानबूझकर कहानी के केंद्र में खड़ा करना है। सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी रिपोर्ट में न केवल एक काल्पनिक भारतीय यात्री का नाम उछाला गया, बल्कि यह आरोप भी जोड़ा गया कि कुछ भारतीय नागरिकों ने मोसाद से मुलाकात की और एक कथित पूर्व रॉ अधिकारी को विमान के अपहरण की साजिश में शामिल किया। इस तरह की कहानियां केवल फर्जी खबर नहीं होतीं; वे विशेष राजनीतिक और भू-राजनीतिक अर्थ पैदा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। जब किसी अपराध को राष्ट्रीयता, खुफिया एजेंसियों और किसी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष से जोड़ा जाता है, तो पाठक को तथ्यों की बजाय एक तैयार निष्कर्ष दिया जाता है। वहां से भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना आसान हो जाता है।**भारत के संदर्भ में ऐसे दुष्प्रचार का प्रभाव और भी व्यापक हो सकता है। किसी भारतीय नागरिक पर बिना प्रमाण गंभीर अपराध का आरोप लगाने से उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी आघात हो सकता है। यदि किसी विदेशी दर्शक को केवल वायरल वीडियो के आधार पर यह विश्वास हो जाए कि एक भारतीय किसी विमान हमले की साजिश में शामिल था, तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि पूरा दावा कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था।** इंटरनेट पर प्रसारित झूठ का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वह सत्यापन के अभाव में तुरंत धारणा बनाता है, जबकि खंडन और तथ्य सामने आने में समय लगता है। गलत सूचना की गति हमेशा तथ्य-जांच की गति से अधिक रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस अंतर को और बढ़ा दिया है। विमान का नियंत्रण अंततः प्रशिक्षित चालक दल और यात्रियों ने वापस हासिल कर लिया, लेकिन सूचना के क्षेत्र में ऐसा कोई आपातकालीन नियंत्रण तंत्र मौजूद नहीं है जो हर झूठ को तुरंत रोक सके। वहां जनता स्वयं अंतिम सुरक्षा दीवार है। यदि हजारों लोग किसी फर्जी वीडियो को बिना सोचे साझा कर दें, तो उसका डिजिटल प्रसार इतना व्यापक हो सकता है कि बाद में किया गया तथ्य-जांच अभियान भी सभी लोगों तक न पहुंचे। इसलिए डिजिटल नागरिकता का अर्थ केवल इंटरनेट का उपयोग करना नहीं, बल्कि जानकारी के प्रति संवेदनशीलता और

कैसी रही विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया

कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी के बाद जो प्रतिक्रिया आम तौर पर होनी चाहिए, नायक को जो सम्मान देना स्वाभाविक है, वह देने में पश्चिम के कई मीडिया संस्थान विफल रहे। दुर्भाग्य से इस घटना को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी को लेकर पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों पर गौर करना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे "हाथापाई" बताया। ब्रिटिश समाचार पत्र द गार्जियन ने उन्हें 'हीरो पायलट' यानी 'नायक पायलट' कहा, लेकिन नायक शब्द को उद्धरण चिह्नों में रखा। बीबीसी ने अपनी खबर का शीर्षक दिया, 'कौन हैं हीरो भारतीय पायलट?' यहां भी नायक शब्द को उद्धरण चिह्नों में रखा गया। इसी तरह समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस-प्रेस (एएफपी) ने शीर्षक दिया कि कॉकपिट में संघर्ष के बाद भारतीय पायलट को 'नायक' के रूप में सराहा गया। यहां भी नायक शब्द को उद्धरण चिह्नों में रखा गया। पहली नजर में यह एक मामूली संपादकीय शैली का मामला लग सकता है। कोई कह सकता है कि आखिर एक शब्द और उसके आगे-पीछे लगे दो उद्धरण चिह्नों से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पत्रकारिता में शब्दों का चयन केवल भाषा और व्याकरण तक सीमित नहीं होता। शब्दों के माध्यम से ही किसी घटना का स्वरूप, उसकी गंभीरता और उससे जुड़ी व्यक्तियों की छवि पाठकों के सामने निर्मित होती है। साफ़ हो चुका था कि भारत की छवि बिगाड़ने के एजेंडे को लगातार चलाने के बाद एक भारतीय के साहस को स्वीकारने में कितनी असहजता इन्हें हुई।



IV

119TH CONGRESS
2D SESSION

H. RES. 1612

Honoring Captain Smit Machehhar and the crew and passengers of Flydubai Flight 1073, and condemning the attempted terrorist attack on that flight.

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

OCTOBER 5, 2026

Mr. GOTTHEIMER (for himself, Mr. MCCAUL, and Mr. BACON) submitted the following resolution; which was referred to the Committee on Foreign Affairs

RESOLUTION

Honoring Captain Smit Machehhar and the crew and passengers of Flydubai Flight 1073, and condemning the attempted terrorist attack on that flight.

Whereas, on September 30, 2026, Flydubai Flight 1073 departed Dubai International Airport for Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, carrying approximately 174 passengers, the majority of them Israeli citizens, including 4 United States citizens and 27 children;

Whereas, midway through the flight, the first officer attacked the captain on the flight deck with the aircraft's emergency crash axe and attempted to seize the flight controls, and the aircraft lost more than 14,000 feet of altitude in under 30 seconds;

Whereas Captain Smit Machehhar, a citizen of India, fought off the attack and, despite grave injuries, used his re-

कप्तान स्मित की बहादुरी का अमरीकी संसद ने माना लोहा

सामाजिक सत्यापन को उससे भी अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। किसी वायरल संदेश को साझा करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उस झूठ से बनी धारणा को मिटाने में कई दिन, कई सप्ताह और कभी-कभी कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए डिजिटल युग में जिम्मेदार नागरिकता का सबसे सरल नियम होना चाहिए, पहले सत्यापन, फिर विश्वास और उसके बाद ही प्रसारण। बात पश्चिमी मीडिया के दोगलेपन की भी होनी चाहिए, जरा देखिए कि कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कैप्टन स्मित मच्छर के बारे में किस तरह खबरें प्रकाशित कीं। द गार्जियन ने उन्हें 'हीरो पायलट' कहा। और हम इसे बिल्कुल उसी तरह लिख रहे हैं, जिस तरह यह प्रकाशित हुआ था। यहां हीरो शब्द को उद्धरण चिह्नों के भीतर रखा गया। बीबीसी ने लिखा, "कौन हैं हीरो भारतीय पायलट?" यहां भी हीरो शब्द उद्धरण चिह्नों में था। वहीं समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस-प्रेस यानी एएफपी ने शीर्षक दिया, "कॉकपिट में संघर्ष के बाद भारतीय पायलट को हीरो के रूप में सराहा गया।" एक बार फिर हीरो शब्द के चारों ओर उद्धरण चिह्न लगाए गए। अब आप कह सकते हैं कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यह सिर्फ एक शब्द है। केवल दो उद्धरण चिह्न हैं। **लेकिन असली मुद्दा यही है। क्योंकि ये कोई अनजान ब्लॉग नहीं हैं। ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली समाचार संगठनों में शामिल हैं। इनकी सुर्खियां विभिन्न देशों तक पहुंचती हैं। इनकी खबरों को दूसरे समाचार संस्थान भी प्रकाशित करते हैं।करोड़ों लोगों के लिए किसी घटना की जानकारी पाने का पहला और कभी-कभी एकमात्र माध्यम वही सुर्खियां होती हैं, जिन्हें वे पढ़ते हैं। इसलिए जब कोई समाचार संस्थान बिना उद्धरण चिह्नों के किसी व्यक्ति को हीरो कहता है, तो वह स्वयं उस वर्णन की जिम्मेदारी लेता है।** इसके विपरीत, जब वह हीरो शब्द को उद्धरण चिह्नों में लिखता है, तो वह उस शब्द से एक दूरी बना लेता है। इसका अर्थ होता है कि दूसरे लोग उन्हें हीरो कह रहे हैं और समाचार संस्थान आवश्यक रूप से उस शब्द का समर्थन नहीं कर रहा है। इसे संपादकीय निष्पक्षता बनाए रखने का एक तरीका माना जा सकता है। लेकिन यदि यह वास्तव में निष्पक्षता का मामला है, तो उनके अपने पुराने समाचार अभिलेख बताते हैं कि अतीत में इस मानक को किस तरह लागू किया गया है। वर्ष 2008 में लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग के बाद द गार्जियन ने ब्रिटिश एयरवेज के सह-पायलट जॉन कोवार्ड को हीरो बताया था।उस समय हीरो शब्द के आसपास कोई उद्धरण चिह्न नहीं लगाए गए थे।वर्ष 2009 में, जब कैप्टन सुली सुलनबर्गर ने अमेरिका में साहसिक

आखिर कैसे दिया गया साजिश को अंजाम?

फ्लाईदुबई फ्लाइट एफजेड1073 के ओमानी को-पायलट हम्माम अल हम्मामी ने दुबई-तेल अवीव एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने और 11 सितंबर, 2001 के हमलों से प्रेरित होकर इसे इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल से टकराने की योजना बनाई थी। 29 साल के संदिग्ध ने 30 सितंबर को प्लान को अंजाम देने की कोशिश करने से पहले, रूट और एयरपोर्ट से खुद को परिचित करने के लिए तेल अवीव के लिए दो पिछली फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया था। इस घोषणा में फ़्लाइट के ख़िलाफ़ साज़िश के बारे में नई जानकारी दी गई है, जिसमें भारतीय कैप्टन स्मित थे। कहा जाता है कि संदिग्ध ने कॉकपिट के अंदर उन पर क्रैश एक्स से हमला किया और एयरक्राफ़्ट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। कैप्टन के विरोध करने और एक रिज़र्व पायलट, केबिन क्रू मेंबर और यात्रियों के बीच-बचाव करने के बाद हमला नाकाम कर दिया गया।

जांच करने वालों को संदिग्ध के अतिवाद की तरफ़ झुकाव के संकेत 2017 में मिले, जब वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था। गल्फ़ न्यूज़ ने बताया कि यूएई की जांच में कहा गया कि वह अतिवादी साहित्य और आतंकवादी संगठनों और आत्मघाती हमलों की बड़ाई करने वाले ऑनलाइन कंटेंट से प्रभावित था।

अधिकारियों ने कहा कि इन प्रभावों से कथित तौर पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले विचार सामने आए। संदिग्ध ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों से प्रेरणा ली और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके वैसा ही ऑपरेशन करने का विचार उसकी सोच में पूरी तरह बैठ गया। उसके कबूलनामे ने इस सोच को एविएशन में करियर बनाने के उसके फैसले से जोड़ा। संदिग्ध ने 2020 से 2024 तक ओमान एयर के लिए काम किया, 2025 में मोररोक्को के शाही एयरलाइंस में शामिल हुआ और जनवरी 2026 में फ्लाईदुबई चला गया। रॉयटर्स ने बताया कि रॉयल एयर मोरक्को ने कहा कि संदिग्ध ने 2025 में एयरलाइन के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग ली, लेकिन नौकरी के लिए उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया।ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पढ़ाई के दौरान, वह रेगुलर तौर पर रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक मस्जिद में जाता था। गल्फ न्यूज़ ने बताया कि कहा जाता है कि वह "माई सेंटर" नाम के एक सेंटर से जुड़े लोगों से जान-पहचान रखता था। संदिग्ध ने कथित तौर पर दावा किया कि सेंटर को "अबू हमज़ा" नाम का एक लेबनानी आदमी मैनेज करता था और उसे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पढ़ाई के दौरान, वह रेगुलर तौर पर रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक मस्जिद में जाता था।

गल्फ न्यूज़ ने बताया कि कहा जाता है कि वह "माई सेंटर" नाम के एक सेंटर से जुड़े लोगों से जान-पहचान रखता था। संदिग्ध ने कथित तौर पर दावा किया कि सेंटर को "अबू हमज़ा" नाम का एक लेबनानी आदमी मैनेज करता था और उसे मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े एक एसोसिएशन से मदद मिलती थी। घटना से पूर्व हम्मामी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली चीज़ों के संपर्क में आकर और एक प्राइवेट कोच से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया ।

वह यह हमला जुलाई में ही कर देता, लेकिन एक "दोस्त" के कारण उसने अपना फैसला टाल दिया। जांचकर्ता संदिग्ध की कथित तैयारियों और क्या उसके दूसरे लोगों या संगठनों से संबंध थे, इसकी जांच कर रहे हैं। अमीरात के अटॉर्नी-जनरल ने कहा कि वापसी की फ़्लाइट के लिए एक रिज़र्व पायलट उसी फ़्लाइट में सफ़र कर रहा था और हमले के समय वह कॉकपिट के पास था। पायलट ने देखा कि कॉकपिट का दरवाज़ा बार-बार अजीब तरीके से खुल और बंद हो रहा है। कॉकपिट में घुसने के बाद, उसने देखा कि संदिग्ध मच्छर पर हमला कर रहा है और उसने केबिन क्रू के एक सदस्य और कई यात्रियों के साथ बीच-बचाव किया।उन्होंने मिलकर घायल कैप्टन को बचाया और संदिग्ध को काबू में किया। इसके बाद रिज़र्व पायलट और उसके को-पायलट ने एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल वापस पा लिया, उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया और सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया।

रूप से हडसन नदी पर एक खराब एयरबस विमान की सफलतापूर्वक आपातकालीन लैंडिंग कराई, तो बीबीसी ने उन्हें हीरो पायलट कहा था। उस समय भी हीरो शब्द को उद्धरण चिह्नों में नहीं रखा गया था। ऐसे और भी उदाहरण हैं।वर्ष 2018 में, जब टैमी जो शुल्ट्ज ने अमेरिका में साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक क्षतिग्रस्त विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई, तो द गार्जियन के एक टिप्पणी आधारित लेख की सुर्खी थी, "टैमी जो शुल्ट्ज 148 लोगों की जान बचाने से बहुत पहले ही एक हीरो थीं।"यहां भी हीरो शब्द के आसपास कोई उद्धरण चिह्न नहीं थे। एएफपी ने भी सुलनबर्गर को 'हडसन के हीरो पायलट' कहा था और लिखा था कि वह दोबारा आसमान में लौट आए हैं।इसलिए **यहां सवाल यह नहीं है कि इन समाचार संस्थानों को हीरो शब्द का इस्तेमाल करना आता है या नहीं। जाहिर है, उन्हें इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरह आता है।सवाल यह है कि यहां उनकी भाषा क्यों बदल जाती है? यह मामला तब और दिलचस्प हो जाता है, जब उनके प्रतिस्पर्धी समाचार संस्थान उसी शब्द का इस्तेमाल बिना किसी शर्त या संदेह के करते हैं।** रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को ही देख लीजिए। दोनों ने स्मित को बिना उद्धरण चिह्नों के हीरो कहा है। ऐसे में यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ अन्य समाचार संस्थान अब भी पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर यह पक्षपात क्यों है?इस घटना को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग भी अपने आप में जांच और समीक्षा की मांग करती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कॉकपिट में हुए हमले को मूल रूप से एक कहासुनी या झड़प के रूप में वर्णित किया। अब जरा इस पर विचार कीजिए। **एक पायलट को चाकू मारा गया था। विमान हजारों फीट नीचे गिर रहा था। कॉकपिट की सुरक्षा भंग हो चुकी थी। यात्रियों को हमलावर को काबू करने में मदद करनी पड़ी. इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वह था 'अल्टरकेशन' यानी आपसी झड़प। दरअसल, अन्य समाचार संस्थानों की रिपोर्टिंग में भी लड़ाई और हाथापाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की भाषा ने वास्तव में जो कुछ हुआ था, उसकी गंभीरता को कम करके प्रस्तुत किया। अब यह स्पष्ट है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्टिंग का बचाव किया है। इस समाचार संगठन का कहना है कि उसने केवल उन्हीं तथ्यों को रिपोर्ट किया, जिनकी वह पुष्टि कर सकता था। लेकिन एक बार फिर, इस्तेमाल किए गए शब्द ही यह निर्धारित करते हैं कि किसी घटना को किस नज़रिए से देखा जाएगा। वे यह तय करने में मदद करते हैं कि लोग उस घटना को किस तरह समझेंगे।** भारतीय विमानन से जुड़े मामलों में हम ऐसा पहले भी देख चुके हैं। पिछले वर्ष जून की घटना पर लौटते हैं। एयर इंडिया की उड़ान एआई 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी। बाद में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इसमें दर्ज किया गया कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। रिपोर्ट में यह स्थापित नहीं किया गया था कि किस पायलट ने स्विच को बदला था। यह भी स्थापित नहीं किया गया था कि स्विच किस कारण से बदले गए और न ही किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया की कुछ खबरें तेजी से पायलट की गलती की ओर इशारा करने लगीं। बीबीसी की ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी पर लिखा था, "एयर इंडिया विमान हादसा, पायलट ने इंजनों की ईंधन आपूर्ति बंद की, विमान में कोई खराबी नहीं।" अन्य रिपोर्टों में भी संभावित मानवीय गलती और कॉकपिट की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि उस समय जांच अभी जारी थी। **एजेंडा साफ़ है, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश का सर जितना नीचे रख सकें कर दिया जाए। भारतीय कामगार, भारतीय उत्पादों का अत्यधिक दुष्प्रचार हो, अतिवादी ताकतों को बढ़ावा दिया जाए और अगला "अल-कायदा" भारतीय उपमहाद्वीप में पैदा किया जाए।** पूरी दुनिया में आज के समय आप्रवासी विरोध चल रहा है। मुस्लिम आप्रवासी अपने अधिकार के लिए जोर-शोर से लड़ते दिख रहे हैं, और सभी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं।फ्रांस में हो रहे छात्र आंदोलन की आड़ में आप्रवासी अपने चूल्हे भी सेंक रहे हैं। लेकिन, पश्चिमी मीडिआ की हिम्मत नहीं है , कि चूँ भी कर सके। दूसरी ओर भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई हैं, जिनके साथ लगातार नस्लवाद, भेदभाव और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ाया गया है। अमेरिका में तो यह एक तरह से राजनीतिक फायदा लेने का औजार तक बन चुका है। जिन भारतीय आप्रवासियों के दम पर अमेरिका का सिलिकॉन वैली खड़ा हुआ, आज उसी अमेरिका में एक भारतीय छात्र के लिए शिक्षा प्राप्त करना नाकों चने चबाने जितना कठिन है।**भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शांति मिशन में सहयोग करने वाला देश है, ऐसी कोई बड़ी वैश्विक प्राकृतिक आपदा नहीं , जिसमें भारत ने सहयोग न किया हो। ऐसे में बार-बार वैश्विक युवा पीढ़ी के मन में भारत के प्रति नकारात्मक छवि पैदा करना, भारतीयों की उपलब्धि को कम करके दिखाना, सम्मान को न स्वीकारना यह हीन-भावना से प्रेरित नहीं, एक सोची समझी नीति है। हमें यह मान् लेना चाहिए कि यदि हम अपने नायकों को खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वैश्विक स्तर पर हमारे नायकों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा।** कैप्टन स्मित को दिया गया सम्मान साहस, सेवा और मानवीय जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह भारत विरोधी तत्वों के लिए समय द्वारा दिखाया गया आईना है । ●

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित से फोन पर बातचीत कर न केवल उनके स्वास्थ्य का हाल जाना, बल्कि विमान हादसे के दौरान दिखाई गई उनकी असाधारण बहादुरी को पूरे देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा, "हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं।" बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने हादसे का आंखों देखा हाल साझा करते हुए बताया कि गंभीर चोटों के कारण वह विमान के नीचे फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि विमान नीचे जा रहा है और यदि उन्होंने आखिरी कोशिश नहीं की तो कई लोगों की जान जा सकती है कैप्टन ने अपनी हिम्मत का श्रेय भगवान हनुमान, हनुमान चालीसा के पाठ और परिवार से मिले संस्कारों को दिया। प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुनकर भावुक हो गए और उनके परिवार, विशेषकर पत्नी सोनल की हिम्मत और धैर्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि देशभर के मंदिरों में कैप्टन के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आभार जताते हुए कैप्टन को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और भारत उनकी सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।



नवंबर की शुरुआत में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, सांस लेना हुआ मुश्किल

दमघोंटू हवा के बीच दिल्ली

●मदर इंडिया डेस्क

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ने चिंताजनक रूप ले लिया है। सुबह और शाम के समय आसमान में छाई धुंध, सड़कों पर धुएं की चादर और हवा में घुलते प्रदूषक राजधानी की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि खुले में कुछ देर बिताना भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। **कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता स्तर भी बेहद खराब बना हुआ है।**

कई कारण, हर साल वही कहानी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारकों का संयुक्त प्रभाव है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उठने वाला धुआं हवा के साथ राजधानी तक पहुंचता है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और सड़कों पर जमा मिट्टी प्रदूषण को लगातार बढ़ाते हैं। नवंबर के दौरान मौसम में बदलाव भी स्थिति को गंभीर बना देता है। तापमान में गिरावट, हवा की धीमी गति और वातावरण में प्रदूषकों के जमा होने की वजह से जहरीले कण आसानी से फैल नहीं पाते।

नतीजतन, दिल्ली के ऊपर स्मॉग की मोटी और जानलेवा परत बन जाती है, जो जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है ।

ग्रैप के प्रतिबंध, लेकिन राहत कब?

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के दूसरे चरण के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके अंतर्गत सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल और धूल नियंत्रण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने तथा सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं।हालांकि, सवाल यह है कि क्या ये अस्थायी उपाय दिल्ली को स्थायी राहत दिला पाएंगे? हर साल सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के बाद आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं, लेकिन मौसम बदलते ही समस्या को लेकर चर्चा भी धीमी पड़ जाती है।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ता खतरा

प्रदूषित हवा का सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ता है। आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में भारीपन जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रदूषण अधिक होने पर सुबह की सैर और खुले मैदानों में व्यायाम से बचें। जरूरत पड़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाला एन95 मास्क पहनें और घर के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के उपाय करें। इसमें आप एयर प्यूरफाइअर लेना, घर में मिस्ट का छिड़काव और सुखाव करना शामिल है । इसके अतिरिक्त सबसे जरूरी है कि प्रदूषणकारी स्थानीय तत्वों पर आप नजर रखें, उसकी शिकायत 311 एप एमसीडी या एनजीटी के पोर्टल पर करें। सोशल मीडिया और समाज की भी सहायता जरूरत पड़ने पर अवश्य लें।

स्थायी समाधान की जरूरत

दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केवल कुछ दिनों के प्रतिबंध पर्याप्त नहीं हैं। **पराली प्रबंधन, स्वच्छ ईंधन, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और औद्योगिक उत्सर्जन की सख्त निगरानी जैसे कदम पूरे साल लागू करने होंगे।** केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। **आखिरकार, साफ हवा किसी शहर की सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है।** दिल्ली की चमकती इमारतें, चौड़ी सड़कें और आधुनिक विकास तभी सार्थक हैं,जब यहां रहने वाले लोगों को खुलकर सांस लेने का अवसर मिले।●

निजामपुर पशु आश्रय मामला

बेजुबानों के आशियाने पर चली जेसीबी

दिल्ली के निजामपुर गांव में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय की चारदीवारी गिराए जाने पर एमसीडी ने जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रूपये की सहायता का आश्वासन दिया है, जबकि फिजिक्स वाला के अलख पांडेय ने पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रूपये दिए हैं।



अवैध रूप से चारदीवारी गिराए जाने के बाद सीएम रेखा ने की त्वरित कार्रवाई

●मदर इंडिया डेस्क

दिल्ली के नजफगढ़-कांझावला क्षेत्र के निजामपुर गांव में पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के निर्माणाधीन पशु आश्रय की चारदीवारी तोड़े जाने के मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। **दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस मामले में भवन विभाग के जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।** वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जागृति मिश्रा को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडेय ने पशु आश्रय के पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी है। जागृति मिश्रा स्ट्रीट वर्ल्ड ट्रस्ट के माध्यम से घायल, बीमार, दिव्यांग और लावारिस पशुओं की देखभाल करती हैं। उनके संगठन के संरक्षण में 100 से अधिक आवारा कुत्ते और अन्य पशु हैं। वह निजामपुर गांव में एक पशु आश्रय और निःशुल्क पशु चिकित्सालय का निर्माण करा रही थीं। **मिश्रा के अनुसार, इस परियोजना के लिए उन्होंने अपनी बचत और आम लोगों से मिले चंदे के माध्यम से लगभग 70 लाख रुपये खर्च किए थे.** मामला 24 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब निर्माणाधीन आश्रय की चारदीवारी को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। **मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी।** घटना के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए, जो तेजी से वायरल हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनसे निर्माण कार्य के सिलसिले में पैसे मांगे गए थे और इनकार करने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। इसके बावजूद मामले की गंभीरता ने घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 अक्टूबर

को जागृति मिश्रा से मुलाकात की और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने, पुलिस को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की दिशा में कार्रवाई करने और जिलाधिकारी को पशु आश्रय दोबारा स्थापित करने में सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 26 अक्टूबर को एमसीडी ने बाहरी उत्तर क्षेत्र के भवन विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निगम के आदेश में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है। **हालांकि, निलंबन आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संबंधित अधिकारी पर कौन से विशिष्ट आरोप हैं और निर्माणाधीन ढांचे को गिराने के लिए क्या आधार अपनाया गया था।** इस मामले में राजनीतिक पहचान को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। शुरुआती वीडियो में जागृति मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की पार्षद सोनू डबास का नाम लिया था। इसके बाद आप विधायक जरनैल सिंह पार्षद सोनू डबास के साथ उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान मिश्रा ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्थानीय निवासी सोनू चिल्लर को सोनू डबास समझ लिया था। इस तरह पार्षद सोनू डबास को लेकर हुई गलतफहमी दूर हो गई। वहीं, दिल्ली पुलिस ने सोनू चिल्लर की भूमिका की जांच शुरू की।

इस बीच, फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडेय ने मिश्रा के पशु आश्रय के पुनर्निर्माण में मदद के लिए 10 लाख रुपये का योगदान दिया है। सांसद स्वाती मालिवाल ने भी 15 लाख रुपये अनुदान की घोषणा की। यह राशि निर्माणकार्य दोबारा शुरू करने और घायल तथा बेसहारा पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय तैयार करने में मदद के उद्देश्य से दी गई है। फिलहाल, इस मामले में एमसीडी की विभागीय जांच और पुलिस की पड़ताल महत्वपूर्ण बनी हुई है। यह भी देखना होगा कि पशु आश्रय के निर्माण को दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासन कब तक आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर , घटनास्थल का दौरा करने और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने की घटना की भी प्रशंसा होनी चाहिए। दिल्ली में एक महिला सीएम के रहते अगर दिल्ली की बेटी के साथ ऐसा हो तो वह निंदनीय है , और सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसे कृत्य पर सही कार्रवाई की है। नियमविरुद्ध रिश्वत लेकर निर्माण तोड़ देने की घटनाओं के साथ, अवैध निर्माण को संरक्षित करने के मामले भी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं , जिनपर ध्यान देने की भी कड़ी आवश्यकता है । ●

घटनाक्रम एक नजर में

24 अक्टूबर: निर्माणाधीन आश्रय की चारदीवारी जेसीबी से गिराई गई; मिश्रा का आरोप, कोई नोटिस नहीं मिला।

25 अक्टूबर: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात कर जांच के निर्देश दिए और 5 लाख रुपये की सहायता का आश्वासन दिया।

26 अक्टूबर: एमसीडी ने जूनियर इंजीनियर विकास कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया; राज्यसभा सांसद स्वाती मलिवाल ने किया 15 लाख रुपये सांसद फंड से देने का ऐलान

29-30 अक्टूबर: अलख पांडेय द्वारा पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपये के योगदान की खबरें आईं।



जागृति मिश्रा को सीएम रेखा रेखा गुप्ता ने दिया था त्वरित कार्रवाई का भरोसा



कानून

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार



अपराध पर सख्ती बरकरार

17 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस की कमान संभालने वाले आयुक्त अनुराग कुमार के शुरुआती कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर सख्ती, बीट पुलिसिंग, खुफिया तंत्र की मजबूती, यातायात सुधार और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिखाई देता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा से लेकर नशे के कारोबार के विरुद्ध अभियानों और पुलिसकर्मियों की समस्याओं तक, उनकी प्राथमिकताओं का दायरा व्यापक रहा है।

• विशेष संवाददाता

किसी महानगर की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करना केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने अथवा अपराधियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी नहीं है। विशेष रूप से देश की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में पुलिस के सामने चुनौतियों का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। यहां संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक प्रदर्शनों, वीआईपी सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से एक साथ निपटना पड़ता है।इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस पर देश की राजधानी की सुरक्षा के साथ-साथ करोड़ों नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। **ऐसी परिस्थितियों में पुलिस नेतृत्व के लिए प्रशासनिक अनुभव, दूरदर्शिता, अनुशासन, त्वरित निर्णय क्षमता और जनता के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। दिल्ली पुलिस के वर्तमान आयुक्त अनुराग कुमार ने 17 जुलाई 2026 को अपना कार्यभार संभाला था।** 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार इससे पहले खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। पुलिसिंग और खुफिया तंत्र का उनका अनुभव राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यभार संभालने के बाद से उनके द्वारा दिए गए विभिन्न प्रशासनिक और परिचालन संबंधी निर्देशों में पुलिस व्यवस्था की बुनियादी मजबूती, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय और पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार पर विशेष जोर देखा गया ।

वर्दी का बढ़ाया मान



शुरुआती कार्यकाल की प्राथमिकताएं

- **भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं , पदभार संभालते ही वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट संदेश।**
- **थानों की कार्यप्रणाली, बीट पुलिसिंग, पैदल गश्त और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर।**
- **20 जुलाई के बड़े प्रदर्शन के बाद विशेष शाखा को प्रस्तावित प्रदर्शनों की विस्तृत अग्रिम जानकारी जुटाने के निर्देश।**
- **हर ट्रैफिक सर्किल को कम से कम एक प्रमुख समस्या वाले स्थान की पहचान कर विशेष कार्य योजना बनाने को कहा गया।**

अनुराग कुमार, पुलिस आयुक्त, दिल्ली

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

उनके शुरुआती कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रुख रहा है। **पदभार संभालने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठकों में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।** यह संदेश ऐसे समय में महत्वपूर्ण था, जब दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई थी। पुलिस आयुक्त ने इस समस्या को केवल कुछ व्यक्तियों के आचरण तक सीमित रखने के बजाय पुलिस संगठन की साख और संस्थागत विश्वसनीयता से जोड़कर देखा।

दरअसल, पुलिस की छवि केवल अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि एक आम नागरिक के साथ थाने में कैसा व्यवहार किया जाता है। किसी व्यक्ति की शिकायत कितनी गंभीरता से सुनी जाती है, उसे न्याय मिलने की प्रक्रिया में कितनी सहायता मिलती है और पुलिसकर्मी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, ये सभी बातें पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को निर्धारित करती हैं। **वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जनसेवा का दायित्व भी है।** इस दृष्टि से भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख और पुलिसकर्मियों के आचरण में सुधार पर दिया गया जोर महत्वपूर्ण है।

बीट पुलिसिंग और पैदल गश्त

अनुराग कुमार ने पुलिसिंग की मूलभूत जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दी है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए केवल बड़ी जांच एजेंसियों और विशेष अभियानों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। **थानों की कार्यप्रणाली, बीट पुलिसिंग, पैदल गश्त, नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रिय उपस्थिति भी उतनी ही आवश्यक है।**

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने, अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के कार्यों की निगरानी करने और नागरिकों की शिकायतों के समाधान में व्यक्तिगत रुचि लेने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई की जानकारी देना और पुलिस अधिकारियों के लिए नागरिकों तक पहुंच आसान बनाना भी इस दिशा का हिस्सा है।

इस दृष्टिकोण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अपराध नियंत्रण की शुरुआत अपराध घटित होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले होती है। किसी इलाके में पुलिस की नियमित मौजूदगी अपराधियों के लिए निरोधक का काम कर सकती है। बीट अधिकारी यदि अपने क्षेत्र की परिस्थितियों, संदिग्ध गतिविधियों और स्थानीय समस्याओं से परिचित हों, तो कई घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता है। साथ ही, पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ने से अपराधों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने तथा जांच में सहयोग हासिल करने में भी सहायता मिलती है।

मजबूत खुफिया तंत्र

खुफिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना भी उनके कार्यकाल की एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में सामने आया । 20 जुलाई को केंद्रीय दिल्ली में हुए बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की अप्रत्याशित संख्या और परिस्थितियों को नियंत्रित करने में आई चुनौतियों ने पुलिस की अग्रिम तैयारी तथा खुफिया आकलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने विशेष शाखा को प्रस्तावित प्रदर्शनों के संबंध में अधिक व्यवस्थित और विस्तृत जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शनकारियों की संख्या सहित अन्य जानकारी



तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा (आईपीएस) से दिल्ली के लाखों नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करते अनुराग कुमार (आईपीएस)

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लगभग 15,000 दिल्ली पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों की तैनाती की गई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ की पुलिस के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और यातायात व्यवस्था पर समन्वय किया गया।

जैसे उनकी पृष्ठभूमि, अलग-अलग राज्यों से आने वाले लोगों की भागीदारी, आयोजकों और प्रमुख पदाधिकारियों की भूमिका, प्रदर्शन के मुद्दे, जुटाव के तरीके, ठहरने तथा आवागमन की व्यवस्था, स्थानीय संपर्क, संगठनों से जुड़ाव, वित्तीय स्रोत और अन्य व्यवस्थागत पहलुओं का आकलन करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य किसी भी बड़े प्रदर्शन से पहले परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझना और उसी के अनुरूप पुलिस बल, यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्था की योजना तैयार करना है। आधुनिक पुलिसिंग में खुफिया जानकारी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। 21वीं सदी में केवल घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय संभावित परिस्थितियों का पहले से आकलन करना अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि, इस तरह की व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है, जिसका पालन नवनियुक्त पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने करने का प्रयास किया। **प्रभावी पुलिसिंग वही है जो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करे।**

यातायात: हर सर्किल की जवाबदेही

यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में भी पुलिस आयुक्त ने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। दिल्ली की यातायात संबंधी समस्याएं हर इलाके में एक जैसी नहीं हैं। कहीं अतिक्रमण और अवैध पार्किंग जाम का कारण बनते हैं, तो कहीं खराब यातायात प्रबंधन, व्यस्त चौराहे, व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही और यातायात नियमों का उल्लंघन समस्या को गंभीर बना देते हैं।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ट्रैफिक सर्किल को कम से कम एक प्रमुख समस्या वाले स्थान की पहचान कर उसके समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसमें अतिक्रमण हटाने, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, सड़क प्रबंधन में सुधार और जनजागरूकता जैसे उपाय शामिल हैं।

ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने और गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यातायात प्रबंधन केवल चालान काटने तक सीमित नहीं रह सकता। दिल्ली के नागरिकों को रोजाना जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें लंबा ट्रैफिक जाम, सड़कों पर अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात नियमों की अनदेखी प्रमुख हैं। प्रत्येक यातायात सर्किल को स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए जिम्मेदार बनाना प्रशासनिक जवाबदेही को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है।

पार्कों का सुरक्षा ऑडिट

महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सितंबर में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के

एक डीडीए पार्क में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई। इस घटना ने राजधानी के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यह स्पष्ट हुआ कि केवल पार्क और सार्वजनिक स्थान विकसित कर देना पर्याप्त नहीं है; वहां पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मचारियों की उपलब्धता और नियमित पुलिस गश्त भी आवश्यक है।

इस घटना के बाद पुलिस आयुक्त ने सभी 15 पुलिस जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा का व्यापक ऑडिट करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत लगभग 1,500 पार्कों का निरीक्षण किया गया, जिनमें करीब 300 प्रमुख और बड़े पार्क शामिल थे। निरीक्षण में अंधेरे वाले स्थानों, खराब स्ट्रीट लाइट, गैर-कार्यशील सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता, चारदीवारी की स्थिति और पूर्व में हुई आपराधिक घटनाओं जैसे पहलुओं को शामिल किया गया।

इसके साथ ही संबंधित नगर निकायों और अन्य विभागों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं होती। किसी पार्क में रोशनी की व्यवस्था संबंधित नागरिक एजेंसी को करनी होती है, वहीं सीसीटीवी कैमरों का रखरखाव और चारदीवारी की मरम्मत भी अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी हो सकती है। पुलिस द्वारा इन कमियों की पहचान कर संबंधित एजेंसियों के साथ समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाना सार्वजनिक सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

ब्रिक्स सम्मेलन की कसौटी

अनुराग कुमार के कार्यकाल में दिल्ली पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जिम्मेदारियों में से एक 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भी रहा। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के शीर्ष नेता और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। ऐसे आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था किसी भी पुलिस बल के लिए बड़ी परिचालन चुनौती होती है।

दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन से पहले व्यापक सुरक्षा तैयारियां कीं। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, संदिग्ध वाहनों की जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, यातायात व्यवस्था और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।**इस दौरान लगभग 15,000 दिल्ली पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों की तैनाती की गई।** महत्वपूर्ण मार्गों पर विशेष निगरानी व्यवस्था भी स्थापित की गई। उद्देश्य था कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो तथा आम नागरिकों को भी यथासंभव कम असुविधा का सामना करना पड़े।इस तरह के आयोजन की सफलता केवल सुरक्षा कर्मियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए सूचनाओं का सही आदान-प्रदान,उनकी सटीकता की परख,तेज क्रियान्वयन



पदभार संभालने के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात करते पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार

अनुराग कुमार (आईपीएस)

एक संक्षिप्त परिचय

- 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी। मूल रुप से उत्तर प्रदेश के निवासी।
- वर्ष 2004-05 में दिल्ली के उत्तरी जिले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रहे।
- खुफिया ब्यूरो में जम्मू-कश्मीर डेस्क का नेतृत्व किया। जनवरी 2018 से तीन वर्ष से अधिक समय तक वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में मिनिस्टर (कार्मिक एवं सामुदायिक मामले) रहे।
- अक्टूबर 2021 में खुफिया ब्यूरो में लौटकर दिल्ली ब्यूरो का नेतृत्व किया और बाद में विशेष निदेशक बने।
- 2010 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2016 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित।
- 17 जुलाई 2026 को सतीश गोलचा के स्थान पर दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला।

अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, अनुशासित तैनाती और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक होती है। ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था ने एक बार फिर यह प्रदर्शित किया कि राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां भी हैं।

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव भी किया गया। 19 अगस्त को दिल्ली पुलिस में 43 आईपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हुआ। इसमें आठ विशेष आयुक्तों के साथ 21 डीसीपी और अतिरिक्त डीसीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया। यातायात, सतर्कता, विशेष शाखा, सुरक्षा, आर्थिक अपराध और अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों में भी दायित्वों का पुनर्वितरण हुआ।प्रशासनिक फेरबदल अपने आप में किसी सुधार का अंतिम प्रमाण नहीं होता, लेकिन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्मूल्यांकन किसी भी बड़े पुलिस संगठन के संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि इससे जिला स्तर पर निगरानी, निर्णय प्रक्रिया और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय कितना बेहतर होता है।

नशे के कारोबार पर वार

नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई भी दिल्ली पुलिस की प्रमुख परिचालन गतिविधियों में शामिल रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत एक महीने तक सत्यापन और प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जिसमें 191 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इस अभियान में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के सत्यापन के साथ मादक पदार्थों से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच की गई।

इसी प्रकार अक्टूबर में ऑपरेशन कवच 15.0 के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। इस अभियान में पुलिस ने 256 कथित नशा कारोबारियों को गिरफ्तार करने और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 214 मामले दर्ज करने की जानकारी दी। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की गई तथा मादक पदार्थों से अर्जित संदिग्ध धनराशि भी जब्त की गई।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस का पहले से संचालित अभियान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इसलिए इसे पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की नई पहल कहना उचित नहीं होगा। हालांकि,

आंकड़ों की जुबानी

1,500
पार्कों का सुरक्षा निरीक्षण, इनमें करीब 300 बड़े पार्क

15
पुलिस जिलों में सार्वजनिक स्थानों का सुरक्षा ऑडिट

43
आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल (19 अगस्त)

191
विदेशी नागरिक हिरासत में — ऑपरेशन विस्टा 1.0

256
नशा कारोबारी गिरफ्तार — ऑपरेशन कवच 15.0 की सफलता

214
मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज

उनके कार्यकाल में इस अभियान का प्रभावी संचालन मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की निरंतर कार्रवाई और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। **इस दिशा में वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब केवल छोटे स्तर के विक्रेताओं की गिरफ्तारी के बजाय नशे की आपूर्ति करने वाले बड़े नेटवर्क, वित्तपोषकों और संगठित गिरोहों पर भी प्रभावी कार्रवाई हो।**

पुलिस कल्याण के लिए कदम

पुलिस प्रशासन के एक ऐसे पहलू पर भी अनुराग कुमार ने ध्यान दिया है, जिसकी चर्चा अक्सर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की खबरों के बीच कम होती है। यह पहलू है पुलिसकर्मियों का कल्याण, उनकी कार्य परिस्थितियां और उनकी शिकायतों का समाधान और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास। 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में वकील और पुलिसकर्मियों के बीच हुई कथित झड़प के बाद स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया। इस घटना में एक अधिवक्ता के सिर में गंभीर चोट लगने का आरोप सामने आया। विवाद के बाद संबंधित एसीपी और थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया। हालांकि, इस संतुलनात्मक कार्रवाई से पुलिस विभाग के कुछ वर्गों में असंतोष पैदा हुआ। एक थाना विशेष के पुलिसकर्मियों और अन्य ने भी अपने सहकर्मियों के समर्थन में आवाज उठाई और उनके साथ होने वाले व्यवहार तथा विभागीय निर्णयों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।

2 नवंबर को पुलिस मुख्यालय में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एकत्रित हुए। **इस घटनाक्रम के बाद पुलिस आयुक्त ने स्वयं पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस संवाद के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जिला बार एसोसिएशनों और पुलिस के प्रतिनिधियों की संयुक्त समन्वय समिति बनाने की पहल सामने आई।** इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की पदोन्नति, एमएसीपी, आवास और अन्य सेवा संबंधी समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए भी संवाद व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह घटनाक्रम के बाद कई विशेषज्ञों ने पुलिस आयुक्त के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने साफ कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दबाव और अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं, पुलिस के विरुद्ध किसी भी शिकायत की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। पुलिस और वकील दोनों ही न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके बीच टकराव की स्थिति का लाभ अंततः अपराधियों को मिलता है और आम नागरिक प्रभावित होता है। ऐसे में संवाद और समन्वय की स्थायी व्यवस्था विकसित करना निश्चित रूप से आवश्यक है, जिसके लिए कदम समन्वय समिति के रूप में उठाए गए।

सुरक्षित दिल्ली केवल पुलिस का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की अपेक्षा है।

की गतिविधियां उल्लेखनीय रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस के ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित किए। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए उपयोगी समाधानों को प्रोत्साहित किया गया।

हालांकि यह अनुराग कुमार आईपीएस के पदभार संभालने से पहले, लेकिन उनके कार्यकाल में विद्यार्थियों के प्रयासों को मान्यता देने और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने का अवसर मिला। आज के दौर में पुलिसिंग को साइबर तकनीक, डिजिटल निगरानी, आंकड़ों के विश्लेषण और आधुनिक जांच प्रणालियों से जोड़ना आवश्यक हो गया है। ऐसे प्रयास भविष्य में पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

असली कसौटी: नतीजे

इन सभी पहलों और गतिविधियों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अनुराग कुमार के शुरुआती कार्यकाल में पुलिसिंग के कई महत्वपूर्ण आयामों पर ध्यान दिया गया है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से लेकर यातायात प्रबंधन तक, खुफिया तंत्र की मजबूती से लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा से लेकर पुलिसकर्मियों के कल्याण तक, उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का दायरा व्यापक रहा है।

हालांकि, किसी भी पुलिस आयुक्त के कार्यकाल का मूल्यांकन केवल बैठकों, निर्देशों, अभियानों और घोषणाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। **इन पहलों का वास्तविक महत्व उनके परिणामों से निर्धारित होगा।** भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का प्रभाव पुलिस विभाग की कार्यसंस्कृति में दिखाई देना चाहिए। खुफिया तंत्र की मजबूती से सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। यातायात संबंधी योजनाओं से जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आनी चाहिए। पार्कों की सुरक्षा के ऑडिट के बाद वहां पर्याप्त रोशनी, कार्यशील सीसीटीवी कैमरे और नियमित गश्त सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी प्रकार पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का लाभ उन्हें वास्तविक रूप में मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अपराधों की रोकथाम, जांच की गुणवत्ता, मामलों के निस्तारण, प्रतिक्रिया समय, साइबर अपराधों के खुलासे, यातायात दुर्घटनाओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जैसे मानकों पर नियमित जानकारी सार्वजनिक करना भी उपयोगी होगा। इससे नागरिकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि पुलिस द्वारा घोषित प्राथमिकताएं वास्तव में कितनी सफल हो रही हैं।फिलहाल अनुराग कुमार के शुरुआती कार्यकाल में कई ऐसे कदम देखने को मिले हैं जो एक आधुनिक, जवाबदेह और जन-केंद्रित पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। उनका जोर इस बात पर दिखाई देता है कि पुलिस बल केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने वाली संस्था न रहे, बल्कि अपराधों की रोकथाम, नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाए। **किसी भी पुलिस आयुक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल अपराधियों की गिरफ्तारी या बड़े आयोजनों की सफल सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। उसकी असली कसौटी यह होती है कि एक आम नागरिक थाने में अपनी शिकायत लेकर कितने विश्वास के साथ पहुंचता है, महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, व्यापारी अपनी समस्या के समाधान के लिए पुलिस पर कितना भरोसा करते हैं और पुलिसकर्मी स्वयं अपने संगठन में कितना सम्मान तथा सहयोग महसूस करते हैं।** राजधानी दिल्ली को ऐसी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है जो सख्त होने के साथ संवेदनशील भी हो, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होने के साथ मानवीय भी हो और कानून लागू करने में दृढ़ होने के साथ नागरिकों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध भी हो। अनुराग कुमार के अब तक के कार्यकाल में सामने आई पहलें इसी दिशा में कई सकारात्मक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। आवश्यकता है कि इन प्रयासों को निरंतरता मिले, इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और इनके परिणामों का नियमित मूल्यांकन हो।आखिरकार, सुरक्षित दिल्ली केवल पुलिस का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की अपेक्षा है। एक जवाबदेह पुलिस बल, अपराधमुक्त वातावरण, बेहतर यातायात व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और पुलिस-जनता के बीच मजबूत विश्वास ही उस राजधानी की पहचान बनने चाहिए, जिस पर देश गर्व कर सके। ●



डीयू के पिंक बूथ में महिला पुलिस अधिकारी से वार्ता करते अनुराग कुमार । छात्राओं की समस्याओं को भी सुनने, समझने और हल निकालने के लिए पुलिस आयुक्त ने दिए आदेश



No.14016/24/2007.UTS.I
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
Kartavya Bhavan -3, New Delhi
Dated the 17th July, 2026

ORDER

With the approval of the Competent Authority, Sh. Anurag Kumar, IPS (AGMUT:1994) is hereby appointed as Commissioner of Police, Delhi with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

2. Sh. Satish Golcha, IPS (AGMUT:1992) is directed to report to the Lieutenant Governor Delhi for further posting, upon assumption of charge by the new incumbent.

(Rakesh Kumar Singh)
Under Secretary to the Government of India
011-24610271

To,

Sh. Anurag Kumar, IPS (AGMUT:1994)

Copy to:

1. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
2. The Commissioner of Police, Delhi.
3. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.

INTERNAL DISTRIBUTION

PS to HM/PS to MoS(N)/PS to MoS(BGR)/PSO to HS/Sr. PPS to Secretary (BM)/PSO to AS (UT)/PSO to JS(UT)/PS to JS (P.I)/Personal file/Guard File/SO (IT)-to upload the order on MHA's website under AGMUT Cadre Management-order-transfer and posting.

गृह मंत्रालय का नियुक्ति आदेश, 17 जुलाई 2026

उपराज्यपाल के निर्देशों, सी.पी. के प्रयासों का जमीन पर असर

कर्तव्यनिष्ठा *22 जुलाई, संसद मार्ग*

घायल होने के बाद भी ड्यूटी पर डटे रहे एसीपी जय प्रकाश

पत्थर लगने से सिर से खून बहता रहा, फिर भी प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया



एसीपी पंजाबी बाग जय प्रकाश

साहस और कर्तव्य की मिसाल

● मदर इंडिया डेस्क

पंजाबी बाग सब-डिवीजन के एसीपी जय प्रकाश ने 26 फरवरी 2026 को पदभार संभाला था और तब से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत करने में सक्रिय हैं। 22 जुलाई को जंतर-मंतर पर सीजेपी के धरना-प्रदर्शन के दौरान उनकी तैनाती संसद मार्ग पर पहले बैरिकेड पर थी। शाम करीब 4:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी पानी की बोतलें उछालते हुए संसद की ओर बढ़ने लगे और भीड़ में शामिल कुछ शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। एक पत्थर एसीपी जय प्रकाश के माथे पर आंख के ऊपर लगा, लेकिन **घायल होने के बावजूद वे मोर्चे पर डटे रहे और प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया।** साथी पुलिसकर्मी उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां सिर पर कई टांके लगे। उपचार के बाद वे फिर से अपने सब-डिवीजन में ड्यूटी पर हैं। **क्षेत्रवासी उनकी कर्तव्यनिष्ठा की खुल कर सराहना कर रहे हैं।**

घटनाक्रम	26 फरवरी 2026	22 जुलाई, शाम 4:30	उपचार
	एसीपी पंजाबी बाग का पदभार संभाला	संसद मार्ग पर पथराव में घायल	आरएमएल अस्पताल, सिर पर कई टांके

जनसुनवाई *हर शनिवार, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे*

कीर्ति नगर थाने में सुनी गईं क्षेत्रवासियों की समस्याएं

एसीपी जय प्रकाश और एसएचओ महावीर सिंह ने नागरिकों से किया सीधा संवाद



डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी के नेतृत्व में पश्चिमी जिला पुलिस सजग

● मदर इंडिया डेस्क

दिल्ली पुलिस का 'थाना दिवस–जनसुनवाई' कार्यक्रम पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के नेतृत्व में राजधानी के थानों में जारी है। **इसी कड़ी में पंजाबी बाग सब-डिवीजन के कीर्ति नगर थाने में एसएचओ महावीर सिंह के नेतृत्व में जनसुनवाई हुई।** एसीपी पंजाबी बाग जय प्रकाश ने भी कार्यवाही का निरीक्षण कर क्षेत्रवासियों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई में धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों के साथ यूजीआर क्षेत्र के मेन मार्केट और चूना भट्टी में असामाजिक तत्वों द्वारा कथित रूप से शांति भंग करने जैसे स्थानीय मुद्दे उठे। कई मामलों में मौके पर ही समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस और जनता के बीच सीधे जुड़ाव की इस पहल का स्वागत किया। **डीसीपी (पश्चिम) हरेश्वर वी. स्वामी ने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिमी जिला पुलिस नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है।**



जनसुनवाई में शिकायतें सुनते पुलिस अधिकारी

एक नजर में	शुरुआत	कब	कहां
	जून 2026, उपराज्यपाल के निर्देश पर	हर शनिवार, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे	राजधानी के सभी थाने

कीर्ति नगर में 1/57A और 1/75 WHS के निर्माण ने खड़े किए सवाल

आखिर किसकी शह पर चल रहा है नियमों की अनदेखी का खेल?

● विशेष संवाददाता

दिल्ली में अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सरकार और संबंधित विभागों की सख्ती के दावों के बीच सेंट्रल दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित वेयरहाउज़िंग(डब्लूएचएस) क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। **स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्लॉट नंबर 1/57A और 1/75 डब्लूएचएस पर हो रहे निर्माण में निर्धारित भवन निर्माण नियमों और स्वीकृत नक्शे की अनदेखी ही नहीं की जा रही, बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण डंके की चोट पर किया गया है** । प्राप्त तस्वीरों में दोनों स्थानों पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार, इन निर्माणों में स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण किए जाने और भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा आधिकारिक निरीक्षण के बाद ही हो सकती है।

अनुमति कितनी, निर्माण कितना?

कीर्ति नगर के इन दोनों प्लॉटों पर हो रहे निर्माण को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौके पर किया जा रहा निर्माण स्वीकृत भवन नक्शे के अनुरूप है? सूत्रों के अनुसार, दोनों संपत्तियों पर निर्माण की वास्तविक स्थिति और स्वीकृत नक्शे के बीच अंतर है। स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच संबंधित विभाग से कुछ बातें जानना जरूरी है, जिनका ब्योरा साथ के बॉक्स में दिया गया है। यदि इन आरोपों में सच्चाई सामने आती है, तो यह भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला हो सकता है।

सरकारी जमीन और अतिक्रमण पर भी सवाल

सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र में सरकारी भूमि और निर्धारित सीमाओं के संभावित अतिक्रमण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में संबंधित विभाग के लिए जरूरी है कि वह राजस्व रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेजों और स्वीकृत भवन



विभाग से जरूरी सवाल

अनुमति: क्या दोनों प्लॉटों के भवन निर्माण के लिए विधिवत अनुमति ली गई है?

नक्शा: क्या निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जा रहा है?

FAR व ऊंचाई: क्या निर्धारित FAR और भवन की ऊंचाई संबंधी नियमों का पालन हो रहा है?

मंजिलें: क्या स्वीकृत मंजिलों से अधिक निर्माण किया जा रहा है?

निरीक्षण: क्या विभाग के अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है?

प्रकृति : 15 फीट गहरे बेसमेंट के साथ 6 मंजिला अवैध कमर्शियल निर्माण कैसे ?

नक्शे के आधार पर पूरे मामले की जांच करे।

आखिर किसी भी निर्माण को अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या मौके पर निर्माण की वास्तविक माप की गई? यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित विभाग को देना चाहिए।

कार्रवाई के दावे, फिर भी क्यों नहीं रुक रहा खेल?

दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। कई क्षेत्रों में अतिरिक्त मंजिलों, नियमों के विपरीत निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, कीर्ति नगर के 1/57A और 1/75 WHS के निर्माण की स्थिति भी जांच का विषय है। **सवाल यह है कि जब संबंधित विभागों के पास भवन निर्माण की निगरानी और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, तो ऐसे मामलों में समय रहते निरीक्षण क्यों नहीं होता?**

क्या विभाग को इन निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं है, या फिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? इस पूरे मामले में एमसीडी और संबंधित अधिकारियों से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपेक्षित हैं।

हादसों से सबक लें सुरक्षा से समझौता क्यों?

अवैध निर्माण केवल भवन नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण होने पर इमारत की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित हो सकती है। इससे न केवल भवन में रहने वाले लोगों, बल्कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है।

लापरवाही 5 *नवंबर, चावड़ी बाज़ार*

लें सबक, चावड़ी बाजार में इमारत गिरने के बाद जेई-एई सस्पेंड

आखिर ग्रेप 2 के बावजूद कैसे हो रहा था अवैध निर्माण? संकरी गली में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा



मलबे में राहत एवं बचाव अभियान



ढही हुई निर्माणाधीन इमारत



घटनास्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधि व अधिकारी

अवैध निर्माण ने ली दो जानें

● मदर इंडिया डेस्क

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित गली सतारा, शीश महल में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसा चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचीं।केंद्रीय जिला के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि इमारत का निर्माण तीसरी मंजिल तक हो चुका था और उसके ऊपर वाली मंजिल पर काम चल रहा था। छत की स्लैब डालने के दौरान इमारत ढह गई। एनडीआरएफ की मदद से अब तक तीन लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें से दो को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक घायल है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। उनके अनुसार यहां अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा था। इस संबंध में नगर निगम की संबंधित एजेंसियों को पहले ही पत्र भेजा गया था और लगातार कार्रवाई के लिए संपर्क किया जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सहायक अभियंता (एई) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) को निलंबित करने तथा ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी ने एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। एमसीडी मेयर प्रवेश वाही और क्षेत्रीय पार्षद राफिया माहिर ने यह पुष्ट किया कि इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी। मेयर ने भरोसा दिलाया है कि संबंधित तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

घटनाक्रम	सुबह 9:35	2 की मौत	कार्रवाई
	गली सतारा, शीश महल में इमारत ढही	एक घायल, मलबे से तीन लोग निकाले गए	एई-जेई निलंबित, ठेकेदार पर एफआईआर

इसलिए जरूरी है कि संबंधित विभाग केवल शिकायतों का इंतजार न करे, बल्कि समय-समय पर निर्माण स्थलों का निरीक्षण करे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

अब देखना यह है कि कार्रवाई कब होगी?

कीर्ति नगर के 1/57A और 1/75 WHS का मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी और सामने आई तस्वीरों के आधार पर इन निर्माण कार्यों की यदि निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग को बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कार्यों की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभाई।

आखिर सवाल यह है कि दिल्ली में आम नागरिक के लिए नियम इतने सख्त और कुछ निर्माणों के मामले में इतनी ढिलाई क्यों? दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में लगातार अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर कार्रवाई होती हमने देखी है। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सरकार, एलजी और दिल्ली के महापौर की ज़ीरो टोलरेंस की नीति है। ऐसे में सवाल है कि क्या एमसीडी इन दोनों निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर सच्चाई जनता के सामने लाएगी, या अवैध निर्माण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? जनता जवाब चाहती है, प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद रखती है। ●





नक्शे के आधार पर पूरे मामले की जांच करे।

आखिर किसी भी निर्माण को अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या मौके पर निर्माण की वास्तविक माप की गई? यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित विभाग को देना चाहिए।

कार्रवाई के दावे, फिर भी क्यों नहीं रुक रहा खेल?

दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। कई क्षेत्रों में अतिरिक्त मंजिलों, नियमों के विपरीत निर्माण और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, कीर्ति नगर के 1/57A और 1/75 WHS के निर्माण की स्थिति भी जांच का विषय है। **सवाल यह है कि जब संबंधित विभागों के पास भवन निर्माण की निगरानी और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, तो ऐसे मामलों में समय रहते निरीक्षण क्यों नहीं होता?**

क्या विभाग को इन निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं है, या फिर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है? इस पूरे मामले में एमसीडी और संबंधित अधिकारियों से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अपेक्षित हैं।

हादसों से सबक लें सुरक्षा से समझौता क्यों?

अवैध निर्माण केवल भवन नियमों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। निर्धारित मानकों के विपरीत निर्माण होने पर इमारत की संरचनात्मक मजबूती प्रभावित हो सकती है। इससे न केवल भवन में रहने वाले लोगों, बल्कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है।

लापरवाही 5 *नवंबर, चावड़ी बाज़ार*

लें सबक, चावड़ी बाजार में इमारत गिरने के बाद जेई-एई सस्पेंड

आखिर ग्रेप 2 के बावजूद कैसे हो रहा था अवैध निर्माण? संकरी गली में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा



मलबे में राहत एवं बचाव अभियान



ढही हुई निर्माणाधीन इमारत



घटनास्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधि व अधिकारी

अवैध निर्माण ने ली दो जानें

● मदर इंडिया डेस्क

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित गली सतारा, शीश महल में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढहने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। हादसा चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचीं।केंद्रीय जिला के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि इमारत का निर्माण तीसरी मंजिल तक हो चुका था और उसके ऊपर वाली मंजिल पर काम चल रहा था। छत की स्लैब डालने के दौरान इमारत ढह गई। एनडीआरएफ की मदद से अब तक तीन लोगों को बाहर निकाला गया है। इनमें से दो को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक घायल है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। उनके अनुसार यहां अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा था। इस संबंध में नगर निगम की संबंधित एजेंसियों को पहले ही पत्र भेजा गया था और लगातार कार्रवाई के लिए संपर्क किया जा रहा था, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे पर गहरी चिंता जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सहायक अभियंता (एई) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) को निलंबित करने तथा ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी ने एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। एमसीडी मेयर प्रवेश वाही और क्षेत्रीय पार्षद राफिया माहिर ने यह पुष्ट किया कि इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही थी। मेयर ने भरोसा दिलाया है कि संबंधित तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

घटनाक्रम	सुबह 9:35	2 की मौत	कार्रवाई
	गली सतारा, शीश महल में इमारत ढही	एक घायल, मलबे से तीन लोग निकाले गए	एई-जेई निलंबित, ठेकेदार पर एफआईआर

इसलिए जरूरी है कि संबंधित विभाग केवल शिकायतों का इंतजार न करे, बल्कि समय-समय पर निर्माण स्थलों का निरीक्षण करे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे।

अब देखना यह है कि कार्रवाई कब होगी?

कीर्ति नगर के 1/57A और 1/75 WHS का मामला कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी और सामने आई तस्वीरों के आधार पर इन निर्माण कार्यों की यदि निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग को बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निर्माण कार्यों की निगरानी करने वाले अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभाई।

आखिर सवाल यह है कि दिल्ली में आम नागरिक के लिए नियम इतने सख्त और कुछ निर्माणों के मामले में इतनी ढिलाई क्यों? दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में लगातार अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर कार्रवाई होती हमने देखी है। भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सरकार, एलजी और दिल्ली के महापौर की ज़ीरो टोलरेंस की नीति है। ऐसे में सवाल है कि क्या एमसीडी इन दोनों निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर सच्चाई जनता के सामने लाएगी, या अवैध निर्माण का यह खेल यूं ही चलता रहेगा? जनता जवाब चाहती है, प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद रखती है। ●







करोल बाग़ जोन समिति की चेयरपर्सन अलका ढींगरा के साथ नवनियुक्त डीसी



भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे चुकी हैं श्वेता नगरकोटी

चुनौतियां बड़ी

नगर निगम में उपायुक्त नियुक्त किया गया था। उस समय वह पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके बाद उन्हें निगम के नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी मिली और 21 अक्टूबर के आदेश के अनुसार उन्हें सेंट्रल जोन में तैनात किया गया है। नगरकोटी 2020 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अखिल भारतीय रैंक 410 हासिल की थी। **सेंट्रल जोन में नई जिम्मेदारी के साथ नगरकोटी के सामने निगम सेवाओं के संचालन, स्वच्छता, अतिक्रमण नियंत्रण, भवन संबंधी मामलों और नागरिक शिकायतों के निस्तारण जैसी प्रशासनिक प्राथमिकताएं रहेंगी।** निगम के इस फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न जोन और विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करना है। नगरकोटी का सेंट्रल जोन में आगमन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली में नगर निगम प्रशासन से जुड़ी जवाबदेही, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई तथा नागरिक सेवाओं की प्रभावशीलता प्रमुख प्रशासनिक मुद्दे बने हुए हैं। सेंट्रल जोन, जिसमें पूर्ववर्ती करोल बाग जोन जैसे पुराने और अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र शामिल हैं, वहां निगम प्रशासन के सामने भवनों की स्थिति, बाजार क्षेत्रों का प्रबंधन, स्वच्छता, पार्किंग, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और विकास कार्यों के समन्वय जैसी कई चुनौतियां रहती हैं। **देखना होगा दिल्ली नगर निगम का यह बदलाव क्षेत्र में व्याप्त अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगा पाएगा?** ●



एक शिष्टाचार भेंट के दौरान श्वेता नगरकोटी

सेंट्रल जोन की बड़ी चुनौतियां

- अवैध निर्माण पर अंकुश
- स्वच्छता और पार्किंग
- सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण
- विकास कार्यों का समन्वय
- पुराने भवनों की स्थिति
- नागरिक शिकायतों का निस्तारण
- बाजार क्षेत्रों का प्रबंधन
- जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर रोक

> **देखना होगा दिल्ली नगर निगम का यह बदलाव क्षेत्र में व्याप्त अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगा पाएगा?**

श्वेता नगरकोटी

एक नजर में

- 2020 बैच, एजीएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी।
- सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अखिल भारतीय रैंक 410।
- अरुणाचल प्रदेश के केयी पन्योर जिले की उपायुक्त रहीं।
- 7 अगस्त 2026 के आदेश से एमसीडी में उपायुक्त; पहले उत्तरी जोन, 21 अक्टूबर 2026 से सेंट्रल जोन।

डिजिटल इंडिया की नई उड़ान!

यूपीआई ने अक्टूबर में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड



25.47 अरब ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटल भुगतान ने देश में छुआ नया मुकाम

● मदर इंडिया डेस्क

भारत में डिजिटल क्रांति अब केवल बड़े शहरों और आधुनिक बाजारों तक सीमित नहीं रह गई है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, सब्जी विक्रेता से लेकर ऑनलाइन कारोबार तक, आज देश का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल भुगतान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना चुका है। **इसी बदलते भारत की एक बड़ी तस्वीर अक्टूबर 2026 में सामने आई, जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने लेनदेन के मामले में नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया।** अक्टूबर महीने में भारत में यूपीआई के माध्यम से कुल 25.47 अरब (2,547 करोड़) ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में इसमें लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा बताता है कि देश में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता कितनी तेजी से बढ़ रही है। यह उपलब्धि केवल तकनीकी विस्तार का संकेत नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहे बदलाव, लोगों की भुगतान संबंधी आदतों और व्यापार के नए तरीकों को भी दर्शाती है।

रोजाना 82 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन

अक्टूबर 2026 में यूपीआई के माध्यम से औसतन प्रतिदिन लगभग 82.2 करोड़ लेनदेन किए गए। इस दौरान कुल ट्रांजैक्शन का मूल्य बढ़कर लगभग 31.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से प्रतिदिन औसतन लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। पहली बार दैनिक औसत लेनदेन मूल्य ने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि यूपीआई अब केवल छोटी रकम के भुगतान का माध्यम नहीं रहा, बल्कि बड़े और छोटे दोनों प्रकार के आर्थिक लेनदेन में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

चाय की दुकान से बड़े शोरूम तक क्यूआर कोड का राज

कुछ साल पहले तक बाजारों में नकद भुगतान का ही बोलबाला था। छोटी दुकानों पर खरीदारी करने के लिए ग्राहकों को अक्सर खुले पैसे रखने पड़ते थे। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज छोटी से छोटी दुकान पर भी क्यूआर कोड दिखाई देना आम बात हो गई है। ग्राहक मोबाइल से कोड स्कैन करता है, रकम दर्ज करता है और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। किराना दुकानों और सब्जी विक्रेताओं द्वारा क्यूआर कोड से भुगतान स्वीकार करना, रेस्तरां और कैफे में मोबाइल से तत्काल बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली-पानी और मोबाइल बिलों का घर बैठे भुगतान, दोस्तों और परिवार के बीच तुरंत पैसों का लेनदेन तथा छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा, इस बदलाव के उदाहरण हैं। **इस बदलाव ने नकदी पर निर्भरता कम करने के साथ व्यापारिक लेनदेन को अधिक सुविधाजनक बनाया है।**

त्योहारों की खरीदारी ने बढ़ाई रफ्तार

अक्टूबर का महीना देश में त्योहारों और खरीदारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। नवरात्र, दुर्गा पूजा और दीपावली की तैयारियों के बीच बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी। कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, मिठाइयों और अन्य उत्पादों की खरीदारी में डिजिटल भुगतान का व्यापक इस्तेमाल हुआ।

सूत्रों के अनुसार, त्योहारों के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग, बाजारों में खरीदारी, खानपान और रोजमर्रा के खर्चों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान अब केवल सुविधा का विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक उपभोक्ता जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

छोटे व्यापारियों के लिए भी बना बड़ा सहारा

यूपीआई का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छोटे कारोबारियों के बीच देखा जा सकता है। पहले छोटे दुकानदारों को नकदी रखने, खुले पैसे उपलब्ध कराने और भुगतान का हिसाब रखने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डिजिटल भुगतान ने इन प्रक्रियाओं को काफी हद तक आसान बनाया है।

अब दुकानदार मोबाइल पर भुगतान की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अपने लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। इससे ग्राहकों को भुगतान की सुविधा मिलती है और व्यापारियों को भी अपने दैनिक कारोबार का हिसाब रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और घरेलू व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान एक उपयोगी विकल्प बनकर उभरा है।

डिजिटल क्रांति के साथ साइबर सुरक्षा भी बड़ी चुनौती

डिजिटल भुगतान ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसके साथ साइबर धोखाधड़ी की चुनौतियां भी सामने आई हैं। फर्जी क्यूआर कोड, नकली भुगतान स्क्रीनशॉट, अनजान लिंक, ओटीपी मांगने वाले कॉल और यूपीआई के जरिए धोखाधड़ी जैसी घटनाएं डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।अपने बड़े बुजुर्गों, और बच्चों की सुरक्षा भी यूपएआई के इस दौर में बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह है कि डिजिटल भुगतान करते समय कुछ सावधानियां हमेशा बरतनी चाहिए, जिनका ब्योरा साथ के बॉक्स में दिया गया है। **डिजिटल भुगतान की सफलता तभी स्थायी हो सकती है, जब तकनीकी सुविधाओं के साथ लोगों की डिजिटल सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।**

अक्टूबर 2026: आंकड़ों में यूपीआई

कुल ट्रांजैक्शन: 25.47 अरब (2,547 करोड़)

सालाना वृद्धि: पिछले अक्टूबर से लगभग 23 प्रतिशत अधिक

रोजाना औसत: लगभग 82.2 करोड़ लेनदेन

कुल मूल्य: लगभग 31.53 लाख करोड़ रुपये

रोजाना औसत मूल्य: लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये, पहली बार एक लाख करोड़ के पार

क्या भारत पूरी तरह कैशलेस होने की ओर?

यूपीआई के लगातार बढ़ते आंकड़े भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में नकदी का इस्तेमाल समाप्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, बैंकिंग सुविधाओं और साइबर सुरक्षा को लेकर अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं।

देश के सभी नागरिकों तक डिजिटल भुगतान की सुविधाएं पहुंचाने के लिए मजबूत इंटरनेट नेटवर्क, सुरक्षित बैंकिंग व्यवस्था और डिजिटल जागरूकता जरूरी है। इसके साथ ही बुजुर्गों और तकनीक का सीमित इस्तेमाल करने वालेलोगों को भी डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया समझाने की आवश्यकता है।

भारत की डिजिटल पहचान बनता यूपीआई

आज मोबाइल फोन केवल बातचीत का साधन नहीं, बल्कि खरीदारी, बिल भुगतान और कारोबार का माध्यम बन चुका है। **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अगला लक्ष्य केवल ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि डिजिटल सुविधाओं को देश के हर नागरिक तक सुरक्षित और समान रूप से पहुंचाना होना चाहिए।**

कभी जेब में नकदी रखना जरूरी हुआ करता था, आज कई लोगों के लिए मोबाइल में यूपीआई होना ही पर्याप्त है। यही बदलते भारत की डिजिटल तस्वीर है, जहां एक छोटा-सा क्यूआर कोड देश की बड़ी आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन चुका है।●

सुरक्षित भुगतान के 6 मंत्र

- अपना यूपीआई पिन और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें।
- पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी यूपीआई PIN दर्ज न करें।
- किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से बचें।
- भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और रकम जांच लें।
- भुगतान की पुष्टि केवल अपने बैंक या यूपीआई ऐप में करें।
- संदिग्ध ट्रांजैक्शन की सूचना तुरंत बैंक और साइबर अपराध हेल्पलाइन को दें।



LOVELY MARBLE HOUSE

- All Kinds of Marbles
- Marble Slabs
- Marble Tiles
- Granites
- Kota Stones

Happy Diwali



सुभाष सचदेवा
पूर्व विधायक
मोती नगर विधानसभा क्षेत्र



C-73, Shardapuri Ringh Road, New Delhi-110015

Phone: 9999007290 | 9999493736

AKS' HOMES
& INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

HAPPY Diwali

FESTIVAL OF LIGHTS,
FOUNDATIONS OF TRUST.

May the glow of Diyas bring prosperity to your home and happiness to your heart. Wishing you and your family a joyful and blessed Diwali.



Happy
Bhaiya Dooj



Happy
Guru Purab



Happy
Chhath



Arun Sehgal
9810167855



Rohit Sehgal
9871266855

D-12 GF Kirti Nagr New Delhi - 110015

Ph. 011-64523456, 64523457, 64523458

www.raintreegrill.com

A Trusted Name in Residential Construction & Infrastructure

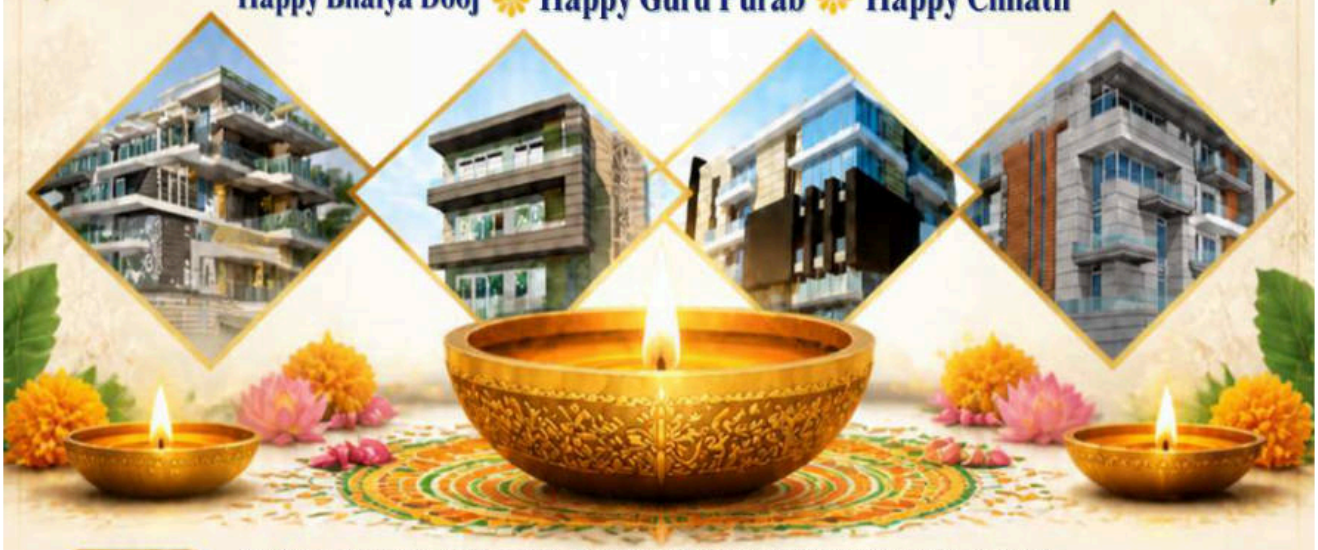
Wish You A Very Happy Diwali

KBT

FULFILLING PROMISES

HAPPY DIWALI

Happy Bhaiya Dooj ❋ Happy Guru Purab ❋ Happy Chhath





SHEKHAR GROVER
CHAIRMAN

Our Approach is to Look Beyond The Needsites Of Today, And Plan The Needs For Future. We Fulfill Our Business Objectives, Commercial Aspirations without Compromising On Quality Of Construction And Provide Exceptional Customer Services By Pursuing Business Through Innovation And Advanced Technology In The Field Of Construction.

Through Our Continuous Efforts, We Try To Get Better Every Single Day. Our Company Encourages Innovation And Futuristic Concepts, That Can Add Value To The Lives Of Our Esteemed Customers.

FOLLOW US ON

KAMAL BUILDTECH PVT. LTD.

KAMAL BUILDTECH PVT LTD.

~CONTACT DETAILS~
OFFICE

F-29,Central Market Kirti Nagar, Delhi - 110015

Phone No: +91 9310054006, +91 9990054006
Email: kamalbuildtech@hotmail.com
Website: www.kamalbuildtech.com

ROYAL KOAS®

शुभ लाभ

ROYAL KOAS®

EMPIRE SAFE CO.

Home & Office Furniture



Happy
Diwali



Happy Bhaiya Dooj | Happy Guru Purab | Happy Chhath

19, Furniture Block, Kirti Nagar, New Delhi – 110015
Phone: +91 80480 34068 Email: bhatia.empire@gmail.com

HAPPY
Diwali

KALA MANDIR
WOODEN FURNITURE

Manufacturers of Quality Wooden Furniture



Paras Ram Singh
7703990879



Shop No. 21, DDA LSC, Furniture Block, Kirti Nagar New Delhi-15 Ph. 41424116, 25417787, 25417438, Fax: 011-41424116
E-mail: info@kala-mandir.com, Web: www.kala-mandir.com



रमेश नगर में विधायक हरीश खुराना का क्षेत्रीय दौरा

अंगुली से नापकर दिखाई सड़क की मोटाई

व्यापारियों से सीधा संवाद कर सुनीं समस्याएं, सीवर, स्ट्रीट लाइट और पानी की लीकेज पर अधिकारियों को दिए तत्काल समाधान के निर्देश

●मदर इंडिया डेस्क

नई दिल्ली। जनसमस्याओं को समझने और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हरीश मदन लाल खुराना ने दीपावली से पूर्व रमेश नगर क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। वीरवार सुबह 11 बजे भ्याना टेंट हाउस, रमेश नगर गोलचक्कर से शुरू हुए इस दौरे में स्थानीय व्यापारियों, भाजपा पदाधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विमल भ्याना, पूर्व अध्यक्ष, भाजपा रमेश नगर मंडल के विशेष आग्रह पर डीआईडी न्यूज के चीफ एवं ऑल इंडिया एस एंड एम न्यूजपेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित सुमन भी क्षेत्रीय दौरे में शामिल हुए।

सड़क की गुणवत्ता की मौके पर जांच बनी चर्चा का विषय

दौरे का सबसे खास और चर्चित क्षण रमेश नगर मेन मार्केट में देखने को मिला, जब विधायक हरीश खुराना ने निर्माणाधीन सड़क की मोटाई को अपनी अंगुली से नापकर मीडिया और व्यापारियों के सामने प्रदर्शित किया। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मौके पर इस प्रकार जांच करने की पहल ने व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय व्यापारियों ने इसे विकास कार्यों की गुणवत्ता और जनता के सामने जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया।

इलाके के दौरे के दौरान रमेश नगर गोलचक्कर व्यापारी संगठन, वीरबंदा वैरागी मार्केट और ओल्ड मार्केट के व्यापारी संगठनों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर जिला भाजपा से मंगला, भाजपा रमेश नगर मंडल की अध्यक्षा दिव्या गोसाई, संजय खुराना, सुरेश कथुरिया सहित मंडल की पूरी टीम मौजूद रही।

व्यापारियों ने बताई अपनी समस्याएँ

व्यापारियों ने विधायक के समक्ष अपने-अपने बाजारों की समस्याएं रखीं और उनके शीघ्र समाधान की मांग की।
दौरे के दौरान व्यापारियों और स्थानीयनिवासियों ने रोजमर्रा की कई महत्वपूर्ण समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। इनमें सीवर, स्ट्रीट लाइट, पौधों की छंटाई, पानी की लीकेज और बाजारों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।

तत्काल समाधान के दिए गए निर्देश

स्थानीय लोगों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए विधायक हरीश खुराना ने संबंधित विभागों के कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) और सहायक अभियंताओं (एई) को तत्काल कार्रवाई करने तथा समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जनता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के मामलों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए।
दीपावली से पहले हुए इस क्षेत्रीय दौरे को स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने महत्वपूर्ण पहल बताया।

सार्थक सिद्ध हुआ दौरा

विभिन्न बाजारों के व्यापारी संगठनों की सामूहिक भागीदारी से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे जनप्रतिनिधि के सामने रखने का अवसर मिला।इस दौरे ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों का ध्यान बाजारों की बुनियादी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। **व्यापारियों को उम्मीद है कि अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद क्षेत्र में सफाई, रोशनी, सीवर और जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा।**
जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठन और स्थानीय नागरिकों के बीच सीधा संवाद किसी भी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। रमेश नगर का यह दौरा इसी दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में सामने आया। ●







उपराज्यपाल का दिल्ली पुलिस से सीधा संवाद

मजबूत पुलिस, सुरक्षित दिल्ली

● मदर इंडिया डेस्क

दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरणजीत सिंह संधू ने पुलिसकर्मियों के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उनके कल्याण, बेहतर कार्य परिस्थितियों और आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया है। **उन्होंने कहा कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के बीच विश्वास पैदा करना, पुलिस को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना और संवेदनशीलता के साथ लोगों की सेवा करना भी होना चाहिए।**

उपराज्यपाल ने उत्सव सदन में दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाद के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित किया और जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।











एक नज़र में

कब-कहां: 3 नवंबर 2026, उत्सव सदन, नई पुलिस लाइन (किंग्सवे कैंप), दिल्ली

मुख्य संदेश: पुलिसकर्मियों का कल्याण, बेहतर कार्य परिस्थितियां, आधुनिक संसाधन और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग

संवाद से बढ़ेगा भरोसा

उन्होंने पुलिसकर्मियों से पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरीकों के माध्यम से आम नागरिकों के साथ अपना संपर्क और संवाद मजबूत करने का भी आह्वान किया। उनका मानना है कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद से न केवल अपराध नियंत्रण में सहायता मिलती है, बल्कि नागरिकों का पुलिस व्यवस्था के प्रति भरोसा भी मजबूत होता है। **उन्होंने दिल्ली के लिए ऐसी व्यवस्था की कल्पना व्यक्त की, जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, उसकी बात सुनी जाए और उसे उचित संरक्षण मिले।** संधू ने जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत बनाने और आधुनिक पुलिसिंग पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। **उनके अनुसार, मजबूत पुलिस बल और सुरक्षित दिल्ली एक-दूसरे के पूरक हैं।**

उपराज्यपाल के संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस ने उनका आभार जताया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सहानुभूति और संवेदनशीलता को विशेष महत्व दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में निचले स्तर के कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवाद तथा पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने का विषय हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। ऐसे समय में उपराज्यपाल का पुलिस बल के साथ सीधा संवाद और उनके कल्याण के प्रति समर्थन का आश्वासन पुलिस व्यवस्था में संवाद, विश्वास और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संधू का संदेश स्पष्ट है कि विकसित दिल्ली का सपना तभी साकार हो सकता है, जब उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ मानवीय और नागरिक-केंद्रित भी हो। एक ऐसी पुलिस व्यवस्था, जहां पुलिसकर्मी सम्मान और बेहतर सुविधाओं के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा आम नागरिक बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास पहुंच सकें, सुरक्षित दिल्ली की वास्तविक पहचान बन सकती है।●



सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

डेटा संरक्षण कानून बनाम प्रेस की स्वतंत्रता

निजता भी जरूरी, पारदर्शिता भी

● मदर इंडिया डेस्क

लोकतंत्र में नागरिकों के पास सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि उन सवालों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता मौजूद रहे। प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों, समाचार पत्रों या टेलीविजन चैनलों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार का विस्तार है। भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सार्वजनिक धन की लूट का पर्दाफाश करने के लिए पत्रकारों को अनेक बार ऐसे दस्तावेजों तक पहुंचना पड़ता है जिनमें संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारियां भी शामिल होती हैं। ऐसे में यदि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया कोई कानून पत्रकारिता की सामान्य कार्यप्रणाली को ही कानूनी जोखिम में डालने लगे, तो यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के अधिकार से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन जाता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली, 2025 को लेकर यही बहस अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए आशंका जताई है कि यदि पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं दी गई, तो खोजी पत्रकारिता पर गंभीर अंकुश लग सकता है। डीएनपीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने कहा कि यदि समाचार के विषय बने व्यक्ति को ही अपने व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर ऐसा नियंत्रण मिल जाए जिससे वह रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सके, तो पत्रकारिता का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा।

न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 17 नवंबर को विस्तृत सुनवाई निर्धारित की और कहा कि नागरिकों के निजता के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। वास्तव में यह मीडिया और सरकार के बीच टकराव नहीं, बल्कि दो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन स्थापित करने की चुनौती है।

कानून की जरूरत

डेटा चोरी, पहचान की जालसाजी और साइबर धोखाधड़ी के इस दौर में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून आवश्यक था। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के माध्यम से निजता के इस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। इसलिए प्रश्न कानून की आवश्यकता का नहीं, बल्कि उसके स्वरूप, दायरे और उसके लागू होने के तरीके का है।

कहां है टकराव ?

क्या किसी सरकारी अधिकारी से जुड़े भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को प्रकाशित करने से पहले पत्रकार को उसी अधिकारी की सहमति प्राप्त करनी चाहिए? कानून डेटा फिड्यूशरी पर सहमति प्राप्त करने, सहमति वापस लेने की सुविधा देने और डेटा मिटाने जैसे दायित्व डालता है। यह व्यवस्था व्यापारिक कंपनियों और डिजिटल मंचों के लिए उचित है, लेकिन पत्रकारिता का कार्य इनसे मूलतः अलग है। जांच के दायरे में आया व्यक्ति यदि पहले ही आपत्ति का इस्तेमाल करके प्रक्रिया रोक सके, तो सबूतों को प्रभावित करने और स्रोतों पर दबाव डालने की संभावना पैदा हो सकती है। सार्वजनिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी निजता का अधिकार रखता है, लेकिन उसकी निजता और उसके सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बीच अंतर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्यता है। हालांकि अधिनियम में ऐसा कोई सीधा वाक्य नहीं है कि हर समाचार प्रकाशित करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी ही होगी। पत्रकारिता के लिए स्पष्ट वैधानिक

अपवाद का अभाव ही इस कानूनी अस्पष्टता को जन्म दे रहा है।

सूचना के अधिकार पर असर

अधिनियम की धारा 44(3) के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में किया गया संशोधन 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है। पहले व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से पहले व्यापक जनहित की कसौटी परखी जाती थी, अब ऐसी सूचना देने की बाध्यता ही नहीं रही। सूचना के अधिकार के माध्यम से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा और सरकारी नियुक्तियों की अनेक अनियमितताएं उजागर हुई हैं। यदि निजता के नाम पर जनहित से जुड़ी जानकारी तक पहुंच सीमित हो जाए, तो इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सकता है जो सार्वजनिक जवाबदेही से बचना चाहते हैं।

मीडिया की भी जिम्मेदारी

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने का अधिकार नहीं है। अपुष्ट आरोपों को तथ्य की तरह प्रस्तुत करना या पीड़ितों और नाबालिगों की पहचान उजागर करना पत्रकारिता की स्वतंत्रता के अंतर्गत उचित नहीं ठहराया जा सकता। यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुच्छेद 85 की तरह भारत में भी ऐसी संतुलित व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है, जो जनहित की पत्रकारिता को संरक्षण दे, पर निजी जानकारी के दुरुपयोग को नहीं।

समाधान का समय

अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी होने निर्धारित हैं, यानी व्यावहारिक समाधान निकालने का पर्याप्त अवसर मौजूद है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को कहा था कि अधिनियम का उद्देश्य पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करना नहीं है और सरकार संपादकों के सुझाव सुनने के लिए तैयार है। इस आश्वासन को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा में बदला जाना चाहिए, ताकि छोटे कस्बों के पत्रकार और स्वतंत्र खोजी पत्रकार भी, जिनके पास बड़े कानूनी विभाग नहीं होते, बिना डर के काम कर सकें।

न तो निजता के नाम पर पत्रकारिता को नियंत्रित किया जा सकता है और न ही पत्रकारिता के नाम पर निजता के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। लोकतंत्र में निजता भी जरूरी है और पारदर्शिता भी। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही एक संवैधानिक सरकार, जिम्मेदार मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका की साझा जिम्मेदारी है। ●

पीआरजीआई: संवाद और सरलीकरण की पहल



योगेश कुमार बवेजा
प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया



संतोष कुमार
अपर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (एपीआरजी)

यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रेस और प्रकाशन जगत की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआई) की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। पूर्व में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (आरएनआई) के नाम से जाना जाने वाला यह संस्थान, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बवेजा (आईआईएस) के नेतृत्व एवं संतोष कुमार, एपीआरजी के पर्यवेक्षण में लगातार प्रेस एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आधुनिक और व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रेस एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत शुरू किया गया 'प्रेस सेवा पोर्टल' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन, पंजीकरण, प्रमाणपत्र में संशोधन, स्वामित्व हस्तांतरण, वार्षिक विवरण जमा करने और प्रिंटिंग प्रेस संबंधी सूचनाओं जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। पहले जिन प्रक्रियाओं के लिए प्रकाशकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनमें अब एकल खिड़की डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता और सुविधा लाने का प्रयास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ऑनलाइन आवेदन और आवेदन की स्थिति की जानकारी जैसी सुविधाओं से प्रकाशकों के समय और प्रशासनिक खर्च में कमी लाने का प्रयास हुआ है। नए कानून ने छोटी प्रक्रियागत गलतियों के लिए कारावास के पुराने प्रावधानों को भी समाप्त किया है। सरकारी जानकारी के अनुसार, पोर्टल के शुरुआती छह महीनों में लगभग 40 हजार प्रकाशक इससे जुड़ चुके थे, 37 हजार वार्षिक विवरण जमा किए गए थे और तीन हजार प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण हुआ था।

पीआरजीआई की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रकाशकों के साथ सीधे संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यशालाओं का आयोजन है। जुलाई 2025 में चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशकों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। अगस्त 2025 में हैदराबाद में 'वार्तालाप' कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाशकों की समस्याओं और नए कानून से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की गई। सितंबर 2025 में अहमदाबाद में भी प्रेस सेवा पोर्टल के उपयोग और पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को समझाने के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। इन कार्यक्रमों में प्रकाशकों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने, तकनीकी कठिनाइयों को समझने और कई समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया गया। पीआरजीआई ने प्रकाशकों को सीधे पोर्टल का इस्तेमाल करने, बिचौलियों से बचने तथा उपलब्ध तकनीकी मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण सामग्री का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। ये पहलें इस बात का उदाहरण हैं कि सरकारी नियामक संस्थाएं केवल नियम लागू करने तक सीमित न रहकर संबंधित उद्योग की समस्याओं को समझें और उनका समाधान भी करें। पीआरजीआई का प्रकाशकों के साथ संवाद, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास एक सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पत्रकार जगत को आशा है कि डेटा संरक्षण कानून और उससे उपजी चिंताओं के संदर्भ में भी सरकार और मीडिया संस्थानों के बीच पीआरजीआई कार्यालय की तर्ज पर इसी तरह का संवाद हो,ताकि पत्रकारिता की वास्तविक आवश्यकताओं को समझकर ऐसे प्रावधान तैयार किए जा सकें जो नागरिकों की निजता की रक्षा करने के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखें।



मजाक नहीं
नस्लीय अपमान



भारत में नस्लभेदी ताकतों के पनपने और उन्हें पनाह देने के पीछे कई बार हाथ होता है उन जालसाज इन्फ़्लुएन्सरों का ,जिनके लिए बाँकी दुनिया केवल 'कंटेन्ट' और कमाने का जरिया है। मदर इंडिया पत्रिका लगातार ऐसे फिनफलुएंसर, ठगफ्लुएंसर , और सेक्सफ्लुएंसरों के बारे में पूर्व के अंकों में आप पाठकों को बता चुकी है। धंधे को गंदा करने वाली ऐसी ही एक मछली की करतूत आज आपके सामने एक बार फिर से .....



● मदर इंडिया डेस्क

दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ त्रिपुरा के एक युवक पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज होना इस बात की याद दिलाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की गरिमा के बीच स्पष्ट सीमा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में शौकीन साफ तौर पर युवक को उसकी शक्ल-सूरत और जातीय पहचान के आधार पर 'चीनी' कहकर चिढ़ाते तथा पड़ोसी देश से जुड़ी टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। इस घटना ने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत में आक्रोश पैदा किया है। दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बाद की मीडिया रिपोर्टों में शौकीन की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी गई। बीएनएस के अतिरिक्त इसपर पूर्व में आईपीसी धाराओं में भी केस दर्ज हो चुके हैं। इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारतीय युवा को उनकी शारीरिक बनावट, चेहरे की विशेषताओं, भाषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर विदेशी समझ लेने की प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को उनकी आंखों, चेहरे या पहनावे के आधार पर चीनी अथवा किसी अन्य देश का नागरिक कह देना केवल अज्ञानता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनकी भारतीयता को नकारने

वाला अपमान भी है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहचान है। इन विविधताओं को भारतीय समाज की समृद्धि के रूप में देखने के बजाय उपहास का विषय बनाना संकीर्ण सोच को उजागर करता है। **भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, गरिमा और भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। किसी व्यक्ति की पहचान को निशाना बनाकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वाभाविक या अनिवार्य हिस्सा नहीं है।** लोकतंत्र में असहमति, व्यंग्य और हास्य के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी समुदाय को नीचा दिखाने के औचित्य के रूप में नहीं किया जा सकता। शौकीन ने विवाद बढ़ने के बाद माफी मांगी और कथित तौर पर दावा किया कि वीडियो एक परिचित व्यक्ति के साथ बनाया गया था तथा उसका उद्देश्य मजाक करना था। इस दावे की सत्यता की जांच आवश्यक है। यदि वीडियो वास्तव में पूर्वनियोजित था, तो यह जानना महत्वपूर्ण तो यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उसमें शामिल युवक की सहमति किस सीमा तक थी, उसे रिकॉर्डिंग के उद्देश्य और संभावित प्रसार की जानकारी थी या नहीं, और क्या सामग्री के प्रसारण से उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। केवल यह कह देना कि सब कुछ पटकथा के अनुसार था, मामले को अपने आप समाप्त नहीं कर देता। यह विवाद केवल एक इन्फ्लुएंसर या एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर के लोगों को देश के विभिन्न महानगरों में रहने, पढ़ने और काम करने के दौरान कभी-कभी नस्लीय टिप्पणियों, रूढ़ धारणाओं तथा पहचान से जुड़े अपमान का सामना करना पड़ता है। किसी नागरिक से बार-बार यह पूछना कि वह भारत का है या किसी दूसरे देश का, अथवा उसकी राष्ट्रीयता को चेहरे की बनावट से जोड़ना, उसे अपने ही देश में बाहरी होने का अनुभव करा सकता है। राष्ट्रीय एकता के नारे तभी सार्थक होंगे जब प्रत्येक नागरिक को व्यवहार में समान सम्मान मिले। पूर्वोत्तर भारत देश का कोई अलग-थलग हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति और संवैधानिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। उसकी जनता के सम्मान की रक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के दौर में सामग्री बनाने वालों की जिम्मेदारी कई गुणा



अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, शौकीन को एक युवा से भिड़ते हुए देखा गया। उस **आदमी के साफ़-साफ़ कहने के बावजूद कि वह त्रिपुरा से है, शौकीन ने उसका मज़ाक उड़ाया और पूछा कि क्या वह चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। उसने बार-बार उस आदमी के हेयरस्टाइल और फीचर्स का मज़ाक उड़ाया और राज्य के नाम को हिंदी में एक गंदी गाली में बदल दिया।** जब वह आदमी उकसावे पर ध्यान नहीं देता दिखा, तो शौकीन ने जवाब पाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी छुआ। **केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू के पोस्ट और सोशल मीडिया पर इस घटना से उत्पन्न आक्रोश के बाद प्रशासन की नींद खुली और आरोपी शोकीन को गिरफ्तार कर लिया गया।**







नस्लीय टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार आमिर शौकीन के बारे में डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट निहारिका भट्ट ने कहा, "यह केस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। आरोपी मोहम्मद आमिर उर्फ आमिर शौकीन ने त्रिपुरा के एक युवक के खिलाफ नस्लीय गालियां दी थीं। इसी वजह से उसे करोल बाग से गिरफ्तार किया था। इस बारे में हमने कोर्ट से आरोपी की पुलिस कस्टडी देने की रिक्वेस्ट की थी, और दिल्ली पुलिस को इस आरोपी की पांच दिन की कस्टडी मिल गई है. क्योंकि संबंधित वीडियो गुजरात में बनाया गया था, इसलिए हमारी टीम सीन को रीक्रिएट करने के लिए गुजरात जाएगी। दिल्ली पुलिस ने केस भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 192, 196, 352, और 353 के तहत दर्ज किया। आमिर पर पूर्व में भी आईपीसी के अंतर्गत मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं इससे पहले त्रिपुरा पुलिस भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शोकीन को दिल्ली पुलिस से हिरासत में लेने के लिए सदर बाजार पुलिस स्टेशन पहुंची। डीएसपी समुद्र देबबर्मा ने कहा, "त्रिपुरा में केस दर्ज किया गया है; जांच अभी भी चल रही है कार्रवाई जांच के स्टेज और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी..."। तीस हजारी कोर्ट में भी आमिर की पेशी हुई जहां उसे 5 दिन की कानूनी हिरासत में भेज दिया गया।

पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्तेजक संवाद, अपमानजनक व्यवहार और विवादास्पद वीडियो तेजी से प्रसारित किए जाते हैं। अधिक दृश्य, अनुयायी और विज्ञापन से होने वाली कमाई की चाह में मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ देना डिजिटल मनोरंजन की गंभीर समस्या है। किसी व्यक्ति को अपमानित करके बनाई गई सामग्री से यदि लोकप्रियता मिलती है, तो उससे ऐसी ही सामग्री बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है। सोशल मीडिया मंचों को नस्लीय उत्पीड़न और लक्षित दुर्व्यवहार के विरुद्ध अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। साथ ही, नागरिकों को भी किसी विवादास्पद वीडियो को साझा करने से पहले उसके संदर्भ और संभावित प्रभाव पर विचार करना चाहिए। इस मामले में दिल्ली और त्रिपुरा पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राथमिकी दर्ज होने और गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद जांच को केवल सार्वजनिक आक्रोश शांत करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पुलिस को मूल वीडियो, उसके संपादन और प्रसारण से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच करनी चाहिए तथा पीड़ित युवक के बयान को संवेदनशीलता केसाथ दर्ज करना चाहिए। हालांकि प्रेस संस्था पीटीआई से बात करने के दौरान् पीड़ित युवक का पक्ष भी सामने आया। 19 साल के युवक, जिसके साथ एक वायरल वीडियो में नस्लीय दुर्व्यवहार हुआ था, ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन को बिना शर्त माफी मांगने के बाद माफ कर दिया।गुजरात शहर के एक रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग स्टाफ़, लड़के ने मीडिया को फ़ोन पर बताया, "सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो असल में करीब एक महीने पहले शूट किया गया था, शायद अहमदाबाद में मज़े में। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे फ़िल्मा रहा है। मुझे तब पता चला जब कुछ दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, और मैं परेशान हो गया।" उन्होंने कहा, "इन्फ्लुएंसर ने अपने काम के लिए पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली है, और मैंने उसे माफ कर दिया है।" नॉर्थ त्रिपुरा के आनंद बाजार इलाके के रहने वाले इस लड़के ने कहा कि उसे डर है कि अगर विवाद बढ़ा और पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि देश से उन्हें मिल रहे प्यार के कारण , ऐसा होना निकट भविष्य में बिल्कुल संभव नहीं है । लेकिन इसका एक बेहद निजी और मार्मिक कारण है। इस जिम्मेदार युवा ने मीडिया को कहा कि वह हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं, जो उनके चार लोगों के परिवार के लिए कमाई का एकमात्र ज़रिया है। उन्होंने कहा, "मैंने अगरतला के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 9 तक पढ़ाई की और अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसे कमाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं साढ़े तीन महीने पहले रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर शामिल हुआ, जिसकी महीने की सैलरी 10,000 रुपये थी। मैं भविष्य में मुश्किल में पड़ जाऊंगा।" सभी पार्टियों के नेताओं ने इस बेहूदा घटना की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की। इसे इस लड़के का बड़प्पन ही कहा जा सकता है कि अपने से उम्र में कई गुना बड़े आमिर द्वारा की गई ऐसी नस्लभेदी हरकत के

करने वाले को माफ कर दे रहा है। लेकिन, क्या आमिर सिद्दीकी पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने उत्तर पूर्वी मूल के भारतीयों के साथ ऐसी अभद्रता की हो ? 24 मार्च 2026 को लोकसभा में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण, नस्लीय अपशब्द, उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाओं का केंद्रीय स्तर पर अलग से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। एनसीआरबी की प्रकाशित अपराध रिपोर्टें उस समय 2023 तक उपलब्ध थीं।दिसंबर 2025 में एंजेल चकमा के साथ हुए जघन्य अपराध की खबर हमारी पत्रिका ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी। अंजेल चकमा त्रिपुरा के रहने वाले एमबीए विद्यार्थी थे।वह अपने छोटे भाई माइकल के साथ बाहर गए थे।आरोप है कि कुछ लोगों ने दोनों भाइयों को चीनी और मोमो कहकर नस्लीय टिप्पणियां कीं। विरोध करने पर विवाद हिंसक हो गया और अंजेल पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल अंजेल की 26 दिसंबर को मृत्यु हो गई। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें दो नाबालिग थे। फरवरी 2026 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। मुख्य आरोपी के नेपाल में होने की सूचना थी।फरवरी 2026 में मालवीय नगर में महिलाओं के फ्लैट में एयर कंडीशनर लगवाने के दौरान नीचे रहने वाले पड़ोसियों से विवाद हुआ। महिलाओं का आरोप था कि पड़ोसियों ने उन्हें नस्लीय और अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बनाया।वायरल वीडियो में महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल दिखाई दिया। कथित तौर पर उन्हें गलत तरीके से देह व्यापार से जोड़ने वाली टिप्पणियां भी की गईं।पुलिस ने दो पड़ोसियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 79, 351(2), 3(5) और 196 के तहत एफआईआर दर्ज की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी घटना की निंदा की। 6 अप्रैल 2026 को वीडियो वायरल हुआ जहां अरुणाचल प्रदेश की एक सांस्कृतिक नृत्य मंडली की महिलाओं को रेलवे स्टेशन पर कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। एक महिला ने उन्हें शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को कहा। महिलाओं को कथित तौर पर 'चिंकी', 'चीनी' और 'मोमो' जैसे अपमानजनक संबोधनों से पुकारा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसने पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव पर फिर से बहस छेड़ दी। इसी भेदभाव की कड़ी में ये सबसे नया किस्सा है। सवाल यह उठता है कि जब यह लगातार होता रहा है तो फिर आमिर शोकीन को लेकर इतना आक्रोश क्यों भड़का है, तो इसका जवाब है उसका कंटेन्ट बनाने का तरीका। **कुछ समय पूर्व भी आमिर का एक विडिओ वायरल हुआ था ,**



अहमदाबाद ले जाकर पुलिस टीम ने आमिर शोकीन से क्राइम सीन पर तहकीकात की, और किस तरह उसने इस घटना को अंजाम दिया वह पुनः जानने का प्रयास किया। मीडिआ के कैमरों के सामने वह बच्चों की दुहाई देता, गिड़गिड़ाता नजर आया ।

जहां वह एक युवती के साथ अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए , उसकी विडिओ रिकॉर्ड कर रहा था। विडिओ में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवती काफी असहज थी , लेकिन वह अपने कार्यस्थल पर विक्रेता की भूमिका में थी उसे इस व्यक्ति की हरकतों को सहन करना पड़ रहा था। खुद को सेलिब्रिटी आमिर शोकीन बताते हुए आमिर ने खुद को आमिर शोकीन बाबा बताया। उस समय भी कई सोशल मीडिआ उपयोगकर्ताओं ने आमिर की इस हरकत की मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत की थी। उस समय प्रशासन की नजरंदाजी का फायदा उठाकर इसके हौंसले बुलंद होते चले गए। इसके अपने भाई वसीम ने मीडिया को बयान देते हुए इसे इलाके का "बैड कैरेक्टर" बताया। उसने कहा कि पुलिस में कई बार इलाके के लोगों द्वारा शिकायत की गई है। उसने बताया कि पिछले 12-15 साल से वह इससे दूर रहते हैं । आमिर के कुछ अन्य विडिओ में वह महिलाओं के अंगवस्त्र पहनता हुआ , समलैंगिकों की नकल करता, समलैंगिक संबंधों का मजाक बनाता भी नजर आता है। यही कारण है जो इस बार लोगों का गुस्सा फूटा, वह इसे सलाखों तक पहुंचा गया। बड़े आईने से देखें तो आमिर समस्या का एक सिरा है। **सोशल मीडिया कमाई का एक माध्यम बन् गया है , और भारतीयों की समय बर्बादी उसके लिए कमाई का तरीका है। बेहूदा हरकतें, नस्लवाद को ट्रेंड मिलता है जिससे इन्फ्लुएन्सरों का घर चलता है। अंततः, इस घटना से सबक केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को लेना चाहिए।** स्थायी समाधान सामाजिक मानसिकता बदलने से ही आएगा। भारत की एकता केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि इस विश्वास से मजबूत होगी कि देश के किसी भी कोने से आने वाला नागरिक कहीं भी सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकता है। नस्लीय अपमान को सामान्य मजाक मानने और बनाने की प्रवृत्ति को समाप्त करना इसी दिशा में एक अनिवार्य कदम है। ●



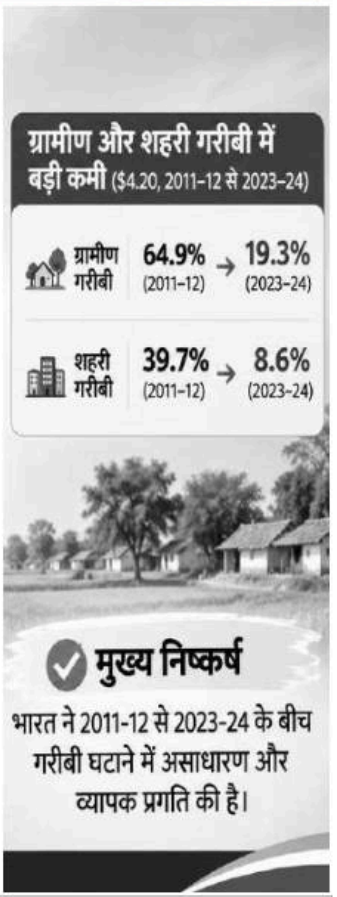
बढ़ रहा है भारत

देश में पिछले एक दशक के दौरान सामाजिक और आर्थिक विकास के कई ऐसे संकेतक सामने आए हैं जो व्यापक परिवर्तन की कहानी बयान करते हैं। नीति आयोग के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के बीच अनुमानित 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की सुविधा अगस्त 2019 के 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर मई 2026 में 15.84 करोड़ घरों तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.5 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए, जबकि आयुष्मान भारत के तहत 43 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी हो चुके हैं। बिजली तक पहुंच 2014 के 85.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 99.9 प्रतिशत हो गई। महिलाओं की श्रमबल भागीदारी भी 2017-18 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत दर्ज की गई।



● आशीर्वाद भारतीय

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में गरीबी का कम होना केवल आर्थिक आंकड़ों में सुधार की कहानी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों के जीवन में आए बदलाव, उनकी क्रयशक्ति, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जुड़ा विषय है। किसी देश की आर्थिक प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जा सकता कि उसका सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार कितना मजबूत हुआ अथवा शेयर बाजार ने कितने नए कीर्तिमान बनाए। विकास की असली कसौटी यह है कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा है। इसी संदर्भ में विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 में जारी भारत संबंधी गरीबी और समानता रिपोर्ट ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच भारत में निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। इस दौरान अनुमानित 49.6 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर आए। वहीं, अत्यधिक गरीबी का अनुपात 27.1 प्रतिशत से घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गया। पहली नजर में ये आंकड़े भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास यात्रा की एक असाधारण उपलब्धि दिखाई देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में यदि इतने बड़े पैमाने पर गरीबी में कमी आई है तो इसे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाना चाहिए। जहां एक ओर पूरा विपक्ष सरकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जन-आंदोलन, छद्म-संसद और भी विभिन्न आयोजन कर रहा है, दूसरी ओर आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार के प्रयास की वैश्विक एजेंसियों द्वारा सराहना की जा रही है। लेकिन विपक्ष द्वारा इस संबंध में सवाल जो उठाए जा रहे हैं , वह भी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न भी उतनी ही गंभी है कि क्या गरीबी के आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट का अर्थ यह है कि भारत में गरीबी समाप्त हो गई है? क्या गरीबी की परिभाषा केवल प्रतिदिन कुछ डॉलर की आय अथवा उपभोग पर आधारित हो सकती है? क्या गरीबी रेखा से ऊपर पहुंच जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति में पहुंच गया है? और क्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आय की असमानता जैसी समस्याएं भी उसी अनुपात में कम हुई हैं? इन प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना विश्व बैंक की रिपोर्ट को केवल राजनीतिक उपलब्धि या राजनीतिक प्रचार के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इस रिपोर्ट का महत्व इसी में है कि यह भारत की वास्तविक प्रगति और शेष चुनौतियों, दोनों को समझने का अवसर प्रदान करती है। यह समझना आवश्यक है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है। विश्व बैंक की 9 अक्टूबर 2026 की भारत संबंधी गरीबी और समानता रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच गरीबी में आए बदलाव का आकलन किया गया है। इसमें दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाओं का उल्लेख किया गया है। पहली है तीन डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय अत्यधिक गरीबी रेखा और दूसरी है 4.20 डॉलर प्रतिदिन की निम्न-मध्यम आय



वाले देशों की गरीबी रेखा। इन दोनों की गणना 2021 की क्रय शक्ति समानता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर की गई है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में तीन डॉलर प्रतिदिन वाली अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात 2011-12 में 27.1 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गई। इस दूसरे मापदंड के आधार पर लगभग 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर आने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में लगभग 3.5 करोड़ लोग तीन डॉलर वाली अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे थे और लगभग 23.2 करोड़ लोग 4.20 डॉलर वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार 49.6 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा अत्यधिक गरीबी की तीन डॉलर वाली रेखा के संबंध में नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत ऊंची 4.20 डॉलर वाली गरीबी रेखा के संबंध में है। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों आंकड़ों को एक ही अर्थ में प्रस्तुत करने से रिपोर्ट की वास्तविक तस्वीर बदल सकती है। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात गरीबी रेखा की परिभाषा है। सामान्य रूप से जब गरीबी की बात की जाती है तो लोग यह समझते हैं कि सरकार अथवा कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था एक निश्चित राशि तय कर देती है और उस राशि से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का आकलन इतना सरल नहीं है। विश्व बैंक ने अलग-अलग आय वर्ग के देशों के लिए अलग-अलग गरीबी मानक निर्धारित किए हैं। वर्ष 2025 में विश्व बैंक ने अपनी अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को संशोधित किया। पहले अत्यधिक गरीबी के लिए 2.15 डॉलर प्रतिदिन का मानक था, जिसे बढ़ाकर तीन डॉलर कर दिया गया। निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए 3.65 डॉलर की गरीबी रेखा को बढ़ाकर 4.20 डॉलर और उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए 6.85 डॉलर को बढ़ाकर 8.30 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। ये संशोधन 2021 की नई क्रय शक्ति समानता और विभिन्न देशों की अद्यतन राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के आधार पर किए गए। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच जीवन-यापन की वास्तविक लागत को अधिक उचित ढंग से समझना है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि विश्व बैंक कहता है कि अत्यधिक गरीबी की रेखा तीन डॉलर प्रतिदिन है तो क्या भारत में कोई व्यक्ति प्रतिदिन तीन डॉलर की राशि रुपये में परिवर्तित करके कमाता है और तभी उसे गरीबी से बाहर माना जाता है? इसका उत्तर है नहीं। यहां क्रय शक्ति समानता की भूमिका सामने आती है। उदाहरण के लिए, भारत में पांच सौ रुपये में जो सामान खरीदा जा







गरीबी में गिरावट के पीछे क्या रहा?

विश्व बैंक की रिपोर्ट में रेखांकित आर्थिक और सामाजिक कारक

01

घरेलू उपभोग में वृद्धि

परिवारों के उपभोग व्यय में विस्तार ने आर्थिक कल्याण में सुधार का संकेत दिया।

02

रोजगार का विस्तार

2017-2023 के दौरान रोजगार में 13.4 करोड़ की वृद्धि; महिलाओं की भागीदारी का विशेष योगदान।

03

सामाजिक सुरक्षा व खाद्य सहायता

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और खाद्य हस्तांतरणों ने परिवारों के जरूरी खर्च का बोझ घटाने में मदद की।

शेष चुनौती

3.5 करोड़
अब भी 3 डॉलर प्रतिदिन से नीचे

23.2 करोड़
अब भी 4.20 डॉलर प्रतिदिन से नीचे

रोजगार की गुणवत्ता
आय की स्थिरता और उत्पादकता पर आगे ध्यान जरूरी।

गरीबी रेखाएँ 2021 की क्रय शक्ति समानता पर आधारित। | स्रोत: विश्व बैंक, भारत गरीबी एवं समानता रिपोर्ट, अक्टूबर 2026.

सकता है, संभव है कि उसी सामान को अमेरिका में खरीदने के लिए दस डॉलर खर्च करने पड़ें। इसका अर्थ यह है कि दोनों देशों में एक ही मुद्रा मूल्य से समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकतीं। भारत में जीवन-यापन की लागत और अमेरिका में जीवन-यापन की लागत में अंतर है। इसलिए यदि डॉलर की वर्तमान विनिमय दर से तीन डॉलर को भारतीय रुपये में बदल दिया जाए तो उससे भारत में स्थिति का सही आकलन नहीं होगा। क्रय शक्ति समानता इस अंतर को समायोजित करने का प्रयास करती है। विश्व बैंक की अप्रैल 2026 की भारत विकास रिपोर्ट में तीन डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2021 की भारतीय कीमतों के संदर्भ में लगभग 58 रुपये प्रतिदिन के बराबर बताया गया है। इसी प्रकार 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा लगभग 82 रुपये प्रतिदिन के बराबर बताई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आज के बाजार में भारत के किसी व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 58 रुपये पर्याप्त हैं या 82 रुपये कमाने वाला व्यक्ति सामान्य अर्थों में समृद्ध हो गया है। ये 2021 की कीमतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक आंकड़े हैं। इन्हें वर्तमान विनिमय दर से परिवर्तित करके देखना तकनीकी रूप से गलत होगा। विश्व बैंक की गरीबी रेखा को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी सार्वभौमिक राष्ट्रीय न्यूनतम आय अथवा जीवनयापन की आवश्यक राशि के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह ऐतिहासिक रूप से मूलतः अंतरराष्ट्रीय तुलना का एक मापदंड है ।

विश्व बैंक का उद्देश्य यह समझना है कि अलग-अलग देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति और उपभोग क्षमता में किस प्रकार परिवर्तन आया है। अत्यधिक गरीबी की तीन डॉलर वाली रेखा उन देशों के संदर्भ में तैयार की गई है जहां बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। **4.20 डॉलर वाली रेखा निम्न-मध्यम आय वाले देशों की राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के आधार पर तैयार की गई है। चूंकि भारत इसी आय वर्ग में आता है, इसलिए विश्व बैंक के आकलन में 4.20 डॉलर का मानक विशेष महत्व रखता है।** दूसरी ओर, 8.30 डॉलर की रेखा उच्च-मध्यम आय वाले देशों के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि जैसे-जैसे कोई देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है, गरीबी को मापने के लिए केवल अत्यधिक अभाव का पैमाना पर्याप्त नहीं रह जाता। लोगों की सामाजिक आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं और जीवन की न्यूनतम स्वीकार्य गुणवत्ता का स्तर बदलता है।अब प्रश्न यह है कि भारत में गरीबी में इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई कैसे? विश्व बैंक ने इसके पीछे तीन प्रमुख कारणों को रेखांकित किया है। पहला, घरेलू उपभोग में वृद्धि; दूसरा, रोजगार में विस्तार, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी; और तीसरा, सामाजिक सुरक्षा तथा खाद्य सहायता से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों का विस्तार। इन तीनों कारकों को अलग-अलग समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गरीबी कम होने की कहानी केवल सरकारी योजनाओं की कहानी

रोजगार के साथ आय की चुनौती



13 गुना

शीर्ष 10% कामगारों की मध्य आय, निचले 10% कामगारों से लगभग 13 गुना



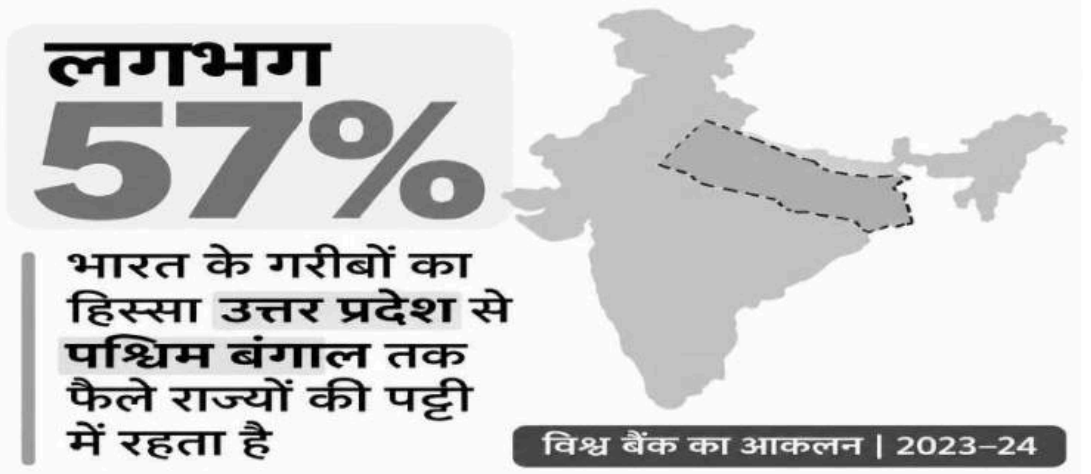
रिपोर्ट की चिंता:

रोजगार बढ़ा, लेकिन वास्तविक कमाई लगभग स्थिर रही

नहीं है और न ही इसे केवल आर्थिक विकास के एक आंकड़े से समझा जा सकता है।सबसे पहले घरेलू उपभोग की बात करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निजी उपभोग का अर्थ है कि परिवार अपनी आवश्यकताओं के लिए कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहे हैं। इसमें भोजन, कपड़े, जूते, घरेलू सामान, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से जुड़े खर्च शामिल होते हैं।जब किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो वह केवल भोजन की न्यूनतम जरूरत पूरी करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों की शिक्षा, बेहतर कपड़े, आवास की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं पर भी खर्च करने लगता है। विश्व बैंक ने अपनी भारत विकास रिपोर्ट में भी घरेलू उपभोग की वृद्धि को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में निजी उपभोग में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके पीछे घरेलू आय में वृद्धि, कम महंगाई और कर संबंधी बदलावों को भी योगदानकर्ता बताया गया। दूसरा बड़ा कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि बताया गया है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच भारत में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में लगभग 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उसी अवधि में कामकाजी आयु वर्ग की आबादी में हुई वृद्धि से लगभग दोगुनी बताई गई है। इस बदलाव में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का विशेष योगदान रहा। अधिक महिलाओं के आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने से परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी और घरेलू आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इसे भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। यहां रोजगार की संख्या और रोजगार की गुणवत्ता के बीच अंतर समझना भी जरूरी है। जब कहा जाता है कि 13.4 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि 13.4 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी या किसी बड़ी निजी कंपनी में स्थायी नियुक्ति मिली। रोजगार के आंकड़ों में स्वरोजगार, कृषि कार्य, छोटे व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र, दैनिक मजदूरी और नियमित वेतन वाले रोजगार जैसे विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई महिला अपने परिवार के कृषि व्यवसाय में काम करती है, कोई व्यक्ति छोटी दुकान चलाता है, कोई रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचता है और कोई व्यक्ति ऑनलाइन वितरण सेवा से जुड़ा है। ये सभी आर्थिक गतिविधियां रोजगार की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं, लेकिन इनकी आय, कार्यस्थल की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता अलग-अलग होती है।भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि रोजगार बढ़ने के साथ उत्पादकता और वास्तविक कमाई में पर्याप्त वृद्धि हो। अक्टूबर 2026 की विश्व बैंक रिपोर्ट ने इस संबंध में चिंता जताई है कि रोजगार में विस्तार के बावजूद वास्तविक कमाई लगभग स्थिर रही है और रोजगार वृद्धि का बड़ा हिस्सा कम उत्पादकता वाली गतिविधियों में केंद्रित रहा। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि शीर्ष 10 प्रतिशत

भारत की गरीब आबादी का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैले एक भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। इस क्षेत्र में शिक्षा, औद्योगीकरण, शहरी रोजगार, कृषि उत्पादकता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है। भारत को भविष्य में गरीबी में और तेजी से कमी लानी है तो इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देनी होगी।

गरीबी का भौगोलिक संकेंद्रण



स्रोत: World Bank, India Poverty and Equity Brief, October 2026



कामगारों की औसत मध्य आय निचले 10 प्रतिशत कामगारों की तुलना में लगभग 13 गुना थी।यह आंकड़ा दिखाता है कि रोजगार का अवसर मिलना और सम्मानजनक आय प्राप्त होना दो अलग-अलग बातें हैं। अगर किसी व्यक्ति को काम तो मिल रहा है, लेकिन उसकी मजदूरी महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ रही, तो उसकी वास्तविक क्रयशक्ति में बहुत सुधार नहीं होगा।रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं लंबे समय से कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग, स्वयं सहायता समूहों और पारिवारिक व्यवसायों में योगदान देती रही हैं। लेकिन इन गतिविधियों में उनका आर्थिक योगदान हमेशा औपचारिक रोजगार के रूप में दर्ज नहीं हो पाता था। जब महिलाओं को कृषि से बाहर छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में अवसर मिलने लगते हैं तो परिवार की आय के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। महिलाओं की अपनी आय होने से बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। गरीबी में कमी का तीसरा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार है। भारत में गरीब और कमजोर आर्थिक वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका उद्देश्य केवल सीधे आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि परिवारों के आवश्यक खर्च को कम करना भी है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय किया था। इसका सीधा प्रभाव परिवारों के भोजन पर होने वाले खर्च पर पड़ता है। यदि किसी गरीब परिवार को गेहूं और चावल खरीदने के लिए अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करना पड़ता, तो वह बची हुई राशि का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा, दवाइयों, कपड़ों और अन्य जरूरतों के लिए कर सकता है। खाद्य सुरक्षा का यह योगदान गरीबी कम करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने भी गरीबी घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को निर्धारित शर्तों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाती थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के अभाव वाले समय में परिवारों को आय का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया। इससे ग्रामीण मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला और पलायन के दबाव को कम करने में सहायता मिली। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता मजदूरी के समय पर भुगतान, पर्याप्त काम की उपलब्धता, पारदर्शिता और तैयार की गई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर रही। इसी प्रकार प्रधानमंत्री

पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भी गरीबी की बहुआयामी तस्वीर को प्रभावित करती हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाना है। इससे लकड़ी, उपले और अन्य पारंपरिक ईंधन जलाने से उत्पन्न धुएं के संपर्क में कमी आई है।



प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (2018)

आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। एक गरीब परिवार के लिए सुरक्षित आवास केवल छत का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ा है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती संबंधी उपचार के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन भी इसी व्यापक विकास दृष्टिकोण का हिस्सा है। ग्रामीण परिवारों को घर तक नल से पानी उपलब्ध कराना विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। पानी लाने में लगने वाला समय बचने से शिक्षा, रोजगार और अन्य गतिविधियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। गरीबी के भौगोलिक वितरण पर ध्यान दें तो तस्वीर का एक दूसरा पक्ष सामने आता है। विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी में गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में दर्ज की गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर अभी भी अधिक है। 2023-24 में 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का अनुपात 19.3 प्रतिशत था, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.6 प्रतिशत था। अत्यधिक गरीबी की तीन डॉलर वाली रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी 3.1 प्रतिशत और शहरी आबादी 1.4 प्रतिशत थी। यह अंतर बताता है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचने के बावजूद ग्रामीण भारत में गरीबी की चुनौती अधिक गहरी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार आज भी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। कृषि की आय मौसम, मानसून, सिंचाई, बाजार भाव, फसल लागत और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होती है। किसी वर्ष अच्छी फसल होने पर किसान की आय में सुधार हो सकता है, लेकिन अगले वर्ष सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या फसल की कीमत में गिरावट से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। खेती में काम करने वाले बहुत से लोगों के पास सीमित भूमि है और अनेक परिवार भूमिहीन मजदूरी पर निर्भर हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार तो उपलब्ध है, लेकिन कई बार काम मौसमी होता है और मजदूरी से परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पातीं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों, नियमित वेतन वाले रोजगार और कौशल आधारित गैर-कृषि कार्यों के अवसर अभी भी सीमित हैं। इसलिए गरीबी कम करने के लिए केवल कृषि सहायता पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, लघु उद्यम और स्थानीय सेवा क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस उपलब्धि का महत्व है। दुनिया के कई देशों में अत्यधिक गरीबी घटाने की प्रक्रिया धीमी हुई है और कुछ क्षेत्रों में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट तथा आर्थिक अस्थिरता ने गरीबी की समस्या को और गंभीर बनाया है। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल देश में गरीबी का अनुपात तेजी से कम होना महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की तुलना केवल उन देशों से नहीं होनी चाहिए जहां गरीबी का स्तर अत्यधिक है। भारत को अपनी तुलना उन अर्थव्यवस्थाओं से भी करनी चाहिए जिन्होंने आर्थिक विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और उत्पादक रोजगार में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। लक्ष्य केवल अत्यधिक गरीबी कम करना नहीं, बल्कि नागरिकों को मध्यम आय और आर्थिक सुरक्षा की स्थिति तक पहुंचाना भी होना चाहिए, यह नेताओं के साथ साथ



पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते पीएम मोदी (2021)

भारत को यह भी समझना होगा । गरीबी और असमानता एक-दूसरे से संबंधित होने के बावजूद अलग-अलग समस्याएं हैं। गरीबी का अर्थ है कि व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी करने की क्षमता पर्याप्त नहीं है, जबकि असमानता का संबंध समाज में संसाधनों, आय और अवसरों के वितरण से है। संभव है कि किसी देश में गरीबी का अनुपात तेजी से घटे, लेकिन उसी समय उच्च आय वाले और निम्न आय वाले लोगों के बीच अंतर बना रहे। इसलिए गरीबी में कमी को आर्थिक समानता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन विकास का बड़ा हिस्सा सीमित वर्गों के हाथों में केंद्रित हो रहा है तो सामाजिक असंतोष और अवसरों की असमानता की समस्या बनी रह सकती है।भारत को आने वाले वर्षों में अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तीन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ाना होगा। पहली प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक रोजगार की होनी चाहिए, ताकि काम करने वाले लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि हो। दूसरी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना होनी चाहिए। तीसरी प्राथमिकता उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होना चाहिए जहां गरीबी अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। गरीबी का स्वरूप हर राज्य और जिले में एक जैसा नहीं होता। कहीं कृषि संकट प्रमुख है, कहीं औद्योगिक रोजगार की कमी है, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कमजोर हैं और कहीं शहरी गरीबों के सामने आवास तथा जीवनयापन की लागत बड़ी चुनौती है। इसलिए सभी क्षेत्रों के लिए एक ही नीति पर्याप्त नहीं हो सकती।शहरी गरीबी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से यह धारणा बन जाती है कि शहरों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं, इसलिए वहां गरीबी कम होती है। लेकिन शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों, घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों, छोटे दुकानदारों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी अस्थिर हो सकती है। महानगरों में मकान का किराया, परिवहन, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च ग्रामीण इलाकों की तुलना में अधिक हो सकता है। इसलिए केवल आय के आधार पर शहरों के गरीब परिवारों की समस्याओं का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। शहरी रोजगार की स्थिरता, किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबी उन्मूलन की नीति का हिस्सा बनाना होगा देश ने गरीबी कम करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य अभी हमारे देशवासियों की आशानुसार पूरा नहीं हुआ है।

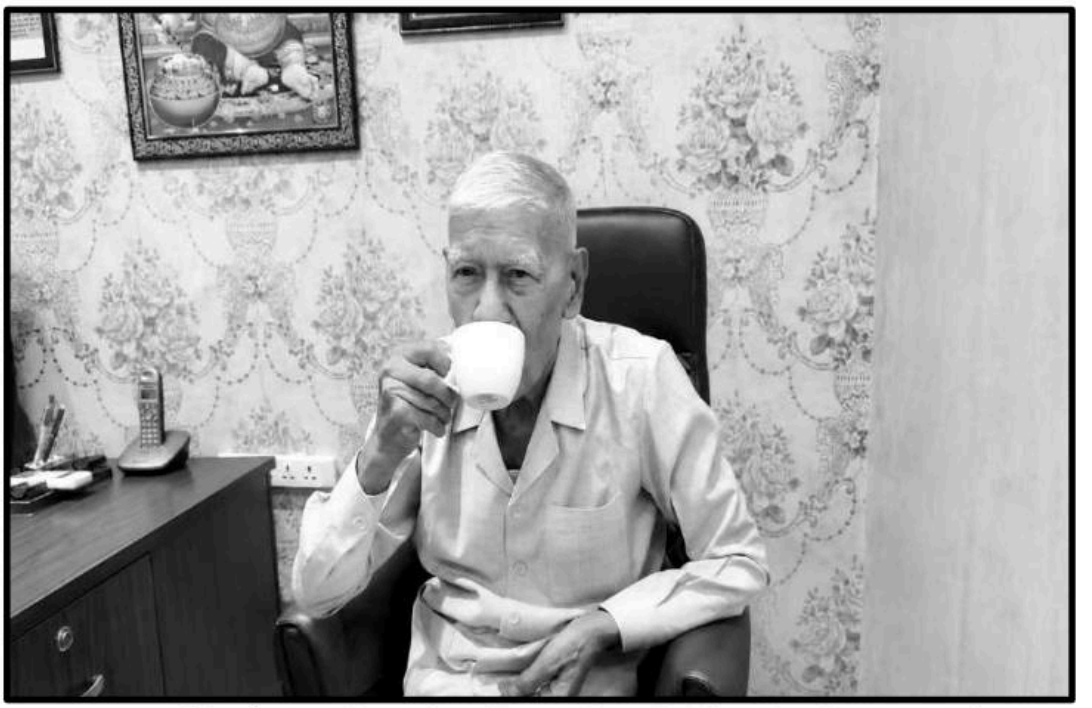
भारत को अब अत्यधिक गरीबी से लड़ने के साथ-साथ आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं पर भी निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। देश को भारत की सरकार से बेहद उम्मीदें हैं। मोदी सरकार ने लगातार देश की आर्थिकई को सुरक्षित करने का कार्य किया है। लेकिन उम्मीद पर लगातार खड़ा उतरना भी एक बड़ी चुनौती है।

गरीबी के आंकड़ों में गिरावट निश्चित रूप से उत्साहजनक है, लेकिन असली सफलता उस दिन होगी जब किसी गरीब परिवार को भोजन, शिक्षा, इलाज, आवास और रोजगार के लिए असहाय होकर दूसरों की ओर न देखना पड़े। भारत ने गरीबी के विरुद्ध लंबी लड़ाई में महत्वपूर्ण दूरी तय की है। अब चुनौती यह है कि इस प्रगति को स्थायी, समावेशी और समान अवसरों पर आधारित विकास में बदला जाए। गरीबी कम होना उपलब्धि है, गरीबी से स्थायी मुक्ति सुनिश्चित करना असली विकास है।●

चाय पर चर्चा

उद्योगपति आर.एस. चौहान के व्यक्तित्व, विचारों और जीवन दर्शन की खास झलक

नर्मल और श्रेया के संस्थापक आर.एस. चौहान से खास मुलाकात, जहां व्यापार के साथ संस्कार, सादगी और जीवन की सच्चाइयों पर हुई दिलचस्प चर्चा।



'चाय पर चर्चा' के दौरान अपने कार्यालय में चाय की चुस्की लेते उद्योगपति आर.एस. चौहान

● मदर इंडिया डेस्क

चाय की चुस्कियों के साथ जब अनुभवों, विचारों और जिंदगी के फलसफों पर बातचीत होती है, तो चर्चा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। कुछ ऐसा ही खास माहौल देखने को मिला 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम में, जहां प्रसिद्ध उद्योगपति और नर्मल एवं श्रेया के संस्थापक श्री आर.एस. चौहान से मुलाकात हुई। व्यापार जगत में अपनी अलग पहचान रखने वाले आर.एस. चौहान को लोग सम्मानपूर्वक 'चौहान साहब' के नाम से पुकारते हैं। उनका व्यक्तित्व उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं अधिक व्यापक है। मृदुभाषी स्वभाव, सहयोग की भावना, उदार हृदय और सादगीपूर्ण जीवनशैली उनकी पहचान है। उन्होंने अपने व्यापार को केवल कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और प्रतिष्ठा से जुड़ी एक जिम्मेदारी के रूप में देखा है।



आर.एस. चौहान, संस्थापक, नर्मल एवं श्रेया

चौहान साहब की पंक्तियां

आए, आकर चले गए, जो दुनिया के आली थे,
जब गए सिकंदर हिंद से, तो दोनों हाथ खाली थे।
आया है सो जाएगा, क्या राजा, रंक, फकीर,
विधि का विधान है ये, कह गए संत कबीर।

— आर.एस. चौहान

मेहनत और दूरदर्शिता

एक सच्चे राजपूत के रूप में चौहान साहब ने व्यापार की दुनिया को अपना कर्मक्षेत्र और संघर्ष का मैदान माना। लगातार परिश्रम और दूरदर्शी सोच के बल पर उन्होंने न केवल अपने प्रतिष्ठानों का विस्तार किया, बल्कि समाज और व्यापार जगत में अपनी विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा भी स्थापित की। नर्मल और श्रेया जैसे प्रतिष्ठानों के माध्यम से उनकी व्यावसायिक यात्रा उनके संकल्प और मेहनत की कहानी बयां करती है।**चौहान साहब के व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि तमाम उपलब्धियों और सम्मान के बावजूद उनके व्यवहार में कोई बनावट दिखाई नहीं देती।** वे आज भी आम लोगों के बीच सहजता से मिलते हैं और सभी के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भाव रखते हैं। उनके जीवन में जहां मां लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि दिखाई देती है, वहीं मां सरस्वती के प्रति सम्मान, संस्कार और ज्ञान की महत्ता भी उनके विचारों में झलकती है।

जीवन की नश्वरता पर विचार

कार्यक्रम के दौरान नेशनल टीवी चैनल एचडी संगम के दिल्ली स्टेट न्यूज़ हेड श्री ललित 'सुमन' जी के साथ बातचीत में चौहान साहब ने जीवन की नश्वरता और इंसान के वास्तविक उद्देश्य पर कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने विचारों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने समझाया कि **दुनिया में धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव सब कुछ अस्थायी है।** इतिहास के महान विजेता सिकंदर भी जब इस संसार से विदा हुए, तो अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके। ऐसे में इंसान को अपने जीवन में अहंकार और दिखावे के बजाय अच्छे कर्मों, विनम्रता और इंसानियत को महत्व देना चाहिए।

संत कबीर के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह संदेश भी दिया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। राजा हो या रंक, हर किसी को एक दिन इस संसार से विदा होना है। **इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम करना चाहिए, जिससे जाने के बाद भी लोग इंसान को उसके अच्छे व्यवहार और कर्मों के लिए याद रखें।**

'चाय पर चर्चा' की यह मुलाकात केवल एक उद्योगपति की सफलता की कहानी नहीं रही, बल्कि इसने जीवन के उन मूल्यों को भी सामने रखा, जिन्हें अक्सर दौलत और शोहरत की दौड़ में भुला दिया जाता है।

आर.एस. चौहान का जीवन और उनके विचार यही संदेश देते हैं कि **असली सफलता केवल बड़ा कारोबार खड़ा करने में नहीं, बल्कि बड़ा दिल रखने, अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज में सम्मान के साथ जीने में है।**●

"असली सफलता केवल बड़ा कारोबार खड़ा करने में नहीं, बल्कि बड़ा दिल रखने, अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज में सम्मान के साथ जीने में है।"

पेंशन के नाम पर साइबर ठगी बुजुर्गों की जीवनभर की कमाई पर डिजिटल अपराधियों का हमला!

84 वर्षीय सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी से जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के बहाने 4.5 लाख रुपये की ठगी, बैंक अधिकारी बनकर ठगों ने जीता भरोसा

● मदर इंडिया डेस्क

पेंशन किसी व्यक्ति के लिए केवल हर महीने बैंक खाते में आने वाली रकम नहीं होती, बल्कि यह उसके जीवनभर के परिश्रम और बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक होती है। **लेकिन जब इसी पेंशन को जारी रखने की औपचारिकता साइबर अपराधियों के लिए ठगी का हथियार बन जाए, तो यह हमारी डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।**



बचाव के उपाय | ठगी हो तो तुरंत 1930

ओटीपी व पिन: किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी या यूपीआई पिन साझा न करें, पैसे पाने के लिए कभी पिन दर्ज न करें।

लिंक व ऐप: जीवन प्रमाणपत्र के नाम पर आए संदिग्ध लिंक न खोलें, एपीके फाइल या अनजान ऐप इंस्टॉल न करें।

पहचान: बैंक अधिकारी होने का दावा करने वाले की पहचान बैंक के आधिकारिक माध्यम से जांचें।

ठगी हो जाए तो: तुरंत 1930 पर कॉल करें, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें और बैंक को सूचना दें।

फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लगाया चूना

पुणे के कोंढवा क्षेत्र में रहने वाले 84 वर्षीय सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी को 8 और 9 अक्टूबर 2026 को अज्ञात व्यक्तियों ने फोन किया और खुद को एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का अधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी है और व्हाट्सऐप पर लिंक या फाइल भेजकर प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया।

ठगों ने झांसे को विश्वसनीय बनाने के लिए वीडियो कॉल भी की, जिसमें बैंक का लोगो दिखाई दे रहा था। इसके बाद पीड़ित से बैंक संबंधी जानकारी भरवाई गई और मोबाइल पर आया ओटीपी साझा करवा लिया गया। **कुछ समय बाद खाते से 4.5 लाख रुपये निकाले जाने का संदेश आया।** 23 अक्टूबर 2026 को कोंढवा पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।

जीवन प्रमाणपत्र बना नया हथियार

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अपराधियों ने किसी लालच का नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता का सहारा लिया। पेंशन रुकने के डर और बैंक पर भरोसे का ठगों ने पूरा फायदा उठाया।

सरकार की 'जीवन प्रमाण' सुविधा में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से डिजिटल प्रमाणपत्र बनता है। इसके लिए केवल बैंक शाखा, सरकारी कार्यालय, जन सेवा केंद्र या आधिकारिक डिजिटल माध्यमों की ही मदद लें।

बैंक और प्रशासन की भी जिम्मेदारी

केवल नागरिकों को सावधान रहने की सलाह देना काफी नहीं है। बैंकों को शाखाओं में बुजुर्गों को सही प्रक्रिया समझानी चाहिए, संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत कार्रवाई की व्यवस्था बनानी चाहिए और शिकायत करने वाले को एक सरल शिकायत निवारण व्यवस्था मिलनी चाहिए।

बुजुर्गों के लिए विशेष संदेश

बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाला हर व्यक्ति बैंक अधिकारी नहीं होता। अगर थोड़ा भी शक हो तो अपनी युवा पीढ़ी से मदद लें। आपको जीवन का तजुर्बा इन ठगों से कहीं ज्यादा है, इस ज्ञान का उपयोग करें। **आपकी एक छोटी-सी सावधानी जीवनभर की कमाई बचा सकती है।●**

कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट

दूसरे को नसीहत, खुद पालन नहीं ?

व्हाट्सऐप पर घूम रहा एसोसिएशन का नोटिस

अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना एवं आवश्यक एडवाइजरी
समस्त मार्केट सदस्यों के लिए

प्रिय मार्केट सदस्यों,

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार द्वारा GRAP (Graded Response Action Plan) लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।

इसी क्रम में हाल ही में DC (Deputy Commissioner) महोदया का मार्केट में दौरा हुआ, जिसके दौरान अधिकारियों द्वारा मौके पर ही नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान किए गए। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रशासन अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मार्केट में अतिक्रमण (Encroachment) को लेकर भी सरकार एवं प्रशासन बेहद सख्त हैं। दुकानों के बाहर सड़क, फुटपाथ, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सामान रखना, रास्तों को बाधित करना अथवा किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करना अब गंभीर कार्रवाई का कारण बन सकता है। प्रशासन द्वारा ऐसे अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ चालान एवं अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

विशेष रूप से CNC एवं आरा मशीन (Saw mill) संचालकों तथा अतिक्रमण करने वाले सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस एडवाइजरी को अत्यंत गंभीरता से लें।

सभी सदस्यों से निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखने की अपील की जाती है:

1. GRAP के अंतर्गत लागू सभी सरकारी दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें।
2. CNC एवं Saw mill संचालक अपनी मशीनों के संचालन से संबंधित वर्तमान सरकारी अनुमति एवं प्रतिबंधों की स्थिति अवश्य जांच लें।
3. दुकानों के बाहर किसी भी प्रकार का सामान, लकड़ी, माल या अन्य सामग्री रखकर सड़क, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण न करें।
4. अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान की निर्धारित सीमा के अंदर ही व्यापारिक गतिविधियां संचालित करें।
5. किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न करें जो प्रदूषण नियंत्रण अथवा अतिक्रमण संबंधी सरकारी नियमों का उल्लंघन करती हो।
6. प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज एवं अनुमति पत्र उपलब्ध रखें।
7. अपने कर्मचारियों एवं स्टाफ को भी इन सभी दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक करें।

सभी सदस्यों से विशेष अपील है कि इसे सामान्य सूचना न समझें।

प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ रही है। मौके पर चालान एवं अन्य कानूनी कार्रवाई होने की स्थिति में संबंधित व्यापारी को आर्थिक नुकसान एवं अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

मार्केट एसोसिएशन सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सरकारी नियमों का पालन करें, मार्केट में व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी सदस्य को अनावश्यक परेशानी एवं नुकसान से बचाएं।

कृपया स्वयं भी सतर्क रहें और अपने आसपास के व्यापारियों को भी जागरूक करें। प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय समय रहते सभी आवश्यक सुधार कर लें।

आपका सहयोग ही मार्केट की सुरक्षा, सम्मान एवं सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

Team KNTFDA

एसोसिएशन का दोहरा रवैया







दुकान के आगे सड़क पर रखे लकड़ी के तख्ते और ढेर (मदर इंडिया को मिली तस्वीरें)

● विशेष संवाददाता

कीर्ति नगर टिम्बर मार्केट में इन दिनों एसोसिएशन का एक नोटिस व्हाट्सऐप पर तेजी से घूम रहा है। इसमें सदस्यों को चेताया गया है कि ग्रैप लागू होने के बीच डीसी महोदया के दौरे में मौके पर चालान हुए हैं और दुकानों के बाहर सड़क, फुटपाथ या गलियों में माल रखना अब गंभीर कार्रवाई का कारण बन सकता है। **लेकिन मार्केट की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। आरोप है कि न्यू टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के महासचिव ने अपनी ही दुकान के आगे सरकारी सड़क की लगभग 250 गज जगह पर लकड़ी का माल रखकर कब्जा कर रखा है।** मदर इंडिया को मिली तस्वीरों में दुकान के आगे सड़क पर लकड़ी के ऊंचे ढेर और दीवार से टिकाकर रखे तख्ते साफ दिखाई देते हैं, जिनसे रास्ता संकरा हो गया है।

नियम सबके लिए बराबर हों

सवाल यह है कि जब एसोसिएशन खुद सदस्यों को 'निर्धारित सीमा के अंदर ही' कारोबार करने की हिदायत दे रही है, तो क्या पदाधिकारियों को पहले उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? छोटे दुकानदारों पर चालान का डर और पदाधिकारियों के लिए छूट, ऐसा दोहरा रवैया किसी भी बाजार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर 2 नवंबर से ग्रैप का दूसरा चरण लागू है। सड़क पर रखा माल न केवल यातायात रोकता है, बल्कि आपात स्थिति में दमकल और एंबुलेंस के रास्ते में भी बाधा बन सकता है।

प्रशासन करे निष्पक्ष जांच

प्रशासन को मौके की पैमाइश कर तथ्यों की जांच करनी चाहिए और नियम तोड़ने वालों पर, पद चाहे जो भी हो, समान कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर महासचिव का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।●



Army Equestrian Centre में Royal Koas पोलो कप-2026 का भव्य आयोजन

रतिंदर पाल सिंह भाटिया (रोम्पी भाटिया) की मेजबानी में सजा पोलो का शाही मंच
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ियों ने दिखाया प्रतिभा का जलवा

● खेल डेस्क

नई दिल्ली स्थित आर्मी एक्वेस्टेरियन सेंटर में 1 नवंबर 2026 को एम्पायर सेफ कंपनी के द्वारा रॉयल कोस पोलो कप का भव्य आयोजन किया गया। **इस विशेष आयोजन की मेजबानी रतिंदर पाल सिंह भाटिया (रोम्पी) ने की। वहीं रॉयल कोस फर्नीचर के एमडी जतिन भाटिया और क्रिएटिव डाइरेक्टर जयवीर भाटिया ने अहम भूमिका निभाई।** कार्यक्रम में राजनीति, सामाजिक और व्यावसायिक जगत से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की।इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना की विशेष उपस्थिति रही।

परंपरा और खेल भावना का संगम

रॉयल कोस पोलो कप ने राजधानी में पोलो खेल की समृद्ध परंपरा और घुड़सवारी संस्कृति को एक विशेष मंच प्रदान किया। तेज रफ्तार घोड़ों, खिलाड़ियों के शानदार तालमेल और मैदान पर रोमांचक प्रतिस्पर्धा ने आयोजन को आकर्षक बना दिया। **पोलो केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता, टीम भावना और उत्कृष्ट घुड़सवारी कौशल का अद्भुत संगम है।** इस खेल की ऐतिहासिक और शाही विरासत और अंतरराष्ट्रीय महत्व ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। पोलो दुनिया के प्रतिष्ठित घुड़सवारी खेलों में से एक है। इसमें खिलाड़ी की एकाग्रता,घोड़े के साथ तालमेल, संतुलन और टीम के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। **भारत में पोलो का इतिहास काफी समृद्ध रहा है और यह खेल देश की घुड़सवारी तथा सैन्य परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है।** ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को इस विरासत से परिचित कराने और खेल के प्रति

रुचि विकसित करने का अवसर मिलता है। पोलो का भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध रहा है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय पोलो खेल की जड़ें मणिपुर के पारंपरिक खेल 'सगोल कंगजेई' में मानी जाती हैं, जिसे सदियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है। मणिपुरी भाषा में 'सगोल' का अर्थ घोड़ा और 'कंगजेई' का अर्थ खेल में इस्तेमाल होने वाली छड़ी से है। इस खेल में पारंपरिक रूप से मणिपुरी टट्टुओं का इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं शताब्दी में असम के सिलचर क्षेत्र में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पारंपरिक खेल में रुचि दिखाई। वर्ष 1859 में ब्रिटिश अधिकारियों रॉबर्ट स्टीवर्ट और जोसेफ शेरर ने सिलचर में एक यूरोपीय पोलो क्लब की स्थापना की, जबकि वर्ष 1862 में कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना हुई, जिसे दुनिया के सबसे पुराने मौजूदा पोलो क्लब के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1880 में प्रतिष्ठित एजरा कप की शुरुआत हुई, जिसे दुनिया की पहली पोलो ट्रॉफी माना जाता है। इसके बाद वर्ष 1892 में भारतीय पोलो संघ की स्थापना ने देश में इस खेल को संगठित और संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। जयपुर, जोधपुर, पटियाला, हैदराबाद और बीकानेर जैसी रियासतें पोलो के प्रमुख केंद्र बनकर उभरीं, जहां राजघरानों ने इस खेल को संरक्षण दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने पोलो की परंपरा को संरक्षित करने, जीवित रखने और इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

20 साल के जुड़ाव को मिला सम्मान

रॉयल कोस के मेनेजिंग डाइरेक्टर जतिन भाटिया ने बताया कि एम्पायर सेफ कंपनी द्वारा द्वारा पोलो की इसी विशेषता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। भारतीय पोलो एसोसिएशन ने इक्वेस्ट्रीयन के साथ उनके परिवार के 20 साल से अधिक के संबंध को देखते हुए यह जिम्मेदारी रॉयल कोस को दी। उन्होंने इस आयोजन को अपने परिवार और रॉयल कोस व एम्पायर सेफ कंपनी के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह हमें दो चीजों को जोड़ने की भी अनुमति देता है जो हमारे दिल के नजदीक हैं: हमारा पारिवारिक व्यवसाय और हमारा पसंदीदा खेल। हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और अपने समुदायों और हितों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश के विभिन्न संगठनों ने भी इस कप में अपनी रुचि दिखाई। क्वारी , ओ3+, डेनवर , पैट्रन टकिला, सिंबा, सिर्फ जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडस ने इस प्रतियोगिता को अपनी स्पॉन्सरशिप प्रदान किए।



भूटानी इंफ्रा अचीवर्स के सिर सजा रॉयल कोस कप का ताज टीम के लाजवाब प्रदर्शन ने दर्शकों का जीता दिल

सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक हरीश खुराना की रही विशेष उपस्थिति

कार्यक्रम में सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक हरीश खुराना की मौजूदगी ने आयोजन को विशेष पहचान दी। दोनों अतिथियों ने इस खेल आयोजन में भाग लेकर खिलाड़ियों और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। अपने सन्देश में अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने के साथ-साथ पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने सरदार रतिन्दर पाल सिंह भाटिया का इस भव्य आयोजन और खेलों को दिए प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद भी किया ।

भूटानी इंफ्रा अचीवर्स ने मारी बाज़ी

पहले रॉयल कोस कप प्रतिस्पर्धा में बाजी मारने वाली टीम भूटानी इंफ्रा अचीवर्स रही, जिसने लगातार अपने प्रदर्शन से दर्शकों में जीत का जोश बनाए रहा। टीम में युवा और वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय टैलेंट का सही तालमेल देखने को मिला। आर्मी एक्वेस्टेरियन सेंटर में 1000 से अधिक दर्शकों ने टीम के सफल प्रदर्शन का आनंद लिया। ●





फ़िल्म

हॉलीवुड में विद्युत जामवाल की दहाड़!

● फिल्म डेस्क

भारतीय सिनेमा में जब भी वास्तविक एक्शन और मार्शल आर्ट्स की बात होती है, विद्युत जामवाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अपने खतरनाक स्टंट, शारीरिक नियंत्रण और कलरिपयट्टु जैसी पारंपरिक भारतीय युद्ध कला में महारत के लिए पहचाने जाने वाले विद्युत ने अब हॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रख दिया है। उनकी फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में वह धालसिम के लोकप्रिय किरदार में नजर आए, जो दुनिया भर में मशहूर वीडियो गेम फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा रहा है।

विद्युत के लिए यह सिर्फ एक विदेशी फिल्म में काम करने का अवसर नहीं था, बल्कि एक ऐसे किरदार को निभाने का मौका था, जिसकी पहचान योग, शारीरिक लचीलेपन और असाधारण युद्ध कौशल से जुड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि धालसिम की दुनिया और विद्युत की वास्तविक मार्शल आर्ट्स पृष्ठभूमि के बीच काफी समानता दिखाई देती है।'स्ट्रीट फाइटर' की दुनिया में धालसिम एक भारतीय योगी योद्धा है। वह अपनी सांसों, योग और असाधारण शारीरिक क्षमता को लड़ाई का हथियार बनाता है।विद्युत जामवाल के लिए यह भूमिका इसलिए भी खास रही, क्योंकि वह स्वयं वर्षों से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते आए हैं। केरल से निकली पारंपरिक युद्ध कला कलरिपयट्टु में उनका प्रशिक्षण उनके एक्शन अंदाज को दूसरी पहचान देता है। ऐसे में धालसिम का किरदार निभाना उनके लिए अपनी वास्तविक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर था।फिल्म में विद्युत का लुक भी गेम के मूल किरदार के काफी करीब रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म में भारतीय किरदार को केवल मजाक या सतही पहचान तक सीमित रखने के बजाय उसे एक वास्तविक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

फिल्म को लेकर अंतरराष्ट्रीय और भारतीय फिल्म समीक्षकों की राय मिली-जुली रही है। जहां कुछ समीक्षकों ने इसकी रंगीन दुनिया, वीडियो गेम जैसे किरदारों और एक्शन दृश्यों की तारीफ की, वहीं कई ने कमजोर कहानी, तेज एडिटिंग और जरूरत से ज्यादा किरदारों को इसकी कमियां बताया। विद्युत जामवाल के प्रदर्शन को लेकर भी समीक्षाओं में सकारात्मक बातें सामने आई हैं। उनकी एक्शन क्षमता और धालसिम के रूप में उपयुक्तता को सराहा गया। कुछ समीक्षकों ने उन्हें फिल्म के उन कलाकारों में शामिल किया, जिन्हें पर्दे पर और अधिक समय मिलना चाहिए था। यही



इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी चर्चा भी है। विद्युत जैसे कलाकार, जिनकी पहचान ही उनके वास्तविक एक्शन कौशल से है, उन्हें अगर ज्यादा मुकाबले और विस्तृत कहानी मिलती, तो उनका प्रदर्शन और प्रभावशाली हो सकता था। किताओ सकुराई के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1993 की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है। कहानी रयू और केन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक बड़े फाइटिंग टूर्नामेंट में दोबारा एक साथ आना पड़ता है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वीडियो गेम की मूल पहचान को बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में इतने सारे लोकप्रिय किरदार होने के कारण कुछ पात्रों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। रयू, केन और चुन-ली की कहानी मुख्य रूप से आगे बढ़ती है और बाकी योद्धाओं को अपेक्षित गहराई नहीं मिलती। इसी वजह से धालसिम का किरदार भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रह जाता है।विद्युत जामवाल के हॉलीवुड पदार्पण का महत्व महत्व यह है कि उन्होंने अपनी पहचान और भारतीय मार्शल आर्ट्स की पृष्ठभूमि के साथ अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत में जगह बनाई है। विद्युत ने खुद भी उम्मीद जताई है कि 'स्ट्रीट फाइटर' एक बड़ी फ्रेंचाइजी बने और आने वाले समय में इसका अगला भाग भी दर्शकों तक पहुंचे।फिल्म के अंत में आगे की कहानी के लिए संभावनाएं छोड़ी गई हैं। हालांकि, अभी किसी सीक्वल या उसमें विद्युत की वापसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ,लेकिन अगर फ्रेंचाइजी आगे बढ़ती है तो धालसिम के किरदार को विस्तार देने का शानदार अवसर होगा।

दर्शक धालसिम की पृष्ठभूमि, उसके योग अभ्यास, भारतीय संस्कृति से उसके जुड़ाव और उसकी अनोखी युद्ध शैली को अधिक विस्तार से देखना चाहेंगे। खास तौर पर विद्युत की वास्तविक मार्शल आर्ट्स क्षमता को देखते हुए उनके लिए ऐसे एक्शन दृश्य तैयार किए जा सकते हैं, जो इस किरदार को फ्रेंचाइजी के सबसे यादगार योद्धाओं में शामिल कर दें।'स्ट्रीट फाइटर' विद्युत जामवाल के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। फिल्म को कहानी और किरदारों के संतुलन को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन विद्युत की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी ने भारतीय दर्शकों के बीच एक नई चर्चा जरूर शुरू की है।

धालसिम के रूप में विद्युत की यह शुरुआत भले ही उनकी पूरी क्षमता को सामने नहीं ला पाई हो, लेकिन इसने उनके लिए नए रास्ते जरूर खोले हैं। अब उम्मीद यही है कि आने वाले समय में उन्हें ऐसे बड़े किरदार मिलें, जिनमें अभिनय के साथ-साथ उनकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को भी पूरा मंच मिले। विद्युत ने हॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या अगली बार उन्हें केवल कुछ यादगार एक्शन दृश्यों तक सीमित रखा जाएगा या धालसिम के रूप में वह इस फ्रेंचाइजी के प्रमुख चेहरों में अपनी जगह बना पाएंगे? भारतीय दर्शकों को इसका इंतजार जरूर रहेगा। ●

छोटा सा नुकसान !

● व्यंग्य डेस्क

हाल ही में व्यंगकार केदारनाथ की यात्रा कर कर आया । मिल के बोलिए बाबा केदार की जय ! अब करते हैं व्यंग्य की शुरुआत। शुरुआत में एक नयी शुरुआत के प्रयास की बात करते हैं। अपने आंदोलनकारी 3 कॉकरोच फिर मंत्र-यंत्र करने आए, धरे गए, लक्ष्मनरेखा से बांधे गए, अब घर बैठे हैं। उनके जर्मन साठी लंदन में नारे लगाने में व्यस्त रहे, तो इधर हम देखने में कि कौन-किसको-कैसे व्यस्त करता है ? बात व्यस्त करने की करें, तो आज कल पुलिस बेहद व्यस्त है। पहले प्रदर्शनकारी ,फिर नेता, फिर पुलिसकर्मी खुद। वह भी हमारी मांगे पूरी करो के सदाबहार नारे के साथ । मांग भी यह है कि पूरी भारतीय व्यवस्था में 2 ही हमपर भारी है , एक सफेदपोश और दूसरे जो पहनते हैं काला कोट। बाहर हम उनको ठोंकते हैं, तो वो कोर्ट में घेर लेते हैं। घेर लेते हैं तो दोगुना घेरते हैं , कानूनी भी और कानून के बाहर भी। हम आलाकमान के आदेश पर कॉकरोच धरें, उन्हें पकड़ें, गाड़ी में घुसाये शहर घुमाएँ, अंदर करें ! और ये काले लिबास वाले अंत में आयें और फिर सारा क्रेडिट लेकर सोशल मीडिया में हीरो बनें। चित भी इनकी , पट भी इनकी। मतलब बाजी जिधर भी हो बाजीगर यही हैं। लेकिन यह तो कुछ नहीं है , व्यंगकार की मानें तो सबसे बड़े बाजीगर अपने किसन बाबू हैं। पता नहीं अचानक से कैसा तूफान आया, पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। वह भी ऐसे छाए कि अपने ही डायलॉग के गाने बनवा कर बलिवुडिया रैपरों ,को टॉफी के रैपर जैसा उड़ा दिया। सवाल भी अच्छा पूछा ," नाम या दाम ?" यही सवाल श्रीमान डोलन्द भी पूछ रहे हैं। चुनाव हर नेता का सरदर्द है। कुछ साल पहले तक दिल्ली का, अब वाशिंगटन का। लेकिन इस सवाल का सबसे सही जवाब जिसने दिया है, उनका



नाम है , श्रीमान मेलन। मेलन भाईसाहब का नाम भी है , और दाम भी है । उनकी गाड़ी हवा में उड़ती है , और उनका रॉकेट धरती पर खुद वापिस भी आ जाता है। उनकी गाड़ी में पंख और बिस्तर में पंखा लगा है , और चड्डी में ए-आई। बस अफसोस इतना है अपने देसी धनकुबेर बंबानी जी के सामने उनका दम फूलने लगता है। भारत सरकार भी सुनने को राजी नहीं ! न नाम चल रहा , न दाम चल रहा और सिक्के की तो पूछो मत ! यहाँ अशोक चिह्न वाला सिक्का चलता है , असली धातु वाला! आप मेलन रहे हैं या बेलन रहे हैं! अगर आपका सिक्का है खोटा! तो लट्ठ पड़ेगा मोटा! भूल से हाथ वाले राजकुमार के पाले में गए , आपको व्यस्त करने के काम में पूरा प्रशासन व्यस्त हो जाएगा। और होर्ज बोरोस की तर्ज पर आपके द्वारा किस तरह देश के खिलाफ टूल किट, बिस्किट और कैट-किट चलाई जा रही है , उसका बखान करने की नई शुरुआत हो जाएगी। मेरा आजकल बड़ा मन करता है कि व्यंग खुद न लिख कर ए-आई से लिखवाऊँ, लेकिन जब भी ऐसे ख्याल मेरे मस्तिष्क में आते हैं तो मेरी माई के शब्द कान में गूँजते हैं " इसके लिए तुम दुनिया का पानी बर्बाद करोगे ?" अरे मेरी मां , मेरे दिमाग का पानी भी तो इसमें लग रहा है। लेकिन क्या ही बोलूँ, आज कल दिमाग भी कंप्यूटर में बंद हैं , और कंप्यूटर में लोगों का दिमाग बंद है। लोगों के दिमाग का डाटा चुराने वाले अब डाटा सजाने के लिए दिमाग ढूंढ रहे हैं। वैसे अब फिर त्योहारी मौसम आ गया है ! बाजार सज चुके हैं , मिठाइयों की सदा आ गई है , और त्योहारी महफिल में रैलियाँ लग चुकी है। 10000 करोड़ के नुकसान के दावे , और लोकतंत्र की 'वापसी' के वादे के बीच, आम आदमी आटे-दाल और चीनी के दाम को लेकर रो रहा है । लेकिन यह तो बड़े लोगों के लिए छोटा सा नुकसान है। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले त्योहारों की हार्दिक बधाई । आशा है कि आपकी दीवाली हरित और देश दुश्मनों की तशरीफ लाल हो ! ●

मदर इंडिया

राशिफल

10 नवंबर से 9 दिसंबर 2026

motherindiamagazine.com



मेष

(चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

महीने की शुरुआत उत्साह से भरी रहेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें निभाने में आपकी मेहनत की सराहना होगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। दूसरे सप्ताह में परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें। महीने के अंत में रुके हुए काम पूरे होंगे और मन प्रसन्न रहेगा।

वृष

(ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो)

यह महीना आपके लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। व्यापार में नए सौदे लाभ दे सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को खुशी देगी। दूसरे सप्ताह में वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी-सी बात पर विवाद हो सकता है। संपत्ति से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

मिथुन

(का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)

महीने की शुरुआत में कामकाज की भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन उसका फल भी जल्द मिलेगा। संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से अटका काम बन सकता है। धन के मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। तीसरे सप्ताह में छोटी यात्रा के योग बनेंगे। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें।

कर्क

(ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)

परिवार और घर से जुड़े मामलों में यह महीना सुखद रहेगा। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। करियर में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। दूसरे सप्ताह में आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। मन में चल रही उलझनों को अपनों के साथ साझा करें, समाधान जल्दी मिलेगा।

सिंह

(मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)

महीने की शुरुआत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होगी। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व की तारीफ होगी और पदोन्नति की बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि अहंकार से बचें, वरना सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। दूसरे सप्ताह में खर्च बढ़ेंगे, इसलिए बजट बनाकर चलें। संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। महीने के अंत में किसी पुराने निवेश से लाभ के योग हैं।

कन्या

(टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)

यह महीना मेहनत और योजना का है। कामकाज में बारीकी से ध्यान देने की आपकी आदत आपको आगे ले जाएगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी के फैसले सोच-समझकर करें। दूसरे सप्ताह में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मदद मिलेगी। खानपान पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त आराम करें।

तुला

(रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)

महीने की शुरुआत में रुके हुए सरकारी या कानूनी कामों में प्रगति होगी। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और अविवाहितों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है। दूसरे सप्ताह में धन लाभ के योग हैं, लेकिन उधार देने से बचें। कलात्मक और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है।

वृश्चिक

(तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

इस महीने आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी होगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। धन के मामले में जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। दूसरे सप्ताह में परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आएगी। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का यह अच्छा समय है। गुस्से पर काबू रखें।

धनु

(ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे)

महीना भाग्य का साथ लेकर आएगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे और नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। दूसरे सप्ताह में घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। ज्यादा वादे करने से बचें, ताकि बाद में दबाव न बने।

मकर

(भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी)

कार्यक्षेत्र में आपकी लगन रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा तबादला या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। दूसरे सप्ताह में भाई-बहनों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, उसे धैर्य से सुलझाएं। सर्दी के मौसम में सेहत का ध्यान रखें और दिनचर्या नियमित रखें।

कुंभ

(गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा)

महीने की शुरुआत में नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी, जिन्हें अमल में लाने का यह सही समय है। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। दूसरे सप्ताह में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न होगा।

मीन

(दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची)

यह महीना आपके लिए सुकून और संतुलन लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। धन के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन बचत पर भी ध्यान दें। दूसरे सप्ताह में परिवार में किसी शुभ समाचार से माहौल खुशनुमा रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। विद्यार्थियों को शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी।

स्वामित्वाधिकारी, सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक ललित 'सुमन' द्वारा वंदना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9 सराय पीपल थला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 से मुद्रित एवं 'मदर इंडिया' कार्यालय, जे-61ए, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015 से प्रकाशित। मोबाईल नं. 9910886465, 8076685718

R.N.I No. DELHIN-1999/02008 RNI Title Code-DELHIN09962

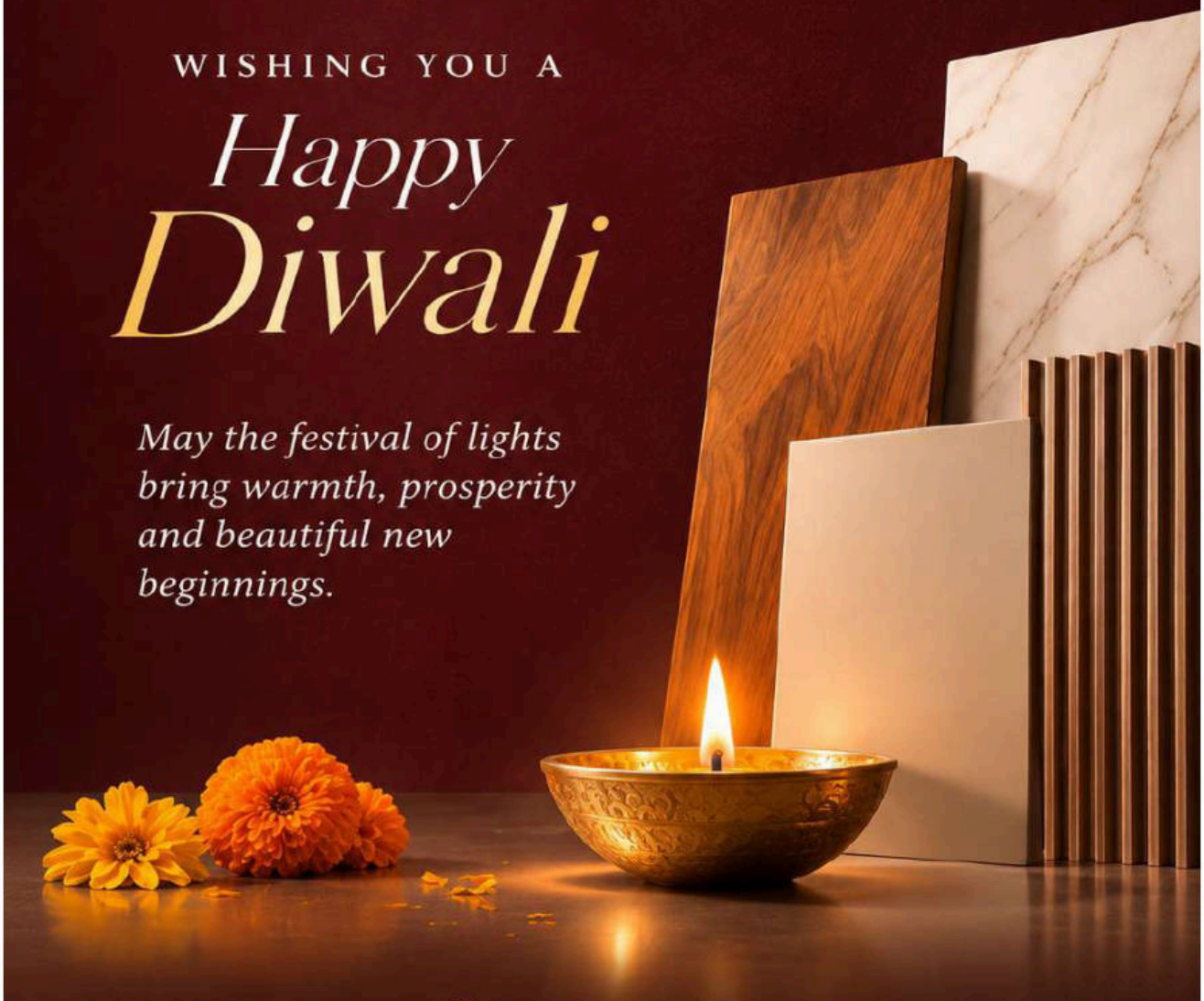
klysta

PLYWOOD & INTERIOR
DECORATIVE PRODUCTS

WISHING YOU A

Happy Diwali

May the festival of lights bring warmth, prosperity and beautiful new beginnings.



Plywood | MDF | Laminates & Acrylic Laminates | Louvers & Wall Panels | Veneers | WPC Boards

RAJKAMAL PLYWOOD INDIA PVT. LTD.

Rank Deep Furniture

Spl.: Wooden Furniture

Happy Diwali

Bring home comfort and
elegance this festive season











Shop No.: A-15, W.H.S. Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi-110015

Rinku - 9811217411 Phone (O): 011-41707411 | E-mail: rankdeepfurniture@gmail.com

Panne Lal Sharma

Mob.: 9818246491

HOME

Happy Diwali

Celebrate Diwali With Beautiful Furniture For Every Home



Bright Home Furniture

Email: brighthomedelhi@gmail.com

Website: www.brighthomefurniture.in

ADDRESS: BASEMENT AND 3RD FLOOR OF TOWER-D, WESTERN SIDE.
P.NO. 97 TO 102 BLOCK-2, W.H.S., BLOCK-A,
TIMBER MARKET, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-15
A-199, 4TH FLOOR, W.H.S., TIMBER MARKET, KIRTI NAGAR,
NEW DELHI-15

FIZZIX

Drinks From Future

ट्रेंड्स को फॉलो मत करो.
उन्हें सेट करो.

ये ड्रिंक नहीं, ये लाइफस्टाइल हैं.

एक प्रीमियम इंस्टेंट फिज़ ड्रिंक,
जो आपकी लाइफस्टाइल और
आपकी जेब – दोनों के लिए परफेक्ट है।

Drop. Fizz. Sip. Repeat.



हम आपके शहर आ रहे हैं!

नॉर्थ इंडिया में शुरू हो रही है एक **रिफ्रेशिंग रेवोल्यूशन।**
अब बेहतरीन स्वाद और स्मार्ट चॉइस, आपके और करीब।

- 80% कम शुगर
- एक ट्यूब में 10 स्वादिष्ट ड्रिंक्स
- सेकेंडों में इंस्टेंट फिज़
- कहीं भी ले जाएं, आसान और हल्का
- स्टाइल के साथ हाइड्रेशन



डिस्ट्रिब्यूटर्स और डीलर्स का स्वागत है!

हमारे सफर का हिस्सा बनें और साथ मिलकर
नॉर्थ इंडिया में बेवरेज इंडस्ट्री का भविष्य बदलें।

- शानदार प्रॉफिट मार्जिन्स
- एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर्स
- एक्सक्लूसिव टेरीटरी राइट्स
- फर्स्ट-मूवर एडवांटेज
- पूरी मार्केटिंग सपोर्ट
- विशसनीय और तेज सप्लाई चेन

आइए मिलकर बनाएं
नॉर्थ इंडिया की अगली बेवरेज रेवोल्यूशन!
Together.

शानदार ऑफर्स का फायदा उठाएं – जल्दी जुड़ें!

ड्रिंक्स के भविष्य
का हिस्सा बनें।

CALL/WHATSAPP
8383023939, 8796556545

अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

नई दिल्ली | नोएडा | उत्तराखंड | औरंगाबाद

corporate@drinkfizzix.com | www.drinkfizzix.com